Machine Translated by Google

चक्रवृद्धि लाभ

न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता सात हालिया एफटीए पर आधारित

है। सोमवार को हस्ताक्षरित भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) अलग-अलग

टी देखने पर कम प्रभावशाली लग सकता है, लेकिन पिछले पांच से छह वर्षों में जो कुछ हुआ है, उसे देखते हुए यह महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था भारत के आकार का सोलहवां हिस्सा है, और भारत के कुल व्यापार का 1% से भी कम हिस्सा है। फिर भी, यह दृष्टिकोण इस तथ्य की अनदेखी करता है कि एफटीए पिछले साढ़े तीन वर्षों में सात अन्य व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करने या बातचीत बंद करने के तुरंत बाद आया है। यह उन बड़े नीतिगत लक्ष्यों को भी नजरअंदाज करता है, जिन्हें भारत ऐसे सौदों के जरिए हासिल करने का प्रयास कर रहा है। COVID-19 महामारी और अमेरिकी शुल्क घर्षण ने भारत को दिखाया है कि उसे आयात और निर्यात पक्षों पर आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने की आवश्यकता है फिर भी, भारत के 16% इम्पोर्ट में से, जो चीन करता है, कोई भी कटौती स्वागत योग्य होगी। ज़रूरी बात यह है कि एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में विविधता लाने की स्ट्रेटेजिक ज़रूरत, खासकर तब जब चंचल डोनाल्ड ट्रंप भारत के सबसे बड़े एक्सपोर्ट मार्केट के इंचार्ज हैं, साफ़ और ज़रूरी है। मॉरीशस, UAE, ऑस्ट्रेलिया, EFTA देशों, UK, EU, ओमान और अब न्यूज़ीलैंड के साथ ट्रेड डील, सभी भारतीय एक्सपोर्टर्स को ऐसे मौके देते हैं जिनका उन्हें फ़ायदा उठाना चाहिए। आखिर में, इस FTA को इसके साइज़ के आधार पर खारिज करना भारत के उन नेगोशिएटर्स के साथ नाइंसाफ़ी होगी जिन्होंने बड़ी जीत हासिल करने के लिए भारत के कम्पेरेटिव फ़ायदे का इस्तेमाल करके अच्छा किया है।

भारत के लिए FTA की पहली खास बात, और जो पहले कभी नहीं हुई, यह है कि न्यूज़ीलैंड एग्रीमेंट के लागू होते ही सभी सामान पर लगने वाले टैक्स तुरंत हटा देगा। दूसरी खास बात यह है कि भारत अपने किसी भी सेंसिटिव सेक्टर में कोई भी छूट देने से बच गया। इन छूटों में सबसे खास है डेयरी, जिसे न्यूज़ीलैंड खास तौर पर शामिल करना चाहता था। तीसरी अच्छी बात यह है कि न्यूज़ीलैंड ने 15 सालों में भारत में $20 बिलियन के इन-इन्वेस्टमेंट को आसान बनाने का वादा किया है। यह EFTA ट्रेड पैक्ट के नियमों जैसा ही है, जिसमें चार EFTA देशों ने 15 सालों में भारत में $100 बिलियन के इनवेस्टमेंट को आसान बनाने का वादा किया था। यह पक्का है कि ये सुविधा देने के वादे हैं, इन्वेस्ट करने के नहीं, लेकिन फिर भी इन्हें डील के टेक्स्ट में शामिल करवाना ज़रूरी है। इसमें मदद करने के लिए, भारत न्यूज़ीलैंड के इन्वेस्टर्स को होने वाली किसी भी दिक्कत को दूर करने के लिए एक खास डेस्क बनाएगा। अगर भारत चीन को पीछे छोड़ना, एक्सपोर्ट बढ़ाना और उसमें विविधता लाना, नौकरियां पैदा करना, कैपिटल अकाउंट को मजबूत करना, और आम तौर पर इनकम बढ़ाना जैसे कई लक्ष्य हासिल करना चाहता है, तो विदेशी इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसा टारगेटेड तरीका ज़रूरी है। घरेलू मैन्युफैक्चरर्स को बड़े लेवल पर काम करने में मदद करने की दूसरी लंबे समय से चली आ रही ज़रूरत एक मुश्किल समस्या बनी हुई है।

तकनीकी समाधानों से दुर्घटनाएं कम हो सकें, उससे पहले सड़कों को अपग्रेड

करने की जरूरत है । भारत कई मायनों में एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा देश है और इस प्रकार एक आम मुर्गी-और-अंडा समस्या की कई

मैं किस्मों का सामना करता है: यह ऐसे समाधान अपनाता है जो केवल बड़े पैमाने पर ही संभव हैं, लेकिन उस पैमाने पर परिचालन के लिए संघर्ष करता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय वाहन-से-वाहन (V2V) संचार प्रौद्योगिकी शुरू करने के लिए तैयार है जो सड़क पर वाहनों को उनके स्थान और गति के बारे में डेटा भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देगा, ताकि सड़क सुरक्षा में सुधार हो सके। यह ऐसे समय में विश्वसनीय लगता है जब भारत में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। अप्रैल में कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में हुई दुर्घटनाओं में 50 से अधिक लोग मारे गए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2025 में दो समान घटनाओं का स्वत: संज्ञान लिया और लेकिन, V2V से मदद मिलने की उम्मीद कम है क्योंकि इसकी हार्डवेयर डिमांड मौजूदा सिस्टम के मुकाबले बहुत कम है, फिर भी यह बहुत ज़रूरी है। V2V, V2X, या गाड़ी से हर चीज़ तक, टेक्नोलॉजी वाली स्कीम का हिस्सा है जिसमें गाड़ियां V2V के अलावा दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर (V2I), जैसे ट्रैक लाइट और टोलिंग, और पैदल चलने वालों (V2P) से भी बातचीत करती हैं। हालांकि, भारत में अभी इसे चालू करने के लिए इंटरऑपरेबिलिटी और बैकएंड सिस्टम की कमी है। असल में, मिनिस्ट्री ने अभी तक यह नहीं बताया है कि भारतीय V2V किस 'भाषा' में ब्रॉडकास्ट करेगा — DSRC या C-V2X — और इसने हैरानी की बात नहीं है कि लोगों की चिंता बढ़ा दी है।

गाड़ी मालिकों को पहले से ही बहुत ज़्यादा कम्प्लायंस कॉस्ट का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें गाड़ी की लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए पेमेंट करना शामिल है, बिना सब्सिडी या अप्रूव्ड डिवाइस की ज़्यादा कॉस्ट को कम करने के लिए कॉम्पिटिटिव वेंडर मार्केट के। V2V नेटवर्क में, हर गाड़ी एक नोड होती है जहाँ ड्राइवर के लिए डेटा प्रोसेस और इंटरप्रेट किया जाता है। हालाँकि, कई कमर्शियल ड्राइवर इंटरफ़ेस वाले एनवायरनमेंट में गाड़ी चलाने के आदी नहीं होते हैं और गाड़ी के अलर्ट को इंटरप्रेट करने के लिए अंडर-ट्रेन्ड होते हैं।

इससे बुरे लोगों द्वारा संचार को बीच में रोककर झूठी चेतावनी भेजने या मजबूत सुरक्षा प्रोटोकॉल की अनुपस्थिति में अनावश्यक ब्रेक लगाने, और नेटवर्क चैनल कंजेशन (5.9 गीगाहर्ट्ज अंतर्राष्ट्रीय मानक है) और पैकेट लॉस की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अधिक बुनियादी तौर पर, देश में उचित सड़क डिजाइन, रूटिंग और गति नियंत्रण का अभाव है, जबकि सड़क का उपयोग दोपहिया वाहनों, पैदल यात्रियों और गैर-मोटर चालित ट्रैक द्वारा प्रमुखता से किया जाता है। यदि कोई शहर 'स्मार्ट' नहीं है, तो वी2वी जैसा 'स्मार्ट सिटी' समाधान सबसे अच्छे रूप में भी मामूली होगा। यह तब और भी उपयोगी होगा जब अधिक उपयोगकर्ता इसे अपनाएंगे, लेकिन वर्तमान में, शुरुआती अपनाने वालों को पूरी लागत का भुगतान करना होगा और लाभ बहुत कम होंगे। यदि प्रौद्योगिकी को भारत की सड़कों की घातकता को कम करने में मदद करनी है,

ईरान पर युद्ध और खाड़ी के टूटे भ्रम

युद्धों को शायद ही कभी

युद्ध के मैदान जहाँ वे फटते हैं।
उनके झटके बाहर की ओर फैलते हैं,
अर्थव्यवस्थाओं को नया आकार देते हैं,
समाज और देश अपने बारे में जो बातें बताते हैं, वे भी एक-दूसरे से जुड़ी होती हैं। ईरान में युद्ध भी कोई अलग नहीं रहा। इसने न सिर्फ़ एक तबाह देश छोड़ा है, बल्कि एक ऐसा इलाका भी छोड़ा है जिसे अपनी खुशहाली की कमज़ोरी और अपनी स्थिरता की अनिश्चितता का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इस लड़ाई से सिर्फ़ एक घायल ईरान ही नहीं, बल्कि एक ऐसा खाड़ी देश भी निकलेगा जिसकी लंबे समय से कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप और माइग्रेंट्स के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह की इमेज बनी हुई थी — और भारत समेत एक बड़ा इलाका खतरे में है।

एक देश तबाह हो गया। सभी रिपोर्ट बताती हैं कि ईरान आज शारीरिक रूप से टूटा हुआ देश है। युद्ध ने कभी फलते-फूलते शहरों को मलबे में बदल दिया है, इंडस्ट्रियल ज़ोन खत्म कर दिए हैं, और ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को पंगु बना दिया है। पावर ग्रिड भरोसे के लायक नहीं रहे, रीनरी खंडहर में पड़ी हैं, और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क टूट गए हैं। तबाही सिर्फ़ सामान तक ही सीमित नहीं है; यह शासन के ढांचे तक फैली हुई है। ईरान के नेतृत्व के खत्म होने से मंत्रालय पंगु हो गए हैं, सुरक्षा बल बिखर गए हैं, और कमांड की चेन अस्त-व्यस्त हो गई है। दशकों में मेहनत से बनाई गई संपत्तियाँ – मिलिट्री स्टॉकपाइल, तेल टर्मिनल, सांस्कृतिक संस्थाएँ – खराब हो गई हैं या नष्ट हो गई हैं।

जो बचता है वह है एक ऐसा देश जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, उसकी खुद पर राज करने और खुद को बचाने की क्षमता बहुत कम हो चुकी है।

इंसानों की मौत भी उतनी ही चौंकाने वाली है: लाखों हिंसा की वजह से बेघर हुए, समुदाय उजड़ गए, और पीढ़ियों को ज़ख्मी किया। युद्ध ने न सिर्फ़ इमारतों और पुलों को तबाह किया है, बल्कि देश को एक साथ रखने वाले सामाजिक ताने-बाने को भी खत्म कर दिया है। संस्थाओं पर भरोसा खत्म हो गया है, और डर, अनिश्चितता और गुस्से की वजह से देश की एकता की भावना खराब हो गई है।

ईरान के अंदर हुई तबाही के आर्थिक नतीजे उसकी सीमाओं से कहीं आगे तक फैले हैं।
क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट गिरने से फ्यूल की कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे ग्लोबल मार्केट में हलचल मच गई है। हर जगह लिक्विड पेट्रोलियम गैस (LPG) और लिक्विड नेचुरल गैस (LNG) की कमी से सप्लाई चेन में दिक्कत आ रही है, जिससे उन इंडस्ट्रीज़ पर असर पड़ रहा है जो लगातार एनर्जी सप्लाई पर निर्भर हैं।

साउथ एशिया और ईस्ट अफ्रीका में फैक्ट्रियां कमी की वजह से बंद हो गई हैं, जिससे सप्लाई चेन में रुकावट आई है और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए लागत बढ़ गई है, जबकि दुबई से लेकर दिल्ली तक के रेस्टोरेंट्स में चूल्हे जलाने के लिए मुश्किल हो रही है। महंगाई का सबसे ज़्यादा असर वर्किंग क्लास पर पड़ रहा है, जो उतार-चढ़ाव से बच नहीं सकते।

खाड़ी को लंबे समय से एक स्थिर ऊर्जा केंद्र के रूप में देखा जाता है। समझौता हुआ है। ग्लोबल मार्केट को लगातार सप्लाई का भरोसा दिलाने की इसकी क्षमता हिल गई है, जिससे ग्लोबल निर्भरता की नाजुकता सामने आ गई है।

शशि थरूर
चौथी बार के सांसद,
लोकसभा (कांग्रेस पार्टी) के लिए
तिरुवनंतपुरम, संसदीय के अध्यक्ष
बाहरी वायु और साहित्य पर स्थायी समिति
अकादमी
29 किताबों के पुरस्कार विजेता लेखक, जिनमें शामिल हैं
'पैक्स इंडिका' (2012) और 'द न्यू वर्ल्ड
डिसऑर्डर' (2020)

युद्ध ने खाड़ी को हिलाकर रख दिया है, जिससे स्थिरता और आर्थिक मजबूती का भ्रम टूट गया है।

हाइड्रोकार्बन एक अस्थिर इलाके में जमा हो गए। युद्ध ने दिखाया है कि जब सुरक्षा की नींव कमज़ोर हो जाती है और स्थिरता का वादा, जो खाड़ी की सबसे बड़ी संपत्ति है, टूट जाता है, तो खुशहाली कितनी जल्दी खत्म हो सकती है।

खाड़ी कमजोर है। दशकों से, खाड़ी ने खुशहाली की इमेज बनाई है: चमचमाती ऊंची इमारतें, हलचल भरे फ्री ज़ोन, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप और माइग्रेंट लेबर के लिए एक मैग्नेट। वह कहानी अब काफी धुंधली हो गई है। युद्ध ने इस इलाके की कमजोरी को सामने ला दिया है, जिससे इसके सुरक्षित पनाहगाह बने रहने की काबिलियत पर भरोसा कम हो गया है। बिज़नेस विस्तार पर फिर से सोच रहे हैं, और कैपिटल आने में हिचकिचा रहे हैं।

भारत की रेमिटेंस इकॉनमी की रीढ़, गल्फ लेबर, अनिश्चितता का सामना कर रही है क्योंकि एम्प्लॉयर बजट कम कर रहे हैं और प्रोजेक्ट्स को छोटा कर रहे हैं, जिससे भारत में माइग्रेंट्स और उनके परिवार रोजी-रोटी को लेकर परेशान हैं। दुनिया के सबसे भरोसेमंद हब, दुबई से ट्रांजिट ट्रैवल अब खतरनाक लगता है, क्योंकि एयरलाइंस रूट बदल रही हैं, पैसेंजर्स को देरी का सामना करना पड़ रहा है, और बिना रुकावट वाली कनेक्टिविटी की जगह चिंता ने ले ली है। गल्फ के सॉवरेन वेल्थ फंड्स से होने वाले इन्वेस्टमेंट पर शक है, उनके पोर्टफोलियो अब भरोसे और टिकाऊपन की निशानी नहीं रहे। ट्रेड रूट भी अस्थिर हैं: भारतीय एक्सपोर्टर जो अफ्रीका और यूरोप के गेटवे के तौर पर गल्फ पोर्ट्स पर निर्भर थे, अब देरी, ज़्यादा इंश्योरेंस प्रीमियम और ग्लोबल कॉमर्स के लिए एक सुरक्षित रास्ते के तौर पर इस इलाके में कम भरोसे का सामना कर रहे हैं। युद्ध ने न केवल लोगों और सामान की आवाजाही को बल्कि कैपिटल के फ्लो को भी अस्थिर कर दिया है, जिससे गल्फ के ग्लोबलाइजेशन के लिए एक सुरक्षित ठिकाने के वादे की नींव ही कमजोर हो गई है — और उस वादे के साथ भारत की गहरी उलझनें सामने आ रही हैं।

यह साइकोलॉजिकल झटका उतना ही बड़ा है जितना कि आर्थिक। इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स को लंबे समय से लगता था कि खाड़ी देश अपने पश्चिम एशियाई पड़ोसियों की उथल-पुथल से बचा हुआ है, एक ऐसी जगह जहाँ मज़बूत देशों और तय पॉलिसियों की सुरक्षा में कैपिटल फल-फूल सकता है। यह विश्वास टूट गया है। युद्ध ने दिखाया है कि खाड़ी देश, अपनी सारी दौलत और महत्वाकांक्षा के बावजूद, क्षेत्रीय संघर्ष के अस्थिर करने वाले असर से बच नहीं सकता।

जब बंदूकें आखिरकार शांत हो जाएंगी, तो ईरान का शासन खड़ा रहेगा, भले ही कमजोर हो जाएगा, लेकिन देश तबाह हो जाएगा: इसकी सीमाएं खाली होंगी और अंदरूनी व्यवस्था कमजोर होगी; इसकी अर्थव्यवस्था पस्त हो जाएगी, तेल से होने वाली कमाई कम हो जाएगी और इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएंगी; इसकी सरकार कमजोर हो जाएगी, इसकी नई लीडरशिप का अभी तक टेस्ट नहीं हुआ होगा, और शायद यह और भी सख्त और दबाने वाली होगी, क्योंकि इसका ध्यान सुधार के बजाय बचने पर होगा।
यह आखिरी संभावना खास तौर पर परेशान करने वाली है। इतिहास बताता है कि संकट में बनी सरकारें अक्सर दबाव के ज़रिए सत्ता में बनी रहती हैं, न कि किसी और चीज़ के ज़रिए।

आम सहमति। ईरान के परेशान नए शासक देश में दमन और विदेश में आक्रामकता का सहारा ले सकते हैं।
वे अलग-अलग तरीके से हमला करने की कोशिश कर सकते हैं — साइबर वॉरफेयर, प्रॉक्सी मिलिशिया, या ग्लोबल डिसरप्शन के ज़रिए — इलाके में डिसरप्शन की अपनी क्षमता के ज़रिए असर डालने के लिए बचे हुए कुछ तरीकों का इस्तेमाल करते हुए। अस्थिरता के बाहर फैलने का खतरा असली है। खाड़ी के देश, जिन्होंने अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए अपनी ज़मीन पर US बेस बनाए थे, अब शायद पाएंगे कि अमेरिकी मौजूदगी सिर्फ़ और हमले और तोड़फोड़ को न्योता देती है।

फिर भी, क्या कोई ज़्यादा उम्मीद वाली बात है? क्या रीकंस्ट्रक्शन, चाहे कितना भी धीमा हो, नए सिरे से काम करने की गुंजाइश बना सकता है? क्या रीजनल एक्टर्स, भले ही अमेरिकी सपोर्ट या इज़राइली दखल न हो, एक टूटे हुए पड़ोसी को फिर से बनाने में एक कॉमन वजह हो सकते हैं ताकि अफ़रा-तफ़री फैलने से रोकी जा सके?

जवाब अभी भी पक्का नहीं है। यह साफ़ है कि युद्ध ने खाड़ी की कहानी फिर से लिख दी है: स्थिरता की एक रोशनी से एक ऐसा इलाका जो कमज़ोरी, उतार-चढ़ाव और लंबे समय तक अशांति के डर से जूझ रहा है।

एक बार जब अमेरिकी अपनी बात मनवा लेंगे, तो उम्मीद है कि इलाके में सहयोग की गुंजाइश होगी। खाड़ी देशों के पास, अपनी कमज़ोरियों के बावजूद, ईरान की तबाही को अपने इलाकों में फैलने से रोकने के लिए रिसोर्स और इंसेंटिव हैं। रिकंस्ट्रक्शन एक शेयर्ड प्रोजेक्ट बन सकता है, भलाई के लिए नहीं बल्कि ज़रूरत के लिए। एक स्थिर ईरान, भले ही कमज़ोर हो, एक अस्त-व्यस्त ईरान से बेहतर है जो अस्थिरता फैला सकता है। चुनौती अविश्वास और दुश्मनी को दूर करने की होगी, और ईरान की तबाही में दबदबे का मौका नहीं बल्कि साझा कमज़ोरी की चेतावनी देखने की होगी।

ईरान में युद्ध ने सिर्फ़ बर्बादी ही नहीं छोड़ी है; इसने गलतफ़हमियों को भी तोड़ दिया है। खाड़ी अब वह सुरक्षित जगह नहीं रही जिसका दावा वह कभी करती थी। ईरान अब कोई मज़बूत क्षेत्रीय ताकत नहीं रहा, बल्कि एक घायल देश है जो ज़िंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। पूरा इलाका एक चौराहे पर खड़ा है: या तो यह अस्थिरता और बदले की कार्रवाई के चक्कर में पड़ सकता है, या यह सहयोग और मज़बूती की एक नई कहानी बनाने के मौके का फ़ायदा उठा सकता है। भारत अरब देशों के साथ अपने अच्छे रिश्तों और ईरान के साथ अपने पुराने रिश्तों का फ़ायदा उठाकर एक अच्छी भूमिका निभा सकता है, ताकि वह इलाके को खराब और निराशा में डूबते देखने के बजाय, उसे फिर से बनाने के लिए एक पुल का काम कर सके।

एक सबक तो पक्का है: कमज़ोर नींव पर बनी खुशहाली टिक नहीं सकती। खाड़ी देशों को अब इस सच्चाई का सामना करना होगा कि उनका भविष्य सिर्फ़ दौलत और उम्मीद पर ही नहीं, बल्कि स्थिरता और सहयोग पर भी निर्भर करता है। अमेरिकियों के आगे बढ़ने के बाद, क्या वे उस चुनौती का सामना कर पाएंगे, यह इस इलाके में हम सभी पर निर्भर करता है, जिनकी दिलचस्पी उस स्थिरता और खुशहाली को बनाए रखने में है जिससे कभी दुनिया जलती थी।

दक्षिण एशियाई शक्ति संतुलन पाकिस्तान की ओर स्थानांतरित हो रहा है

अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के लिए मीडिएटर और जगह के तौर पर
हाल के हमलों में एक तीखी बहस हुई है पाकिस्तान की भूमिका के बाद, भारत में पाकिस्तान के बढ़ते डिप्लोमैटिक कद को लेकर चिंताएं सामने आई हैं। ईरानी और अमेरिकी अधिकारियों – जिसमें अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हैं – ने सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान के लीडरशिप, खासकर फील्ड मार्शल असीम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को सीज़फायर को आगे बढ़ाने और बनाए रखने, और कम्युनिकेशन के चैनल बनाए रखने में उनकी भूमिका के लिए माना है।

हालांकि ईरान युद्ध को लेकर डिप्लोमेसी में पाकिस्तान को अब सेंट्रल माना जा रहा है, लेकिन भारत की प्रतिक्रिया में चुप्पी रही है — जिसे मिस्टर ट्रंप के प्रति सावधानी या स्ट्रेटेजिक कंट्रोल के तौर पर देखा जा रहा है। भारत ने इज़राइल या US की उनके कामों के लिए बुराई नहीं की है, और पाकिस्तान की बढ़ती भूमिका के साथ इस अंतर ने भारत की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी में दोनों देशों के बीच बदलते बैलेंस को लेकर बहस को हवा दी है।

बढ़ी हुई डिप्लोमैटिक विज़िबिलिटी से फ़ायदा पाकिस्तान की डिप्लोमैटिक विज़िबिलिटी न सिर्फ़ उसकी मीडिएशन भूमिका की वजह से बढ़ी है, बल्कि वॉशिंगटन के साथ उसके बढ़ते जुड़ाव और गल्फ़ सिक्योरिटी में उसके बढ़ते असर की वजह से भी बढ़ी है। US के साथ उसके रिश्ते — खासकर मिस्टर के अंडर।

ट्रंप ने पाकिस्तान का कद बढ़ाया है। साथ ही, सऊदी अरब के साथ उसकी डिफेंस पार्टनरशिप, और शायद कतर के साथ भी ऐसी ही सिक्योरिटी पार्टनरशिप ने इस इलाके में उसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत को और मज़बूत किया है।

इस बेहतर डिप्लोमैटिक पोजीशन से इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फायदे हुए हैं।
सऊदी अरब का अरबों डॉलर का वादा पाकिस्तान के बढ़ते असर से होने वाले फाइनेंशियल फायदे को दिखाता है। ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के बाद से, पाकिस्तान ने कई डिप्लोमैटिक जीत भी हासिल की हैं, जिससे भारत की कोशिशों को नाकाम किया गया है कि वह उसे आतंकवाद का देश स्पॉन्सर बताए और डिप्लोमैटिक रूप से अलग-थलग करे। अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट के खिलाफ काउंटरटेररिज्म पार्टनर के तौर पर अमेरिका के साथ पाकिस्तान के बढ़ते जुड़ाव, साथ ही गाजा से जुड़ी बातचीत और ईरान संकट में उसकी भूमिका ने भारत की कोशिशों को कमजोर किया है। कुल मिलाकर, इन डेवलपमेंट से पता चलता है कि पाकिस्तान की हालिया डिप्लोमैटिक तेज़ी ने भारत की स्ट्रैटेजी को कमजोर कर दिया है, जिससे बड़े सवाल खड़े हो गए हैं।

मुक्तेदार खान
के प्रोफेसर
अंतरराष्ट्रीय
संबंधों
इससे संबंधित विश्वविद्यालय
डेलावेयर, एक वरिष्ठ
मध्य पूर्व में नॉन-रेसिडेंट फेलो
पॉलिसी काउंसिल और यूट्यूब चैनल के होस्ट,
'खानवर्सेशंस', ग्लोबल एयर पर

पाकिस्तान की हालिया कूटनीतिक गति

ऐसा लगता है कि इससे भारत की रणनीति कमजोर हुई है, और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पर बड़े सवाल उठ रहे हैं।

दक्षिण एशिया

इस बारे में कि क्या दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बदलने लगा है।

पावर का पिरामिड इंटरनेशनल रिलेशन के जानकारों के मुताबिक, देशों को अक्सर पावर के हायरार्की में उनकी अपनी सीमाओं के बाहर असर डालने और नतीजों को आकार देने की क्षमता के आधार पर समझा जाता है। सबसे ऊपर US और चीन जैसी सुपरपावर हैं — ये ऐसे देश हैं जिनके पास दुनिया भर में पावर दिखाने और खुद इंटरनेशनल ऑर्डर को आकार देने की क्षमता है; उनका असर दुनिया भर में मिलिट्री, इकोनॉमिक और इंस्टीट्यूशनल डोमेन में फैला हुआ है। अगले लेवल में ग्लोबल पावर हैं, जो अकेले ग्लोबल ऑर्डर को आकार देने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन उनके पास कई क्षेत्रों में पावर दिखाने की काफ़ी क्षमता है, जैसा कि रूस ने दिखाया है। उनके नीचे बीच की पावर हैं, जिनकी पूरी ग्लोबल पहुंच नहीं है और जो कई क्षेत्रों पर हावी नहीं हैं, फिर भी पार्टनरशिप और इकोनॉमिक और मिलिट्री क्षमता के ज़रिए अच्छा असर डालती हैं; तुर्की, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया और ब्राज़ील जैसे देशों का अक्सर उदाहरण दिया जाता है। इसके बाद रीजनल पावर हैं, जो किसी खास ज्योग्राफिकल एरिया पर हावी हैं, लेकिन उसके बाहर असर डालने की उनकी क्षमता सीमित है, जैसे खाड़ी में सऊदी अरब। आखिर में, छोटी ताकतें हैं, जिनमें ज़्यादातर देश शामिल हैं जिनका असर ज़्यादातर उनकी अपनी सीमाओं तक ही सीमित रहता है और क्षेत्रीय या वैश्विक नतीजों को आकार देने में उनकी भूमिका सीमित होती है।

लोवी इंस्टीट्यूट हार्ड और सॉफ्ट क्षमताओं को एक ही एनालिटिकल फ्रेमवर्क में मिलाकर पूरी नेशनल पावर को ऑपरेशनल बनाता है। यह लगभग 55% वेटेज मैटेरियल पावर – इकोनॉमिक साइज़, मिलिट्री कैपेबिलिटी और रिसोर्स – को और 45% सॉफ्टर डाइमेंशन जैसे डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक नेटवर्क और इंस्टीट्यूशनल असर को देता है।

ऑपरेशन सिंदूर से पहले, लोवी इंस्टीट्यूट के मेट्रिक का इस्तेमाल करके, मैं भारत को उसकी हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर दोनों क्षमताओं को देखते हुए ग्लोबल पावर के तौर पर ऊपर से दूसरे टियर में रखता, जबकि पाकिस्तान एक रीजनल पावर के तौर पर नीचे से दूसरे टियर में आता। हालांकि, पिछले कुछ महीनों के डेवलपमेंट उलटी दिशाओं में मूवमेंट दिखाते हैं। भारत का

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का परफॉर्मेंस उसके माने गए कद या उसकी बढ़त से जुड़ी उम्मीदों के मुताबिक नहीं देखा गया, जबकि पाकिस्तान को कई लोगों ने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा परफॉर्म करते हुए देखा है।

साथ ही, भारत की लगातार चुप्पी या रोक-टोक – खासकर मिस्टर ट्रंप और बड़े जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट के मामले में – ने उसे दुनिया की बड़ी घटनाओं से अलग-थलग कर दिया है। यह सोच आर्थिक और जियोपॉलिटिकल बदलावों से और मज़बूत हुई है, जिसमें भारत की रैंकिंग चौथी से छठी सबसे बड़ी इकॉनमी पर आना और उन ग्रुप्स की कम होती पहचान शामिल है, जिन्होंने कभी उसे ऊपर उठाया था, जैसे I2U2, BRICS, और क्वाड्रीलेटरल डायलॉग।

इसके उलट, पाकिस्तान ने अपनी फिजिकल काबिलियत में कोई बदलाव किए बिना, अपनी डिप्लोमैटिक ताकत और अहमियत को काफी बढ़ाया है। इसका नतीजा एक साफ बदलाव है: भारत एक ग्लोबल पावर से मिडिल पावर की खासियतों की ओर बढ़ता दिख रहा है, जबकि पाकिस्तान मिडिल-पावर का दर्जा पाने की चाहत के साथ एक ज़्यादा अहम रीजनल पावर के तौर पर उभर रहा है। यह बदलता हुआ डायनामिक — भारत की रिलेटिव हैसियत में नीचे की ओर और पाकिस्तान की ऊपर की ओर — भारत की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के अंदर मौजूदा बहसों की तेज़ी, साथ ही पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक बातचीत के अंदर ज़्यादा भरोसे वाला और पॉजिटिव मूड समझने में मदद कर सकता है।

संदर्भ में

भारतीय पॉलिसी बनाने वालों के लिए मेरा आखिरी ऑब्ज़र्वेशन यह है कि US और इज़राइल के मामले में भारत को जो भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है — चाहे वह सोच से जुड़ी हो या डिफेंस टेक्नोलॉजी पर निर्भरता से — वह जो भी फैसले ले रहा है, उनका असर उसकी ताकत के नरम पहलुओं पर ज़रूर पड़ेगा। हालांकि ये नरम पहलू ग्लोबल लेवल पर किसी देश के असर को बढ़ा या घटा सकते हैं, लेकिन वे हार्ड पावर का विकल्प नहीं हैं: मिलिट्री क्षमता, एक मज़बूत इकॉनमी, डेमोग्राफिक स्केल और लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल क्षमता। इन बुनियादी मामलों में, भारत और पाकिस्तान के बीच कोई खास तुलनात्मक बदलाव नहीं हुआ है।

जहां भारत हार्ड पावर के मामले में मज़बूत बना हुआ है, वहीं पाकिस्तान सॉफ्ट पावर हासिल करने के बावजूद अभी भी एक कमज़ोर इकॉनमी को संभाल रहा है। और यह बात मायने रखती है।

Machine Translated by Google

'डिजिटल विजिलेंटिज्म' समस्या क्यों नहीं है?

टी दिल्ली उच्च न्यायालय हाल ही में कुछ बनाया के बारे में अवलोकन "डिजिटल सतर्कता", और यह कथन कभी-कभी "केवल मुक्त से परे अभिव्यक्ति और उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करना"। संदर्भ यह है मानहानि का मुकदमा दायर किया गया न्यायालय में एक व्यक्ति द्वारा कथित तौर पर एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया एक घरेलू रात में। महिला अपने आचरण को बढ़ाने का प्रयास किया सोशल मीडिया पर अपनी आपबीती पोस्ट करके मीडिया, जिसे द्वारा साझा किया गया था मीडिया हाउस और एक अभिनेत्री, जो जाहिर तौर पर सत्यापित नहीं किया पोस्ट में लगाए गए आरोप। ये अवलोकन और बयानों ने एक बार फिर उजागर किया सोशल मीडिया का बढ़ता उपयोग उत्पीड़न के दावों को बढ़ाना और की भावना के कारण कदाचार सामूहिक लाचारी और लोगों का सिस्टम में विश्वास की कमी शीघ्रतापूर्वक और पर्याप्त रूप से संबोधित करें यौन उत्पीड़न के दावे। चाहे वह सामाजिक भूमिका हो मीडिया ने #MeToo में भूमिका निभाई लाने के प्रयास में आंदोलन यौन पीड़ितों को न्याय उत्पीड़न या वीडियो रिकॉर्डिंग उत्पीड़न के मामले पोस्ट किए गए TikTok, असल बात यह है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है "भीड़ स्रोत" प्रतिशोधात्मक कार्रवाई, जिसमें जोखिम संस्थागत जवाबदेही के कारण सारा विटमर के अनुसार, कोई कार्रवाई नहीं हुई।

प्राची दत्ता

कॉर्पोरेट वकील
न्यूयॉर्क में लाइसेंस प्राप्त
और भारत, सलाह देता है
कंपनियों और फंडों,
और एक के रूप में कार्य करता है
सहायक प्रोफेसर
जिंदल ग्लोबल लॉ
स्कूल और शिव
नादर विश्वविद्यालय

प्रणालीगत उदासीनता दुनिया भर में न्याय व्यवस्था, उनकी लंबी-चौड़ी प्रक्रियाएं, देर से न्याय मिले। उदासीनता और पुलिस का अनुचित दखल अधिकारियों और पीड़ित को दोषी ठहराना, के खिलाफ बोलने की प्रक्रिया यौन उत्पीड़न और भी ज़्यादा है चुनौतीपूर्ण। निवारण प्रक्रिया अक्सर का एक रूप बन जाता है सभी पक्षों के लिए दंड शामिल। प्रोसेस की कमी के कारण, प्रणालियों और संस्थानों में न्याय दिलाने में सोशल मीडिया का अहम रोल है पीड़ितों द्वारा अंतर को पाटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उत्पीड़न और निवारण के बीच तंत्र। इससे आरोपों जैसी समस्याएं

सोशल मीडिया इस्तेमाल किया जा रहा है 'भीड़ स्रोत' दंड देनेवाला कार्रवाई, जिसमें एक्सपोज़र ओईआरएस जवाबदेही इस कारण संस्थागत निष्क्रियता

बिना किसी तंत्र के प्रवर्धित उन्हें सत्यापित करने के लिए, झूठे आरोप के कारण परिचालित सोशल मीडिया द्वारा दी गई गुमनामी मीडिया, जवाबदेही की कमी, और सभी पक्षों की प्रतिष्ठा का नुकसान इसमें शामिल लोग शामिल होते हैं। इससे एक पब्लिक तमाशा, वास्तविकता नहीं इस मुद्दे पर बात करते हुए। हालाँकि, जब प्रक्रियाएँ और सिस्टम लगातार पीड़ितों को फेल कर रहे हैं, इन्हें मजबूत करने की जरूरत प्रक्रियाएँ अत्यंत महत्वपूर्ण हैं महत्व इसलिए ताकि पीड़ितों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना होगा न्याय पाने के लिए निवारण साधन। बैलेंस पक्का करना बहुत ज़रूरी है पीड़ितों की मदद करते हुए की प्रतिष्ठा की रक्षा करना कथित उत्पीड़कों, ताकि कोई ऐसा करे दूसरे को न रौंदें न्याय की तलाश। यह ज़रूरी है प्राकृतिक सिद्धांतों को बनाए रखें न्याय और निष्पक्ष सुनवाई।

'सतर्कता' पर एक और मुद्दा यह है "डिजिटल" की शब्दावली विजिलेंटिज्म" शब्द अपने आप में एक नकारात्मक भावना पैदा करता है अर्थ। लेस जॉनस्टन के अनुसार, "सतर्कता", इसकी परिभाषा के अनुसार, इसमें पूर्वचिंतन शामिल है निजी प्रतिभागी नागरिकों के साथ उनका जुड़ाव यह मुद्दा वॉलंटरी होगा। यह एक सामाजिक आंदोलन भी है, जो उपयोग करता है या उपयोग की धमकी देता है बल और तब उत्पन्न होता है जब स्थापित व्यवस्था खतरे में है के अपराध से संस्थागत मानदंड और उद्देश्य अपराध या अन्य सामाजिक नियंत्रण के लिए आश्वासन देकर उल्लंघन प्रतिभागियों को सुरक्षा और दूसरों को। सोशल मीडिया पोस्ट्स उत्पीड़न सीधे तौर पर नहीं होता सतर्कता के दायरे में क्योंकि कोई स्थापित व्यवस्था नहीं है जो खतरे में है और इसका भी कोई आश्वासन नहीं है पार्टिसिपेंट्स को सिक्योरिटी। असल में, पीड़ित और अपराधी इसके प्राप्तकर्ता हो सकते हैं डॉक्सिंग. सीधे शब्दों में कहें तो, जब कोई प्रक्रियाओं की सामूहिक विफलता, फिर कोई सोशल मीडिया की ओर रुख करता है उत्पीड़न को बढ़ावा देना — यह नहीं हो सकता इसे 'डिजिटल सतर्कता' के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

सोशल मीडिया निवारण ऐसे कई उदाहरण हैं के दौरान अनुचित व्यवहार का हवाई यात्रा। इसका एक उदाहरण है घटना जो घटी नवंबर 2022, जब एक आदमी एक महिला पर पेशाब किया। एयरलाइन कार्रवाई करने में धीमा था शिकायत और यह सिर्फ़ एक बार हुआ यह जानकारी सार्वजनिक की गई कि एयरलाइनों ने इसके खिलाफ कार्रवाई की व्यक्ति। मूल मुद्दा, इसलिए, पर्याप्त होना चाहिए सभी स्तरों पर प्रक्रियाएं ताकि समय पर समाधान किया जा सके। उदाहरण के लिए, अगर एयरलाइनों के पास उचित सख्त नो-वाई के रूप में सिस्टम लिस्ट, शायद किसी को सहारा न लेना पड़े सोशल मीडिया एम्प्लीफिकेशन। के बीच समानता स्थापित करना उपभोक्ता सेवाएँ, जब उपभोक्ता को अप्रिय अनुभव, उन्हें अधिकार है अपनी बात कहने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लें उनकी नाराज़गी. नतीजा यह है दोतरफा — या तो सेवा प्रदाता अपनी प्रतिक्रिया देगा बचाव करें या बुरे के लिए माफ़ी मांगें अनुभव। इससे दूसरों को मदद मिलती है उपभोक्ता सूचित करें इसका लाभ उठाने से पहले विकल्पों का चयन करें सर्विस। इसके अलावा, कंज्यूमर वहाँ सेवाएँ पर्याप्त हैं मौजूद प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ इससे पहले कि कोई व्यक्ति सामाजिक हो जाए मीडिया से नाराज़गी ज़ाहिर करने के लिए कहा। ग्राहक शिकायत टीमें हैं शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए अक्सर प्रतिष्ठा के डर के कारण और फाइनेंशियल नुकसान. हालांकि, न्याय सिस्टम और प्रोसेस जो मदद करते हैं असली, कानूनी न्याय पाना है वे काफ़ी अलग हैं। तत्पर नहीं होते और अक्सर कार्रवाई करने से मना कर देते हैं उत्पीड़न की शिकायतों पर, पीड़ितों के पास कोई विकल्प नहीं बचता दूसरे चैनलों पर ले जाने के लिए अपनी शिकायतों को बढ़ा-चढ़ाकर बताएं। इसलिए, मुद्दा यह नहीं है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा होना लेकिन तथ्य यह है कि घोर विफलता का सामना प्रोसेस, लोगों के पास कुछ नहीं बचता सोशल मीडिया को एक विकल्प के रूप में इस्तेमाल करना ही बेहतर है न्याय पाने का एक तरीका। "डिजिटल सतर्कता", एक सामूहिक प्रक्रियाओं को मजबूत करना और इन प्रोसेस में विश्वास बहुत ज़रूरी है।

तमिलनाडु का विकास रिकॉर्ड

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ का मुख्य ड्राइवर बना हुआ है

क्रियाशीलता राज्य

के.आर. षणमुगम

टी अमिल नाडु, जो है दूसरा सबसे बड़ा राज्य की अर्थव्यवस्था उच्च विकास पथ को बनाए रखा, वास्तविक सकल रिकॉर्ड किया राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में 10.83% की वृद्धि 2025-26 में 11.19% की वृद्धि के बाद 2024-25. इससे राज्य यह राष्ट्रीय औसत 7.4% से काफी ऊपर है और दो अंकों का है लगातार दो सालों में डबल डिजिट ग्रोथ हुई है। यह परफॉर्मेंस राज्य की मजबूत नीति ढांचा, और संरचनात्मक ताकत, इसे एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में स्थान दिलाती है भारत की ग्रोथ के लिए। मीडियम टर्म में, तमिलनाडु की ग्रोथ में तेज़ी काफ़ी अच्छी रही है। इसने एवरेज रियल ग्रोथ दर्ज की है।

2021-22 से 2025 तक 9.07% 25, जबकि 5.21% 2016-17 से 2020-21, और 7.18% कोविड-19 से पहले की अवधि के दौरान। इससे पता चलता है कि महामारी के बाद मज़बूत रिकवरी को सपोर्ट मिलेगा लक्षित पैमाने के उपायों द्वारा और औद्योगिक नीति। नाममात्र जीएसडीपी ₹31.19 से बढ़कर 2024-25 में लाख करोड़ से ₹35.29 2025-26 में लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है, जो 13.16% की वृद्धि दर्ज करेगा, जो कि राज्यों में सबसे अधिक। निरंतर उच्च वृद्धि ने महत्वपूर्ण पैमाने और कल्याण निहितार्थ: यह राजस्व उछाल को बढ़ाता है, पैमाने का विस्तार करता है सामाजिक और बुनियादी ढांचे पर खर्च के लिए जगह, और समर्थन रोजगार और आय सृजन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे समावेशी विकास। सेकेंडरी सेक्टर अभी भी मुख्य ड्राइवर बना हुआ है वृद्धि, 15.02% तक विस्तार 2025-26 में, काफी ऊपर राष्ट्रीय औसत 6.6% है। इसके अंतर्गत निर्माण और विनिर्माण दर्ज किया गया 15.02% की मजबूत वृद्धि दर और 14.22% क्रमशः, कॉम-

राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 7% दोनों सेक्टर के लिए। तमिलनाडु का औद्योगिक आधार जारी है यह इसके विकास मॉडल का आधार है। भारत के कुल उत्पादन में 13.35% का योगदान है। मैन्युफैक्चरिंग GDP. 40,000 से ज़्यादा फैक्ट्रियों में रोज़गार लगभग 25 लाख श्रमिक राज्य राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान पर है फैक्ट्री में रोज़गार। सेवा क्षेत्र, कुल का 53.54% हिस्सा है सकल मूल्य वर्धित (जीवीए), 2025-26 में 8.54% की दर से वृद्धि होगी, 9.1% के राष्ट्रीय औसत से थोड़ा कम। हालांकि, कई सब-सेक्टर में मज़बूती दिखी परिवहन, भंडारण और संचार सहित गति 13.35% और वित्तीय सेवाओं में 11.11% की वृद्धि हुई, जो दर्शाता है व्यापक आधार पर विस्तार। प्राथमिक क्षेत्र में 5.92% की वृद्धि हुई, राष्ट्रीय स्तर से बेहतर प्रदर्शन औसतन 2.7%, जो कि खेती में 8.91% रिकवरी हुई।

विकास के चालक तमिलनाडु की प्रति व्यक्ति आय (NSDP) 2020 में ₹2.096 लाख से लगभग दोगुनी हो गई है- 2025-26 में 21 से ₹4.08 लाख देश में दूसरा सबसे ज़्यादा, कर्नाटक के बाद दूसरे नंबर पर तुलना करें तो, पूरे भारत में औसत उम्र ₹2.196 लाख है। राज्य की ग्रोथ सप्लाई और डिमांड दोनों वजहों से होती है। सप्लाई साइड पर, राज्य को फ़ायदा होता है मजबूत बुनियादी ढांचे से, जिसमें विश्वसनीय बिजली, व्यापक सड़क और बंदरगाह संपर्क, और स्थापित औद्योगिक शामिल हैं कॉरिडोर। हाई ह्यूमन कैपिटल, टेक्निकल एजुकेशन में दिखता है-

कौशल विकास, उत्पादकता का समर्थन करता है सेक्टर। राज्य भी एक है शासन के बाद प्रत्यक्ष निवेश के लिए अग्रणी गंतव्य (एफडीआई), जिसमें प्रवाह बढ़ रहा है 2022-23 में $2,169 मिलियन से 2024-25 में $3,681 मिलियन। मांग पक्ष पर, एक बड़ी उपभोक्ता आधार, बढ़ती आय और तेजी से शहरीकरण मजबूत घरेलू बाजार को बनाए रखते हैं खपत। निवेश की मांग मजबूत बनी हुई है, जो आगे चलकर बढ़ेगी। निजी क्षेत्र की गतिविधि द्वारा विनिर्माण, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, और नवीकरणीय एनर्जी, जिसे अच्छे बिज़नेस माहौल से सपोर्ट मिला है। बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय, और सामाजिक कल्याण आगे मांग को मजबूत करता है। निर्यात प्रदर्शन भी बना रहता है मुख्य ग्रोथ लीवर। के अनुसार नीति आयोग के एक्सपोर्ट तैयारी इंडेक्स में तमिलनाडु को पहला स्थान मिला 64.41 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर, महाराष्ट्र से ठीक पीछे। खास बात यह है कि बढ़ती मांग की वजह से आपूर्ति पक्ष द्वारा मिलान किया गया क्षमता, मदद करने में मदद रिटेल इनेशन पिछले साल के 5.2% से घटकर दिसंबर 2025 में 2.62%। इसके अलावा, तमिलनाडु की एस-कैल पॉलिसी ने एक काउंटर-टेर-साइक्लिकल और डेवलपमेंटल भूमिका निभाई है। जबकि महामारी आवश्यक विस्तारवादी राज्य ने तब से कई उपाय किए हैं स्केल कंसोलिडेशन शुरू किया। स्केल डेसिट में गिरावट आई 2020-21 में जीएसडीपी के 4.91% से 2026-27बीई में 3% तक, जबकि राजस्व घाटा कम हो गया 3.49% से 1.2%. कर्ज-GSDP लगभग 26% रहता है। कुल मिलाकर, राज्य की मजबूत विकास गति, बढ़ता एफडीआई और मजबूत निर्यात प्रदर्शन इसके लिए एक ठोस आधार प्रदान करते हैं $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने का अपना लक्ष्य हासिल करना।

के.आर. षणमुगम पूर्व हैं
मद्रास स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर और GoTN के इकोनॉमिक कंसल्टेंट।

पश्चिम बंगाल में SIR से प्रभावित मतदान

कुल मिलाकर, पूर्वी राज्य में वोटर टर्नआउट में बढ़ोतरी हाल के चुनावी साइकिल में सबसे कम थी।

डेटा बिंदु

देव्यांशी बिहानी साम्बवी
पार्थसारथी पोन वसंत बीए

पश्चिम बंगाल, जहां विधानसभा चुनाव बुधवार को संपन्न हुए। करीब 100 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया 92% तक, जो राज्य में सबसे अधिक है द्वारा जारी प्रोविजनल आंकड़ों के अनुसार चुनावी इतिहास चुनाव आयोग (EC). हालाँकि, जैसा कि हाल ही में तमिलनाडु में देखा गया, रिकॉर्ड मतदान किसी वजह से नहीं हुआ मतदाता भागीदारी में तीव्र वृद्धि, लेकिन कम आधार प्रभाव से विशेष गहन पुनरीक्षण के मतदाता सूची में कमी (SIR) राज्य के वोटर्स का साइज़। SIR एक्सरसाइज़, जो बहुत ही विवादित माहौल में हुई थी पश्चिम बंगाल में लाया गया मतदाताओं में लगभग 11% की कमी 7.66 करोड़ से 6.26 करोड़ तक। तालिका 1 आकार और दिखाती है मतदाताओं और मतदाताओं की वृद्धि 2001 से निकला। अंतिम SIR 2001 की विधानसभा के बाद क्या हुआ चुनावों के परिणामस्वरूप, मतदाताओं की संख्या में 1% की कमी आई 2006 के चुनाव में। नतीजतन, 2006 के चुनावों में मतदाताओं की संख्या में उछाल देखा गया मतदान। लोगों की संख्या वोट देने वालों की संख्या में 7.7% की बढ़ोतरी हुई। इसी तरह, 2021 के चुनाव में मतदाताओं की संख्या 7.34 करोड़ से गिर गई विधानसभा चुनाव में 6.82 करोड़ वोट पड़े ताज़ा पोल के अनुसार, 7% की गिरावट आई है। हालाँकि, लोगों की संख्या वोट देने वालों की संख्या में सिर्फ़ 3.6% की बढ़ोतरी हुई। यह वोटर लिस्ट में सबसे कम बढ़ोतरी है। कम से कम पिछले 10 में भागीदारी विधानसभा चुनाव। इससे यह संकेत मिल सकता है कि कई योग्य मतदाता जो अन्यथा वोट देते, SIR की वजह से ऐसा नहीं कर सके विलोपन। निर्वाचन क्षेत्रवार विश्लेषण दर्शाता है कि 294 निर्वाचन क्षेत्रों में से 242 में वृद्धि देखी गई मतदान करने वाले लोगों की संख्या नवीनतम सर्वेक्षणों की तुलना में 2021 विधानसभा चुनाव. नक्शा 2 यह दर्शाता है कि निर्वाचन क्षेत्रों जिसमें संख्या में वृद्धि हुई थी-

2026 के चुनावों में मतदाताओं की संख्या कितनी थी उत्तरी-पूर्वी और दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्रों में अधिक केंद्रित चान-चाल, डोमकल, सीतलकुची जैसे निर्वाचन क्षेत्रों में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई लगभग 29,000 की रेंज। निर्वाचन क्षेत्रों का एक समूह दक्षिणी डेल्टा के पार और उत्तरी इलाकों के कुछ हिस्सों में भी गिरावट देखी गई। समसेरगंज, मेटियाबुरुज़, और हावड़ा उत्तर में गिरावट देखी गई लगभग 33,500, 24,000 और 2021 की तुलना में क्रमशः 19,000 वोटर। तालिका 3 से पता चलता है कि जिन निर्वाचन क्षेत्रों में एसआईआर के दौरान सबसे अधिक विलोपन हुए, वे भी थे जिन सीटों पर वोटिंग में प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। उदाहरण के लिए, चौरंगी और जोरासांको देखा लगभग 40% मतदाताओं के नाम हटाए गए लेटेस्ट SIR एक्सरसाइज। इन चुनाव क्षेत्रों में वोटिंग हुई लेटेस्ट पोल में लगभग 86%। 2021 की तुलना में कम से कम 33 प्रतिशत अंकों की वृद्धि विधानसभा चुनाव। जिन सीटों पर अनुभव हुआ सबसे कम विलोपन जैसे कि कटुलपुर, भगवानपुर और सबंग में 1000 से ज्यादा वोटिंग हुई ताज़ा पोल में 90%. हालाँकि, यह केवल कम की वृद्धि थी जब 5 प्रतिशत अंकों से अधिक 2021 विधानसभा की तुलना में चुनाव। दूसरे शब्दों में, ये चुनाव क्षेत्रों में पहले से ही बड़ी संख्या में लोग आ रहे थे। मतदाताओं का क्षेत्रवार विश्लेषण मतदान से पता चलता है कि दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र, जिसमें राज्य के 294 निर्वाचन क्षेत्रों में से लगभग 117 शामिल हैं, में वृद्धि देखी गई लगभग सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान करने वाले लोगों की संख्या (तालिका 4). इसके बाद उत्तरी क्षेत्र का नंबर आता है, जहां 54 में से 48 निर्वाचन क्षेत्रों में 2021 की तुलना में वोटरों में बढ़ोतरी देखी गई। ग्रेटर कोलकाता क्षेत्र, जिसमें कई शहरी क्षेत्र शामिल हैं, में उच्च सीटों का अनुपात जहां मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या में भारी कमी आई 2021 की तुलना में।

TABLE 1: West Bengal's electorate and voter participation across Assembly elections

Election year	Total electors (in crore)	Change in electors (in %)	People who voted (in crore)	Change in voters (in %)	Voter Turnout (in %)
2001	4.86	6.7	3.66	-3.1	75.3
2006	4.81	-1.1	3.94	7.7	81.9
2011	5.62	16.9	4.74	20.2	84.3
2016	6.59	17.2	5.47	15.3	83.0
2021	7.34	11.3	6.04	10.4	82.3
2026	6.82	-7	6.26	3.64	91.8

TABLE 3: Voter turnout in constituencies with high deletions during SIR

Assembly Constituency (AC)	Deletions (in %)	Voter turnout in 2021(in %)	Voter turnout in 2026 (in %)	Difference (in %)
Chowrangee	40	53.55	86.5	33
Jorasanko	38	49.99	86.5	36.5
Samserganj	36	80.05	96.0	16.0
HowrahUttar	33	68.51	88.1	19.6
KolkataPort	30	64.61	89.4	24.8
Katulpur	1	90.82	93.3	2.5
Bhagabanpur	2	87.59	92.2	4.6
Sabang	2	89.21	92.6	3.4
Patashpur	2	88.33	92.2	3.9
Mahishadal	2	89.44	89.3	-0.2

TABLE 4: Regional breakdown of constituencies based on whether they saw an increase or decrease in the number of voters between 2021 and 2026

Region	Total number of constituencies	ACs where more people voted in 2026	ACs where fewer people voted in 2026
Greater Kolkata	42	28	14
North	54	48	6
South east	81	55	26
South West	117	111	6

MAP 2 : The constituency-level change in the number of people who voted between 2021 and 2026

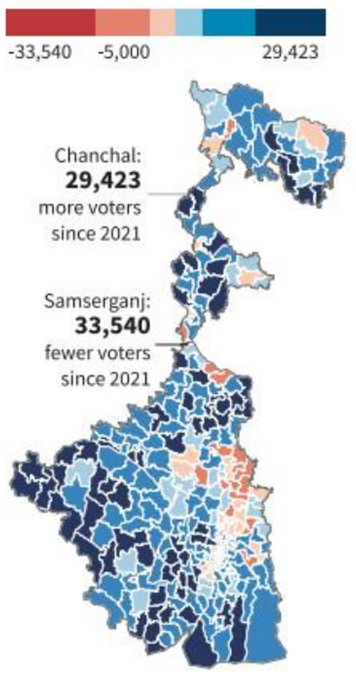

The constituencies that saw an increase in the number of people who voted in 2026, compared to 2021, were concentated more in the western and south-western regions. Constituencies such as Chanchal, Domkal, and Sitalkuchi registered the highest increases

Machine Translated by Google

मूलपाठ& प्रसंग

0

संख्याओं में समाचार

एक US डॉलर के मुकाबले ईरान की नेशनल करेंसी रियाल की वैल्यू

1.8 मिलियन. ईरान का राष्ट्रीय रियाल बुधवार को करेंसी 1.8 मिलियन डॉलर के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई, जो US और इज़राइल के साथ सीज़फ़ायर के कारण $1 हो गई। 28 फरवरी को शुरू हुए युद्ध के दौरान रियाल हफ़्तों तक स्थिर रहा, कुछ हद तक इसलिए क्योंकि देश में बहुत कम ट्रेडिंग या इंपोर्ट हो रहा था। PTI

पंजाब में बॉर्डर पर 585 जगहों पर कैमरे लगाए गए

2,290पंजाब पुलिस है एक ऑफिशियल बयान में कहा गया है कि "डिफेंस की दूसरी लाइन" को मजबूत किया जा रहा है, जो एक गहरा, टेक्नोलॉजी से चलने वाला सिक्योरिटी ग्रिड है जिसे क्रॉस-बॉर्डर लिंकेज के साथ काम करने वाले ऑर्गनाइज्ड क्राइम नेटवर्क की लाइफलाइन को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। PTI

गिरफ्तार किए गए व्यक्ति पश्चिम के बाद से ईरान एशिया युद्ध शुरू हुआ

4,000ईरान के पास निष्पादित किया गया कम से कम 21 UN ने कहा कि युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक 4,000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। फरवरी के आखिर में US-इज़राइली हमलों से युद्ध शुरू होने के बाद से, कम से कम नौ लोगों को मौत की सज़ा दी गई है। PTI

ईरान युद्ध में अब तक अमेरिका को कितना खर्च हुआ है, इसका अंदाज़ा

एक वरिष्ठ नागरिक ने कहा, "इसकी लागत 25 बिलियन डॉलर है।" 25 बिलियन डॉलर में। ईरान में US का युद्ध पेंटागन के अधिकारी ने कहा, 227 लड़ाई के लिए मिलिट्री के प्राइस टैग का पहला ऑफिशियल अंदाज़ा दिया गया। जूल्स हर्स्ट, जो कंट्रोलर का काम कर रहे हैं, ने सांसदों को बताया कि उस पैसे का ज़्यादातर हिस्सा हथियारों के लिए था। रॉयटर्स

बच्चों की मौत बांग्लादेश में खसरे के प्रकोप के कारण

बांग्लादेश ने रिकॉर्ड किया है सरकारी डेटा के मुताबिक, मार्च से अब तक 227 बच्चों की मौत हो चुकी है। यह दशकों में खसरे के सबसे बुरे प्रकोप में से एक है, और संदिग्ध मामलों की संख्या लगभग 35,000 तक पहुंच गई है। PTI

द हिंदू डेटा टीम द्वारा संकलित

हमारे पर का पालन करें facebook.com/thehindu X.com/the_hindu instagram.com/the_hindu

बढ़ता कवरेज, बढ़ता संकट

बढ़ते इंश्योरेंस कवरेज से हॉस्पिटलाइज़ेशन नहीं बढ़ा है या जेब से होने वाला खर्च कम नहीं हुआ है, क्योंकि ज़्यादा लोग ज़्यादा खर्च वाली प्राइवेट सेक्टर की केयर की तरफ जा रहे हैं; सरकार से मिलने वाली हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम परिवारों को पैसे की तंगी से बचाने में नाकाम हो रही हैं, जबकि ज़्यादातर बेहतर लोगों को फायदा हो रहा है।

आर्थिक नोट्स

इंद्रनील
मोंटू बोस

टी 80वीं एनएसएस का नवीनतम डेटा "हाउसहोल्ड सोशल कंजम्पशन: हेल्थ" पर हुए इस सर्वे से कई चिंताजनक नतीजे सामने आए हैं जिन पर और ज़्यादा चर्चा की ज़रूरत है। जनवरी और दिसंबर 2025 के बीच किए गए इस सर्वे से पता चलता है कि 2017-18 (75वां राउंड) की तुलना में इंश्योरेंस कवरेज में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इससे हॉस्पिटल केयर के इस्तेमाल में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। अब ज़्यादातर लोग प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं।

इस बीच, 2017-18 और 2025 के बीच हॉस्पिटलाइज़ेशन पर आउट-ऑफ़-पॉकेट (OOP) खर्च तेज़ी से बढ़ा है, खासकर प्राइवेट सेक्टर में।

बिना देखभाल के कवरेज अभी, 47.4% ग्रामीण परिवार और 44.3% शहरी परिवार किसी न किसी तरह के हेल्थ इंश्योरेंस से कवर हैं। यह मुख्य रूप से 2017-18 और 2025 के बीच प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) और स्वास्थ्य साथी (पश्चिम बंगाल में) जैसी सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस (GFHI) स्कीम के कवरेज में ढाई गुना से ज़्यादा बढ़ोतरी से हासिल हुआ है।

NSS की GFHI की परिभाषा में एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस स्कीम (ESIS), सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS), और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए स्कीम वगैरह भी शामिल हैं।

हालांकि, सोशल रिकॉर्ड के अनुसार, ESIS या CGHS के बढ़े हुए कवरेज का कवरेज में इस बड़ी बढ़ोतरी में बहुत कम योगदान होगा।

2017-18 के दौर में, हॉस्पिटलाइज़ेशन रेट में काफ़ी कमी आई थी। इंश्योरेंस कवरेज में बढ़ोतरी के बावजूद, हॉस्पिटलाइज़ेशन रेट 2014 के लेवल से नीचे है, हालांकि ग्रामीण इलाकों में 2017-18 के रेट के मुकाबले इसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। शहरी इलाकों में, रेट में और गिरावट आई है (Figure 1)।

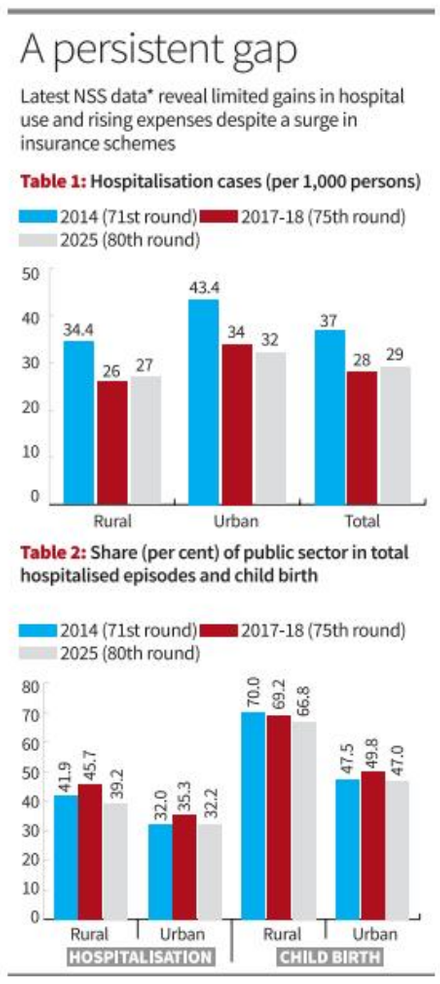

प्राइवेट केयर की तरफ झुकाव 2017-18 और 2025 के बीच, हॉस्पिटल में भर्ती होने और बच्चे के जन्म के लिए सरकारी जगहों के इस्तेमाल में काफी कमी आई है। ज़्यादा लोग प्राइवेट केयर चुन रहे हैं। 2014 और 2017-18 के बीच सरकारी सेवाओं के इस्तेमाल में बढ़ोतरी हुई।

नॉन-हॉस्पिटलाइज़ेशन केयर के लिए, पब्लिक सेक्टर का इस्तेमाल ग्रामीण इलाकों में थोड़ा बढ़ा है, लेकिन शहरी इलाकों में कम हुआ है (Figure 2).

इंश्योरेंस कवरेज तक बढ़ती पहुंच लोगों को फाइनेंशियल मुश्किलों से बचाने में नाकाम रही है। 2014-15 के बीच ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में हॉस्पिटलाइज़ेशन पर OOP खर्च दोगुने से ज़्यादा हो गया है।

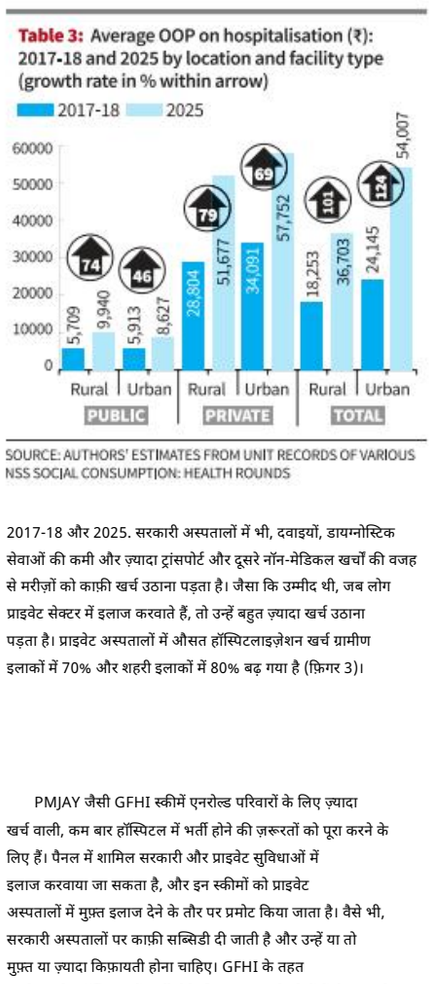

SOURCE: AUTHORS' ESTIMATES FROM UNIT RECORDS OF VARIOUS NSS SOCIAL CONSUMPTION: HEALTH ROUNDS

2017-18 और 2025. सरकारी अस्पतालों में भी, दवाइयों, डायग्नोस्टिक सेवाओं की कमी और ज़्यादा ट्रांसपोर्ट और दूसरे नॉन-मेडिकल खर्चों की वजह से मरीज़ों को काफ़ी खर्च उठाना पड़ता है। जैसा कि उम्मीद थी, जब लोग प्राइवेट सेक्टर में इलाज करवाते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा खर्च उठाना पड़ता है। प्राइवेट अस्पतालों में औसत हॉस्पिटलाइज़ेशन खर्च ग्रामीण इलाकों में 70% और शहरी इलाकों में 80% बढ़ गया है (फ़िगर 3)।

PMJAY जैसी GFHI स्कीमें एनरोल्ड परिवारों के लिए ज़्यादा खर्च वाली, कम बार हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हैं। पैनल में शामिल सरकारी और प्राइवेट सुविधाओं में इलाज करवाया जा सकता है, और इन स्कीमों को प्राइवेट अस्पतालों में मुफ़्त इलाज देने के तौर पर प्रमोट किया जाता है। वैसे भी, सरकारी अस्पतालों पर काफ़ी सब्सिडी दी जाती है और उन्हें या तो मुफ़्त या ज़्यादा किफ़ायती होना चाहिए। GFHI के तहत एनरोल्ड और हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरत वाले लोगों में से 57% ने प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाया। इन स्कीमों के तहत वादे के मुताबिक बहुत कम लोगों को मुफ़्त इलाज मिला। औसत OOP खर्च (बच्चे के जन्म को छोड़कर) ग्रामीण इलाकों में ₹31,250 और शहरी इलाकों में ₹34,259 है।

हालांकि GFHI सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े तबकों को टारगेट करते हैं, लेकिन कई राज्यों ने उन लोगों को भी कवरेज दिया है जो गरीब नहीं हैं। हालांकि, जब बात गरीब इनकम ग्रुप की आती है, तो कवरेज तुलनात्मक रूप से ज़्यादा है।

इन स्कीम के तहत सर्विसेज़ का इस्तेमाल, उन लोगों के मुकाबले बेहतर है जिन्हें ज़्यादा फ़ायदा होता है। डेटा से पता चलता है कि शहरी इलाकों में इन स्कीम के तहत हॉस्पिटलाइज़ेशन सर्विसेज़ का इस्तेमाल करने वालों में से सिर्फ़ 13% सबसे गरीब तबके के हैं। जो परिवार गरीब नहीं हैं, उन्हें शामिल करने से भी इस्तेमाल बढ़ा है और राज्यों के बजट पर ज़्यादा दबाव पड़ा है। हरियाणा और पश्चिम बंगाल में, उनके राज्य के हेल्थ बजट का लगभग 15% GFHI पर खर्च होता है। इस बढ़े हुए स्केल पर दबाव की वजह से प्राइवेट प्रोवाइडर्स को रीइंबर्समेंट में भी देरी हो रही है।

असल में, GFHI प्राइवेट सेक्टर की देखभाल के लिए टैक्स के पैसे का इस्तेमाल सब्सिडी देने के लिए करते हैं। इससे प्राइवेट सेक्टर को उन मार्केट तक पहुंचने में मदद मिलती है जो अब तक कम खरीदने की ताकत के कारण उसकी पहुंच से बाहर थे। भारत में, प्राइवेट सेक्टर ज़्यादातर मुनाफ़े को ज़्यादा से ज़्यादा करने के सिद्धांतों पर काम करता है, जिसमें सामाजिक एकता के लिए सीमित मोटिवेशन होता है और यह असल में अनरेगुलेटेड है।

क्योंकि GFHI रीइंबर्समेंट रेट मार्केट रेट से कम हैं, भले ही रेट CGHS से ज़्यादा फायदेमंद हों, फिर भी मरीज़ों से अक्सर एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है।

इस प्रकार, पहले सात का अनुभव PMJAY और GFHI के सालों के काम से पता चलता है कि ये स्कीमें 'अमीरों की', 'प्रॉफिट के लिए', और 'गरीबों के लिए' हैं!

क्या यह एक अच्छा नतीजा है? शायद अब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (UHC) के इंश्योरेंस वाले मॉडल पर फिर से सोचने और पब्लिक हेल्थकेयर सिस्टम को मज़बूत करने पर फिर से ध्यान देने का समय आ गया है ताकि सबको, पूरी देखभाल मिल सके। इस मामले में, आयुष्मान आरोग्य मंदिर (AAM) — PMJAY का वैसा ही जिसे ज़्यादा नज़रअंदाज़ किया गया है, जिसका मकसद नॉन-कम्युनिकेबल बीमारियों के लिए सर्विस सहित पूरी प्राइमरी देखभाल देना है — उम्मीद की एक किरण दिखाता है। हालांकि, नेशनल हेल्थ मिशन की तरह ही, इसमें भी बहुत कम फंड है।

(इंद्रनील ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ़ गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी में प्रोफेसर हैं। मोंटू बोस TISS, मुंबई के स्कूल ऑफ़ हेल्थ सिस्टम्स स्टडीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। CMIE डेटा इनपुट्स ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के रिसर्च एसोसिएट आकाश CO से लिए गए हैं।)

सार

इंश्योरेंस कवरेज बढ़ने से हॉस्पिटल केयर के इस्तेमाल में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है, और ज़्यादा लोग प्राइवेट हॉस्पिटल जा रहे हैं।

क्षेत्र।

हॉस्पिटल में भर्ती होने पर जेब से होने वाले खर्च में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, और इंश्योरेंस लोगों को पैसे की तंगी से बचाने में नाकाम रहा है।

क्रीमी लेयर की बहस कोर्ट में वापस क्यों आ गई है?

क्या अभी जो ज़ोर दिया जा रहा है, वह फ़ैसले को गलत तरीके से समझने पर आधारित है? क्या इनकम को प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है?

पत्र और आत्मा

प्रणव धवन
विग्नेश कार्तिक केआर

एफ सुप्रीम कोर्ट में नई याचिकाएं SC/ST आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर सिद्धांत को बढ़ाने की मांग कर रही हैं, जो 2024 के दविंदर सिंह फैसले को गलत तरीके से पढ़ने पर आधारित है। इस कदम से दशकों पुरानी बहस फिर से शुरू हो गई है कि क्या इनकम जाति के आधार पर नुकसान का एक प्रॉक्सी हो सकती है, और क्या सामाजिक न्याय को आर्थिक टेस्ट के अंदर फंसाया जा सकता है।

नए सिरे से प्रयास

10 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने वकील की अगुवाई वाली एक जनहित याचिका पर केंद्र और सभी राज्यों को नोटिस जारी किया।

अश्विनी कुमार उपाध्याय ने SC/ST से "क्रीमी लेयर" को बाहर करने की मांग की फरवरी में एक अलग याचिका में इन कोटा के अंदर इनकम के आधार पर प्राथमिकता देने का सिस्टम बनाने की मांग की गई थी। दोनों याचिकाओं में एक ही सोर्स से संवैधानिक मंज़ूरी का दावा किया गया है: पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2024) में सात जजों की बेंच का फ़ैसला।

उस फैसले ने राज्यों को अनुसूचित जाति के समुदायों को सब-क्लासिफ़ाई करने की इजाज़त दी, ताकि उनमें सबसे ज़्यादा हाशिए पर पड़े लोगों को रिज़र्वेशन का फ़ायदा मिल सके। सात में से चार जजों ने यह टिप्पणी की कि क्रीमी लेयर का लॉजिक SC/ST ग्रुप्स पर भी लागू हो सकता है।

अस्पष्टता में पैदा हुआ एक सिद्धांत क्रीमी लेयर सिद्धांत इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) के फैसले के माध्यम से भारतीय संवैधानिक कानून में प्रवेश किया , जहां सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को बरकरार रखा, लेकिन कहा कि अधिक उन्नत वर्ग, "क्रीमी लेयर" को लाभों से बाहर रखा जाना चाहिए।

1993 का ओसीई ज्ञापन

इसके बाद क्रीमी लेयर के बहिष्कार की पहचान मुख्य रूप से आय के बजाय स्थिति के आधार पर की गई। सरकार में क्लास I या क्लास II का पद रखना प्रॉक्सी था, यह पहचान कि इंस्टीट्यूशनल पावर पीढ़ियों के साथ बढ़ती है।

इस सिस्टम को धीरे-धीरे कमज़ोर किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ़ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के 2004 के एक क्लैरिकाटरी लेटर में PSU की सैलरी को एक स्टैंडअलोन डिसक्वालिफ़ाइंग क्राइटेरिया माना जाने लगा। 11 मार्च को, सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ़ इंडिया बनाम रोहित नाथन मामले में उस लेटर को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि सिर्फ़ माता-पिता की सैलरी से क्रीमी लेयर का स्टेटस तय नहीं किया जा सकता।

1993 के OM के स्टेटस-बेस्ड लॉजिक को फिर से लागू कर दिया गया, लेकिन सिद्धांत का गहरा आधार, कि आर्थिक उपलब्धि सामाजिक नुकसान को खत्म करने का सही माप है, बरकरार रहा और उसकी जांच नहीं की गई।

अम्बेडकर की आपत्ति

1932 में लोथियन को लिखे अपने नोट में समिति में, बीआर अंबेडकर ने चेतावनी दी कि अमीर या शिक्षित व्यक्तियों को अछूतों की श्रेणी से बाहर रखना "पूरी तरह से गलत दृष्टिकोण है।"

1936 के महार सम्मेलन में, अंबेडकर ने इसे साफ़-साफ़ कहा: पढ़े-लिखे, अमीर महार आज भी दुकान नहीं खोल सकते, क्योंकि उनकी जाति पता चलने पर ग्राहक चले जाते हैं; वे आज भी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी पहचान ही उन्हें अयोग्य ठहराएगी। आर्थिक तरक्की और सामाजिक आज़ादी अलग-अलग रास्तों पर चलती हैं, और क्रीमी लेयर का सिद्धांत इन दोनों को खत्म कर देता है।

जयश्री पाटिल बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया (2021) में दिए गए डेटा से पता चला कि ग्रुप D के सरकारी कर्मचारी भी इनकम टेस्टिंग की वजह से पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अयोग्य हो गए थे। कोर्ट ने कहा कि साल में ₹6 लाख कमाने वाले परिवार की तुलना ₹24 लाख कमाने वाले परिवार से नहीं की जा सकती, सिर्फ़ इसलिए कि दोनों की कमाई एक ही लिमिट से ज़्यादा है।

निशीथ प्रकाश की पब्लिश हुई स्टैटिस्टिकल रिसर्च से पता चला कि कोटा के फ़ायदों पर अमीर लोगों का कब्ज़ा एक झूठ था। आम सोच के उलट, कोटा पॉलिसी का अच्छा असर 'गांव के इलाकों में कम पढ़े-लिखे SC सदस्यों' पर ही ज़्यादा है।

इस सिद्धांत की सीधी-सादी बात एक ऐसा जाल बनाती है जिसे क्रीमी लेयर का जाल कहा जा सकता है: पैमाना इतना कम रखा गया है कि मुश्किल से टिके लोगों को बाहर रखा जा सके, फिर भी आरक्षण से जुड़े सामाजिक बोझ सैलरी ब्रैकेट की परवाह किए बिना बने रहते हैं।

एससी/एसटी भेद

क्रीमी लेयर को बाहर रखने का मामला था SC/ST समुदायों के लिए OBC की तुलना में हमेशा कमज़ोर रहा है। सब-क्लासिफिकेशन, जिसे दविंदर सिंह ने असल में मंज़ूरी दी थी, पूरी तरह से एक अलग तरीका है। यह पूछता है कि SC लिस्ट में किन सब-कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन सबसे कम है और उन्हें प्राथमिकता देता है।

SC/ST पर क्रीमी लेयर का लॉजिक लागू करने का मतलब होगा कि माता-पिता की इनकम के आधार पर लोगों को रिज़र्वेशन की एलिजिबिलिटी से हटा दिया जाएगा, ठीक यही बात अंबेडकर ने कही थी कि यह कॉन्स्टिट्यूशनली और सोशियोलॉजिकली सही नहीं है। जस्टिस बीआर गवई, जिन्होंने दविंदर सिंह केस में बड़े प्रिंसिपल को सपोर्ट किया था, ने खुद माना कि SC/ST के लिए क्राइटेरिया OBCs के क्राइटेरिया जैसे नहीं हो सकते।

पार्लियामेंट के लिए समय रोहित नाथन

जजमेंट ने कानूनी बदलाव के लिए एक छोटा लेकिन असली मौका दिया है, जो सामाजिक पिछड़ेपन को उस दबेपन से मापता है जिसका वे सामना करते रहते हैं। पार्लियामेंट के पास यह साफ़ करने का संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक ज़िम्मेदारी दोनों है कि सब-क्लासिफिकेशन और क्रीमी लेयर को बाहर करना अलग-अलग तरीके हैं, और क्रीमी लेयर का उन समुदायों पर कोई असर नहीं होता जिन्हें प्रेसिडेंशियल लिस्ट में शामिल करने की शर्त कभी गरीबी नहीं थी।

(प्रणव धवन येल लॉ स्कूल में LLM कैंडिडेट हैं। विग्नेश कार्तिक KR रॉयल नीदरलैंड्स इंस्टीट्यूट ऑफ साउथईस्ट एशियन एंड कैरेबियन स्टडीज, लेडेन में पोस्टडॉक्टरल रिसर्च एसोसिएट हैं)

सेमी वाईके

एम एनडी-एनडीई

Machine Translated by Google

अमूर्त

एक छोटा वीडियो साइंस रिपोर्टिंग में मदद करता है, लेकिन भारत के न्यूज़रूम की असलियत नहीं बताता

एक छोटा सा दखल हेडलाइन की सटीकता को बेहतर बनाता है, लेकिन वैज्ञानिक दावों के क्रिटिकल असेसमेंट को नहीं; हालांकि, भारत के कई भाषाओं वाले, बिखरे हुए न्यूज़रूम, स्ट्रक्चरल दबाव, कम पढ़ाई-लिखाई और भाषा की रुकावटों का मतलब है कि ऐसे समाधानों को बाहर से लाने के बजाय अंदर से ही अपनाना होगा।

वासुदेवन मुकुंठ

लारा मैरी बर्जर, अन्ना केरखोफ, और
निकोला नोस्के, 'न्यूज़रूम में साइंस लिटरेसी में सुधार: एक्सपेरिमेंटल सबूत',

पीएनएएस नेक्सस

एस साइंस जर्नलिज़्म एक बहुत ही दिलचस्प काम है। इसमें अच्छा होने के लिए बस एक 'अच्छा' राइटर होना ज़रूरी है (जैसा कि वे कहते हैं)

मान लीजिए), एक अच्छा पत्रकार, और एक अच्छे पत्रकार की समझ के साथ साइंस और साइंस कम्युनिकेशन को समझना। फिर भी, कुछ शॉर्टकट भी मौजूद हैं, हालांकि वे कुछ बहुत खास इस्तेमाल के लिए हैं, जैसे कि अनुभवी पत्रकारों के लिए टारगेटेड ट्रेनिंग।

21 अप्रैल को, कोलोन यूनिवर्सिटी और ifo इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक रिसर्च के रिसर्चर्स ने PNAS नेक्सस में 'न्यूज़रूम में साइंस लिटरेसी को बेहतर बनाना: एक्सपेरिमेंटल सबूत' टाइटल से एक स्टडी पब्लिश की। स्टडी पेपर में, उन्होंने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया जिसमें उन्होंने जर्मनी में कुछ सौ प्रोफेशनल जर्नलिस्ट्स के बीच एक खास इंटरवेंशन को टेस्ट किया।

खास तौर पर, रिसर्चर्स ने जर्मन जर्नलिस्टिक एसोसिएशन की मेलिंग लिस्ट के ज़रिए 260 जर्नलिस्ट्स को चुना और उन्हें लगभग बराबर टेस्ट और कंट्रोल ग्रुप्स में बांटा। फिर जर्नलिस्ट्स को सात मिनट का एक वीडियो दिखाया गया जो छह "चेकपॉइंट्स" से गुज़रा, जिसके आधार पर जर्नलिस्ट्स से कहा गया कि वे साइंटिफिक स्टडीज़ का क्रिटिकली असेसमेंट कर सकते हैं।

ये फंडिंग सोर्स, सैंपल साइज़, एवरेज, फिगर्स, कोरिलेशन बनाम कॉज़ेशन जैसे स्टैटिस्टिकल मेट्रिक्स और विज़ुअल्स थे। 'टेस्ट' ग्रुप के जर्नलिस्ट्स को कम से कम तीन मिनट तक वीडियो देखना था। टेस्ट ग्रुप के लोग तब तक वीडियो नहीं देख सकते थे जब तक वे दोनों ग्रुप्स को दिए गए टास्क पूरे नहीं कर लेते।

एक्सपेरिमेंटल इनसाइट ये काम दो तरह के थे:
हर जर्नलिस्ट को दो रिसर्च स्टडी मिलीं, (i) हर एक के लिए उन्हें एक हेडलाइन लिखनी थी, और (ii) हर स्टडी पर आधारित न्यूज़ आर्टिकल में गलतियों की जांच करनी थी।

रिसर्चर्स को तीन बातें पता चलीं।
सबसे पहले, 'टेस्ट' ग्रुप के पत्रकारों के सही हेडलाइन लिखने की संभावना 28 परसेंट पॉइंट ज़्यादा थी और आंकड़ों में गलत जानकारी को सही ढंग से पहचानने की संभावना 20 परसेंट पॉइंट ज़्यादा थी - दोनों ही कंट्रोल ग्रुप के पत्रकारों के मुकाबले।

दूसरा, जबकि 'टेस्ट' ग्रुप के पत्रकार ज़्यादा शक करने वाले थे, वे और कंट्रोल ग्रुप के पत्रकार, दोनों ही यह बताने में चांस (50%) से बेहतर नहीं थे कि किसी आर्टिकल में गलतियाँ हैं या नहीं।

तीसरा, 'टेस्ट' ग्रुप के पत्रकारों ने कंट्रोल ग्रुप के पत्रकारों की तुलना में ज़्यादा पॉज़िटिव हेडलाइन लिखीं जो कम इमोशनल भी थीं। हालांकि, उन्होंने क्लिकबेट या डेंसिटी के मामले में बहुत अलग हेडलाइन नहीं लिखीं।

दूसरे शब्दों में, एक छोटा सा दखल पत्रकारों की नई रिसर्च पर समझदारी से रिपोर्ट करने की अपनी काबिलियत में काफ़ी सुधार कर सकता है, लेकिन दूसरों के काम के मुकाबले एक अच्छा जासूस बनने की उनकी काबिलियत में ज़्यादा सुधार नहीं करता।

रिसर्चर्स ने अपने पेपर में लिखा: "कुल मिलाकर, हमारे नतीजे जर्नलिस्टिक साइंस रिपोर्टिंग में सिस्टमिक चुनौतियों को दिखाते हैं। ट्रेंड प्रोफेशनल्स को भी सही हेडलाइन लिखने और साइंटिफिक दावों का गहराई से आकलन करने में मुश्किल हुई, जिससे साइंस की गलत व्याख्या के आर्थिक और सामाजिक जोखिमों पर ज़ोर दिया गया। हालांकि,

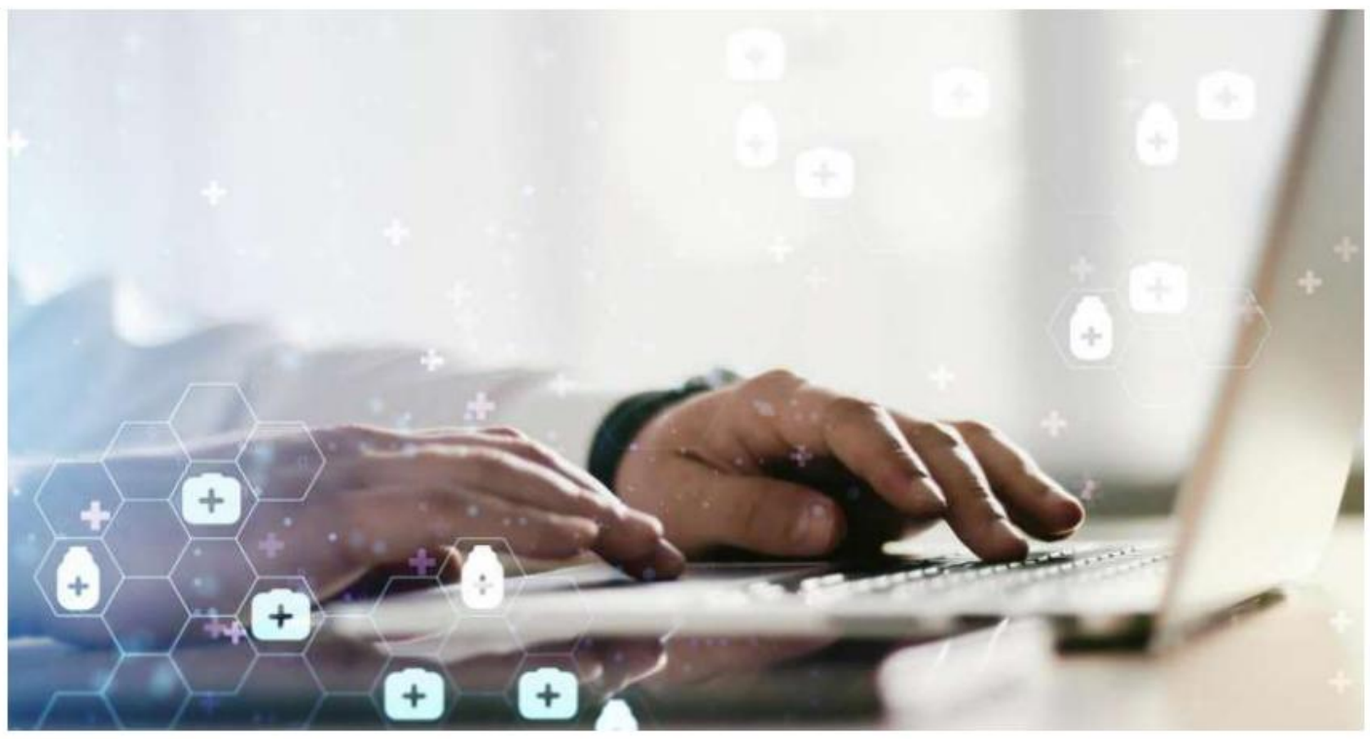

पीछे हटना: युवा पत्रकार IIT या इंडियन काउंसिल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च के किसी साइंटिस्ट के दावे की आलोचना करने में कल्चरली असहज महसूस कर सकते हैं। गेटी इमेजेज़

हमारे परिणामों ने यह भी प्रदर्शित किया कि एक संक्षिप्त, कम लागत वाले हस्तक्षेप से औसतन शीर्षक की सटीकता में उल्लेखनीय सुधार हुआ।"

पेपर में बताए गए 'इफेक्ट्स' के अलावा, यह स्टडी भारतीय न्यूज़रूम में साइंस जर्नलिज़्म के बारे में जो बताती है, उसके मामले में भी काफी जानकारी देती है — ऐसी जानकारी जो वरना आसानी से दिखाई नहीं देती। स्टडी का सुझाया गया इंटरवेंशन, वीडियो, आसान है, भले ही स्टडी के लेखक इस बात का ध्यान रखते हैं कि इसे आसान न बनाया जाए — फिर भी जब यह असल दुनिया, खासकर भारत की उलझी हुई दुनिया से मिलता है, तो ऐसी कोई चीज़ हमेशा अलग हो जाती है।

उदाहरण के लिए, स्टडी यह मानती है कि जिन पत्रकारों की तरफ से यह दखल दे रहा है, उनमें बुनियादी लेवल की पढ़ाई-लिखाई होती है। स्टडी पेपर में यह भी कहा गया है कि पत्रकार "आमतौर पर बहुत पढ़े-लिखे होते हैं": शायद जर्मनी में यह सच है, लेकिन 'बहुत' रिलेटिव है। वीडियो में एब्सोल्यूट बनाम रिलेटिव फिगर और रिप्रेजेंटेटिव सैंपल जैसे कॉन्सेप्ट शामिल हैं। पत्रकार के लिए डॉक्यूमेंट में इन पॉइंट्स को चेकपॉइंट के तौर पर देखने के लिए, जहाँ वह रुककर सोच सके, उनके पास पहले से ही उन्हें पहचानने के लिए ज़रूरी नंबर की जानकारी होनी चाहिए। भारत में इस तरह की पढ़ाई-लिखाई, पत्रकारों के बीच भी, बहुत ज़्यादा नहीं है।

दूसरा, हालांकि स्टडी यह मानती है कि पत्रकार डेडलाइन के साथ काम करते हैं, फिर भी यह ज़्यादातर बड़े भारतीय न्यूज़रूम की एक खास सच्चाई को कम आंक सकती है: जनरलिस्ट रिपोर्टर — वह जो कई बीट कवर करता है, जैसे सुबह एक साइंटिफिक पेपर और दोपहर में एक पॉलिटिकल रैली। और इन लोगों के पास स्टडी के तरीकों की डिटेल में जांच करने के लिए समय और रिसोर्स दोनों की कमी होती है। दूसरे शब्दों में, रिसर्चर्स का वीडियो इंटरवेंशन सिर्फ़ पत्रकार की सटीक होने की क्षमता को बेहतर बनाने में ही कामयाब होता है; यह ऐसे हालात भी नहीं बनाता जो इंटरवेंशन के काम का होने के लिए जगह बनाते हैं।

बेशक, रिसर्च पेपर्स तक पहुंच पाना बहुत मददगार होगा।

कई सबसे असरदार स्टडीज़ बहुत ज़्यादा महंगे पेवॉल के पीछे हैं।

भारत की नई 'वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन' स्कीम अपने दूसरे फेज़ में कई जर्नल्स के पेपर्स तक पब्लिक एक्सेस का वादा करती है, जो अभी शुरू होना बाकी है, इसलिए जर्नलिस्ट अभी एक्सेस वाले फ्रेंडली साइंटिस्ट्स और ओपन-एक्सेस पब्लिकेशन्स पर भरोसा कर रहे हैं।

शायद इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि इसके लिए पत्रकारों को यह भी सीखना होगा कि साइंस के कुछ हिस्सों को बिना साइंस के बारे में लिखे भी कैसे तोड़ा जा सकता है — और इसके लिए पत्रकारों, खासकर कम अनुभवी पत्रकारों को यह मानना होगा कि उन्हें इस तरह से साइंस की रिपोर्टिंग करने की इजाज़त है। युवा पत्रकार आमतौर पर 'द साइंटिस्ट' या 'द डॉक्टर' को ज़्यादा पसंद करते हैं और IIT या इंडियन काउंसिल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च के किसी साइंटिस्ट के दावे की आलोचना करने में कल्चरली असहज महसूस कर सकते हैं — भले ही उन्होंने ऐसा करने का कोई वीडियो देखा हो। एक क्रिटिकल नज़रिया तब ज़्यादा पनपता है जब उसी कम्युनिटी का कोई सीनियर, जाना-माना पत्रकार भी उसका समर्थन करता है।

ऐसा कहा जाता है कि जब पत्रकारों के पास पूरे पेपर तक पहुंच के साथ, वीडियो इंटरवेंशन यह जांचने का एक अच्छा मौका देता है कि प्रेस रिलीज़ हमेशा भरोसेमंद होती हैं या नहीं।

इसके बाद, सबसे बड़ी भारतीय समस्या है। भारत कई देशों का देश है और भाषाओं से भरा हुआ है।

यह स्टडी जर्मन पत्रकारों के साथ जर्मन और इंग्लिश में मटीरियल के साथ की गई थी। साइंस का इतिहास इन भाषाओं से काफी जुड़ा हुआ है, जिसका मतलब है कि जर्मन और इंग्लिश के बीच साइंटिफिक और मैथमेटिकल शब्दों का ट्रांसलेशन करना बहुत आसान है। लेकिन इंग्लिश/जर्मन से मराठी या तमिल में ट्रांसलेट करना लगभग नामुमकिन है, और शायद बहुत कन्फ्यूजिंग भी होगा।

आखिर में, हम एक ज़रूरी बात पर पहुँचते हैं: देश के बिखरे हुए, कई भाषाओं वाले, कम रिसोर्स वाले मीडिया इकोसिस्टम में, साइंस जर्नलिज़्म को कहीं और से लाए गए सॉल्यूशन से ठीक नहीं किया जा सकता (जितना ज़रूरी है)।

यह स्टडी की बुराई कम है — दुनिया को इसी तरह की और चीज़ों की ज़रूरत है — और यह मानना ज़्यादा है कि भारत के न्यूज़रूम को अंदर से ही शक और एडिटोरियल अनुशासन की आदतें डालनी होंगी। यह कोई इत्तेफ़ाक नहीं है कि ये आदतें बीट्स, भाषाओं, विचारधाराओं और न्यूज़रूम से कहीं आगे हैं।

स्ट्रक्चरल दबाव ये हालात न्यूज़ पब्लिकेशन के बिज़नेस मॉडल से तेज़ी से कंट्रोल होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई पब्लिकेशन विज्ञापनों से होने वाली कमाई पर ज़्यादा निर्भर करता है और बहुत ज़्यादा मुकाबले वाले मार्केट में काम करता है, तो कमाई उस ट्रैक से जुड़ जाती है जिसे रीडायरेक्ट किया जाता है।

भाषा की रुकावट इसी तरह, इस इंटरवेंशन का सबसे मज़बूत इस्तेमाल, जहाँ यह असल दुनिया में फेल नहीं होता, यूनिवर्सिटी प्रेस रिलीज़ के मामले में है। जब किसी यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट कोई ज़रूरी स्टडी पब्लिश करते हैं, तो यूनिवर्सिटी का प्रेस ऑफ़िस एक प्रेस रिलीज़ का ड्राफ़्ट बनाता है, अच्छा होता है लेकिन हमेशा साइंटिस्ट से सलाह करके नहीं, और इसे इंटरेस्टेड जर्नलिस्ट को ब्रॉडकास्ट करता है।

ये रिलीज़ अक्सर यूनिवर्सिटी को बहुत अच्छा दिखाने के लिए रिज़ल्ट को बढ़ा-चढ़ाकर बताते हैं। यह एक सीरियस प्रॉब्लम है क्योंकि रिसर्च पेपर के बजाय, ये प्रेस रिलीज़ अक्सर पहली बार होती हैं जब जर्नलिस्ट रिसर्च के कॉन्टैक्ट में आते हैं। अगर उनके पास पूरा पेपर नहीं है और काम करने के लिए सिर्फ़ प्रेस रिलीज़ है, और प्रेस रिलीज़ में स्टडी की फंडिंग के सोर्स या उसके कोहोर्ट के साइज़ का ज़िक्र नहीं है, तो वीडियो की गाइडलाइंस का कोई मतलब नहीं रह जाता।

अभिलेखागार से

अपने को जानो अंग्रेज़ी

एस. उपेंद्रन

"क्या आप वास्तव में मानते हैं कि हमारे कुछ खिलाड़ियों ने वास्तव में मैच तय किए हैं?"

"मेरे चाचा पट्टाभिरामन की राय के अनुसार, मैच फ़िंग संभव नहीं है।"

"वैसे, आप यह नहीं कह सकते, 'मेरे चाचा पट्टाभिरामन की राय के अनुसार। आप।'"

"क्या कोई व्यक्ति अपनी राय व्यक्त नहीं कर सकता?"

"बेशक, वह कर सकता है। लेकिन बात यह है कि अगर आप 'अकॉर्डिंग टू' इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप उसके बाद 'ओपिनियन' नहीं लगा सकते। आप कह सकते हैं, मेरे अंकल पट्टाभिरामन के अनुसार, मैच फ़िंग मुमकिन नहीं है।"

सुनील गावस्कर के अनुसार इस अवैध धंधे में केवल एक या दो लोग ही शामिल हैं।

"रमेश के अनुसार, सुजाता जन्मजात लड़ाकू है।"

"मेरे हिसाब से रमेश...." "....यह सही नहीं है. यह हमेशा किसी और के अनुसार।"

"अच्छा ऐसा है।"

"अगर आप कोई राय ज़ाहिर करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, 'मेरी राय में सुजाता लड़की नहीं है।'"

"मेरी राय में, भारत को रुक जाना चाहिए कुछ समय से क्रिकेट खेल रहा हूँ।
"मेरे हिसाब से इंडिया के पास कोई बॉलर नहीं है।"

कुछ लोगों के अनुसार भारत में टीम भावना नहीं है।

"क्रिकेट के खेल में मेरी रुचि खत्म हो गयी है।"

"लेकिन अखबारों में छपे वो मज़ेदार आर्टिकल हमें बहुत सारा मनोरंजन दे रहे हैं।"

"एंटरटेनमेंट. आर्टिकल हमें एंटरटेनमेंट दे रहे हैं. 'एंटरटेनमेंट' शब्द एक अनकाउंटेबल नाउन है. आप 'एंटरटेनमेंट्स' नहीं कह सकते."

"सच में? मैं हाल ही में गोवा गया था। वहां हर तरह का एंटरटेनमेंट मिलता है।
वो कैसा लगता है?"

"बहुत बढ़िया लगता है। यह एक और उदाहरण है। हर दिन जो एंटरटेनमेंट होता था, वह सच में बहुत बुरा था।"

"इससे मुझे याद आया. मुझे आज सेंट स्टीफ़न कॉलेज जाना है. मेरा दोस्त एक नाटक में एक्टिंग कर रहा है."

"नाटक वास्तव में हो सकता है मनोरंजक। आपको कभी पता नहीं चलता।"
"अच्छा होगा कि मैं घर जाकर अच्छे से तैयार हो जाऊं।"
"तुम कॉलेज प्ले के लिए तैयार हो रहे हो? लेकिन मुझे लगा तुम...."

"....मैं ऐसे नहीं जा सकता. मुझे एक अच्छी जींस पहननी है और...."
"....ओह, तुम तैयार होने जा रहे हो

और 'ड्रेस अप' नहीं। जब आप 'ड्रेस अप' करते हैं, तो आप कुछ पहनते हैं। दूसरे शब्दों में, आप सिर्फ़ अपने कपड़े बदलते हैं।

उदाहरण के लिए, अनन्या ने स्नान किया और स्कूल के लिए तैयार हो गई।

"दूसरे शब्दों में, उसने अपनी वर्दी पहन ली।"

"मेहमानों के आने से पहले, मैं कपड़े पहने और नीचे चला गया।"
"'ड्रेस्ड अप' का क्या मतलब है?"
"ठीक है, जब आप 'ड्रेस अप' करते हैं, तो आप खास कपड़े पहनते हैं। जैसे, जब भी कोई फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन होता है, तो आप बहुत सारे छोटे बच्चों को कृष्ण की तरह तैयार होते हुए देखते हैं।"

"क्रिसमस के दौरान, आप लोगों को सांता क्लॉज़ की तरह तैयार होते हुए पाते हैं।"
"हाँ।"
"लेकिन मुझे बताओ, क्या 'ड्रेस अप' का यही एकमात्र मतलब है? पहनना...." "....इसका मतलब फैंसी या स्मार्ट
कपड़े पहनना भी हो सकता है। क्या तुम नाटक के लिए तैयार होने जा रहे हो?"

"क्या तुम्हें लगता है कि मैं पागल हो गया हूँ?"
ऐसे नॉन-इवेंट के लिए कौन तैयार होगा?"

"मेरी राय में, आप ऐसा करेंगे।"
20 जून 2000 को द हिंदू में प्रकाशित

दैनिक प्रश्नोत्तरी

एडॉल्फ हिटलर की मौत आज ही के दिन 1945 में हुई थी। जर्मनी के तानाशाह पर एक क्विज़:

राधिका संथानम

X

प्रश्न 1 हिटलर के लिए
जर्मन में 'गाइड' शब्द का इस्तेमाल किया गया था?

X

सवाल 2 1923 में,
हिटलर ने तख्तापलट करने और वाइमर रिपब्लिक को हटाने की कोशिश की; इस कोशिश में उसे जेल हो गई।
इसे क्या कहा जाता था?

एक्स

प्रश्न 3 1933 से 1945
तक हिटलर द्वारा स्थापित तानाशाही का नाम क्या है?

X

प्रश्न 4 1936 में, नाज़ी
शासन ने इस इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट का इस्तेमाल प्रोपेगैंडा के लिए किया। यह 1948 तक दोबारा नहीं हुआ।
यह कौन सी घटना थी, और किस घटना के कारण इसमें देरी हुई?

एक्स

प्रश्न 5 एक्सिस अलायंस
हिटलर, मुसोलिनी और एक अन्य नेता के बीच बना था। उसका नाम बताइए।

X

विज़ुअल सवाल: अगर आप हैरी पॉटर के फ़ैन हैं, तो आपने चैंबर ऑफ़ सीक्रेट्स के बारे में सुना होगा। लेकिन क्या आपने चैंबर ऑफ़ हॉरर्स के बारे में सुना है? यह मूर्ति किस म्यूज़ियम के चैंबर ऑफ़ हॉरर्स में मिली है?

पिछले दिन के डेली क्विज़ के सवाल और जवाब: 1. किस मैगज़ीन ने शो को 20वीं सदी की सबसे बड़ी टेलीविज़न सीरीज़ का नाम दिया है? जवाब: टाइम
2. यह फिक्शनल कैरेक्टर होमर सिम्पसन का इस्तेमाल किया गया सबसे मशहूर कैचफ़्रेज़ है। इसे इंग्लिश भाषा में अपनाया गया है। यह क्या है? जवाब: "D'oh!"

3. परिवार के पास जो ग्रेहाउंड और बिल्ली है, उसका क्या नाम है? जवाब: सांताज़ लिटिल हेल्पर, स्नोबॉल II 4. सत्यजीत रे की मशहूर सीरीज़ के टाइटल कैरेक्टर के नाम पर रखे गए कैरेक्टर का क्या नाम है? जवाब: अपू नाहासापीमपेटिलॉन 5. उस एपिसोड का क्या नाम है जिसमें बताया गया है कि अरबपति डोनाल्ड ट्रंप एक समय में यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे और देश को कंगाल कर गए थे? जवाब: बार्ट टू द

भविष्य
विज़ुअल: इस इमेज में, शो के कैरेक्टर्स के नाम बताएं। जवाब: बाएं से: मैगी, मार्ज, लिसा, होमर और बार्ट अर्ली बर्ड्स: पुलकित साठे | पियाली तुली | नील लाल | प्रेम नाथ तिवारी | साधन पांडा

कृपया अपने जवाब dailyquiz@thehindu.co.in पर भेजें।

Word of the day

Esoteric:
confined to and understandable by only an enlightened inner circle

Synonyms: obscure, difficult, complex

Usage: *The book uses esoteric terms that most readers don't understand.*

Pronunciation: newsth.live/esoteric

International Phonetic Alphabet: /esəterɪk/

मतदान एक मिसाल

भारतीय राजनीति में पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 को अलग से याद किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान भी आशा के अनुरूप ऐतिहासिक रहा है। समग्रता में वहां मतदान ने जो कीर्तिमान बनाया है, उसकी तरह-तरह से विवेचना होगी और साथ ही, सीखने की भी कोशिश होगी। पहला श्रेय मतदाता जागरूकता के नाम है, तो दूसरा श्रेय मतदाता सूची पुनरीक्षण को दिया जाना चाहिए। मतदाता सूची सुधार का यह एक बेहतरीन नतीजा है। इसके पहले बिहार और तमिलनाडु के मतदान में भी सूची सुधार का असर दिखा, लेकिन जो पश्चिम बंगाल में हुआ है, वह अद्भुत है। अगर मतदाता सूची सुधार से मतदाता जागरूकता बढ़ती है और मतदान भी बढ़ता है, तो यह प्रक्रिया हर चुनाव से पहले दोहराई जानी चाहिए। लोकतंत्र को ऐसे ही नागरिक चाहिए, जो मतदाता सूची में अपना नाम रखने के लिए सजग रहते हों और मतदान के लिए बड़ी संख्या में अपने घर से बाहर निकलते हों। इस बार चुनावी गड़बड़ी की बात करें, तो एकाध जगह पर पुनर्मतदान की आवश्यकता पड़ रही है और यही उचित है।

बहरहाल, दूसरे चरण के मतदान के दौरान भी कुछ जगह कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है, मगर अच्छी बात है कि हिंसा वैसी नहीं हुई है, जैसी पहले होती थी। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में बंगाल में 300 के करीब हिंसक घटनाएं हुई थीं और 58 लोग मारे गए थे। पिछले चुनाव में मतदान से पहले और आठ चरणों में हुए मतदान के समय व मतदान के बाद भी हिंसा हुई थी, जिससे पश्चिम बंगाल के दामन पर दाग लगे थे। सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं ने विरोधी दलों के समर्थकों को निशाना बनाया था। इसके साथ ही, सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं के बीच भी कुछ जगह हिंसा हुई थी। दरअसल, हिंसक तत्व केवल अपने स्वार्थ और अपराध से संचालित होते हैं, किसी पार्टी की राजनीति या नैतिकता से उनका कोई सरोकार नहीं होता है। यह अक्सर कहा जाता है कि हिंसक तत्व पहले वामदलों की शरण में थे और अब तृणमूल कांग्रेस के पाले में हैं। ऐसे तत्वों का राजनीति में महत्व शून्य हो जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में अब जो भी सरकार बने, उसे बंगाल के दामन से इस दाग को छुड़ाना होगा। ऐसे हिंसक तत्व अक्सर अपने बड़े नेताओं की बोली-भाषा को भी बिगाड़ देते हैं, इसके अनेक उदाहरण हमने बंगाल के इस चुनाव में देखे हैं। ध्यान रहे, बंगाल देश में सर्वाधिक राजनीतिक हिंसा वाला राज्य है, उसके बाद क्रमशः आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर और उत्तर प्रदेश का नाम आता है। चुनावी या राजनीतिक हिंसा के लिए अक्सर बिहार का नाम लिया जाता है, लेकिन वह इस मामले में 14वें स्थान पर है। चुनावी हिंसा में केरल और तेलंगाना जैसे विकसित माने जाने वाले राज्य बिहार से बदतर हैं। बिहार ने अपने दामन पर लगे दाग को छुड़ा लिया है और आंकड़े बताते हैं कि पश्चिम बंगाल ने भी न्यूनतम हिंसक घटनाओं के साथ चुनाव 2026 से इसकी शुरुआत कर दी है।

बंगाल मतदान में एक मिसाल बन गया है। अगर मतदाता सूची सुधार से जागरूकता और मतदान बढ़ता है, तो यह प्रक्रिया हर चुनाव से पहले दोहराई जानी चाहिए।

पश्चिम बंगाल की एक ख्याति भद्र लोक के रूप में रही है और वहां जो भी अगली सरकार बने, उसे सुनिश्चित करना चाहिए कि राजनीति भद्रता की ओर कदम बढ़ाए। मतदान के बाद भी सुरक्षा बलों को सतर्क रहना चाहिए। मतगणना के बाद देख लेने की धमकी बंगाल के नेताओं द्वारा खुलेआम दी गई है, जिसे देश ने सुना है। आगामी दिनों में चुनाव आयोग को भी सजग रहना चाहिए और सुरक्षा बलों की उपयोगिता इसी में है कि वे हिंसा को हर संभव तरीके से काबू में रखें।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 30 अप्रैल, 1951

काश्मीर पर रुख

कांग्रेस अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तमदास टंडन ने कल यहां नगर कांग्रेस द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक सभा में भाषण देते हुए कहा कि भारत में इतनी शक्ति है कि वह काश्मीर के प्रश्न पर अपना रुख बदलने के लिए विदेशी ताकतों द्वारा डाले जा रहे दबाव का मुकाबला कर सके। ब्रिटेन तथा अमरीका ने काश्मीर के संबंध में अपना एक संयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करके, जिसे अन्ततः सुरक्षा परिषद ने स्वीकार किया, एक भारी गलती की है।

मैं ब्रिटेन व अमरीका द्वारा भारत के रुख का विरोध तथा पाकिस्तान का समर्थन करने की उनकी कार्रवाई पर प्रकाश डालने के लिए 'भारी गलती' शब्द का जान-बूझकर उपयोग कर रहा हूं। टण्डनजी ने कहा कि भारत का यह कर्तव्य है कि वह उक्त प्रस्ताव के विरुद्ध साहस के साथ डटा रहे। अमरीका तथा ब्रिटेन शक्तिशाली राष्ट्र हैं। मैं नहीं कह सकता कि भारत सैनिक दृष्टि से उनके विरुद्ध कहां तक खड़ा रहेगा। परन्तु मेरा मत यह है कि भारतीय जनता अपने पर्याप्त दृढ़ निश्चय के साथ सभी कठिनाइयों का मुकाबला कर सकती है। हमने ब्रिटिश साम्राज्यवाद से टक्कर ली, तथा उसे यहां से खदेड़ने में हम सफल हुए। उसी प्रकार हम आज भी अपनी स्वतंत्रता पर होनेवाले नये आक्रमणों का मुकाबला कर सकते हैं तथा काश्मीर की रक्षा कर सकते हैं जो भारत का एक अविभाज्य अंग है।

तीसरे विश्व-युद्ध की चर्चा का उल्लेख करते हुए टण्डनजी ने कहा कि आज भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है तथा वह युद्ध छिड़ जाने की हालत में यह निर्णय करने के लिए स्वतंत्र है कि उसके संबंध में उसका रुख क्या हो। कोई विदेशी ताकत भारत को ऐसे युद्ध का समर्थन कराने के लिए हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई चीज करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। जिस समय भारत गुलाम था ब्रिटेन में उसे उसकी जनता की इच्छा के विरुद्ध गत विश्व-युद्ध में झोंक दिया था। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, मैं कण्ट्रोलों को कृत्रिम मानता हूं। परन्तु मैं महसूस करता हूं कि सभी कण्ट्रोल तुरन्त नहीं हटाये जा सकते। अतः मेरा मत है कि सरकार को ऐसे कण्ट्रोल हटा देने चाहिए, जो अनावश्यक है। यदि हमारे व्यापारी सरकार को यह आश्वासन दें कि वे अपनी सामग्रियों को चोरबाजार में या मुनाफाखोरी से नहीं बेचेंगे, तो हम कण्ट्रोलों से मुक्ति पा सकते हैं।

बंगाल में इस बार बदलाव या बदला

प्रभाकर मणि तिवारी | वरिष्ठ पत्रकार

यहां स्कैन करें

पश्चिम बंगाल चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग के बाद भाजपा और तृणमूल कांग्रेस भले ही अपनी-अपनी जीत के दावे करें, सच यह है कि उनको भी असली वजह समझ में नहीं आ रही है।

पिछले कुछ वर्षों से पश्चिम बंगाल में होने वाला विधानसभा चुनाव देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले अमूमन ज्यादा सुर्खियां बटोरता रहा है, लेकिन इस बार तो यह सत्ता के दो मुख्य दावेदारों, यानी तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के लिए नाक और साख ही नहीं, बल्कि अस्तित्व का सवाल बन गया है। बीते 15 साल से सत्ता में रही ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के लिए यह चुनाव महज चौथी बार सत्ता में वापसी की परीक्षा नहीं है, इसमें पार्टी का अस्तित्व भी दांव पर लगा है। दूसरी ओर, उसे चुनौती देने के लिए इस बार अपने तमाम संसाधन झोंकने वाली भाजपा के लिए भी करो या मरो की स्थिति है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को पता है कि बंगाल की सत्ता पर काबिज होने के लिए उसे इससे बेहतर कोई मौका नहीं मिल सकता।

पश्चिम बंगाल का यह चुनाव कई मायने में अभूतपूर्व रहा है। बीते 25 वर्षों में पहली बार यहां कोई चुनाव महज दो चरणों में कराया गया है। इससे पहले छह से आठ चरणों में मतदान होता रहा है। इसके अलावा भारी तादाद में तैनात केंद्रीय बल और एसआईआर में कटे करीब 91 लाख नामों ने राजनीतिक दलों के समीकरण गड़बड़ा दिए हैं। बीते कई दशकों में पहली बार बंगाल में चुनावी हिंसा न के बराबर हुई है। इससे पहले यहां चुनाव से पहले और बाद में भारी हिंसा होती रही है।

अंग, बंग और कलिंग पर अपना झंडा लहराने की भाजपा की इच्छा बंग, यानी बंगाल पर काबिज हुए बिना अधूरी है। प्रधानमंत्री से लेकर पार्टी के तमाम दिग्गज अपने चुनाव प्रचार में इस बात का जिक्र करते रहे हैं, इसलिए इस बार उसने पिछली गलतियों से सबक लेते हुए अपनी चुनावी रणनीति में बदलाव किया। इसके तहत पार्टी के नेता चुनाव प्रचार में लोगों से बदलाव की अपील करते रहे हैं। दूसरी ओर, ममता बनर्जी लोगों से वोट के जरिये बदला लेने की अपील करती रहीं।

इसमें कोई दोराय नहीं कि इस बार एसआईआर से लोगों में डर का माहौल बना है। लाखों लोगों के नाम मतदाता सूची से कट गए हैं। यही वजह है कि पहली बार बंगाल से बाहर काम करने वाले लाखों लोग मतदान के लिए यहां लौटे हैं। उनको डर है कि अगर इस बार वोट नहीं डाला, तो कहीं अगली बार मतदाता सूची से नाम ही न कट जाए। तार्किक विसंगति वाले 27 लाख वोटर इस बार के चुनाव में वोट नहीं डाल सके हैं। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल ने मतदाताओं के इस डर को ही अपने पक्ष में भुनाते हुए इसे अपना सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था।

भाजपा नेता अपने प्रचार अभियान में राज्य के पिछड़ेपन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और घुसपैठ जैसे पारंपरिक मुद्दे उठाते हुए लोगों से बदलाव की अपील करते रहे। बदला और बदलाव के नारों के बीच हुए इस चुनाव में दोनों चरणों की रिकॉर्डतोड़ वोटिंग के बाद भाजपा और तृणमूल कांग्रेस अपनी-अपनी जीत के दावे भले कर रही हों, हकीकत यह है कि उनको भी असली वजह समझ में नहीं आ रही है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से के अलावा झारखंड से सटे इलाकों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत रही है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव से ही वह इन इलाकों में बेहतर प्रदर्शन करती रही है।

पहले चरण में जिन 152 सीटों पर वोट पड़े, उनमें से 59 सीटें पिछली बार भाजपा ने जीती थी। उत्तर बंगाल की तो 54 में से 30 सीटें उसे मिली थीं। दक्षिण बंगाल, यानी कोलकाता और उससे सटे इलाके तृणमूल कांग्रेस का गढ़ रहे हैं। इस दौर में जिन 142 सीटों पर वोट पड़े, उसमें से पार्टी को पिछली बार 118 सीटें मिली थीं, जबकि भाजपा को महज 18 सीटों से संतोष करना पड़ा था। भाजपा ने इस बार ममता के दक्षिण बंगाल के किले में सेंध लगाने की रणनीति बनाई है। इसके तहत अमित शाह लगातार कोलकाता में बने रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कोलकाता और आस-पास के इलाकों में रैलियां व रोड शो करते रहे। पार्टी का मकसद ममता बनर्जी के महिला व हिंदू वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करना था। इसके तहत ध्रुवीकरण के आरोप तो लगे ही, पार्टी ने अपने संकल्प-पत्र में महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये देने का भी वादा किया है। ममता बनर्जी सरकार लक्ष्मी भंडार योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये देती रही हैं।

कोलकाता की भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी को घेरने की रणनीति के तहत भाजपा ने यहां से शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा था और उनके नामांकनपत्र दायर करते समय अमित शाह ने स्वयं इलाके में रोड शो किया था। यह रणनीति कुछ हद तक कामयाब रही है, क्योंकि यह पहला मौका है, जब चुनाव के दिन ममता सुबह से ही अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा करती नजर आईं। इससे पहले वह दोपहर तक घर से ही मतदान पर निगाह रखती थीं और उसके बाद वोट डालने निकलती थीं।

तृणमूल कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा के रवैये के खिलाफ चुनाव अधिकारी से शिकायत की है। एक वायरल वीडियो में वह फालता के तृणमूल उम्मीदवार जहांगीर खान के परिजन को सरेआम चेतावनी देते नजर आए थे। पार्टी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की। इसके बाद अभिषेक बनर्जी ने प्रचार में आरोप लगाया कि भाजपा पुलिस पर्यवेक्षकों के जरिये सत्ता पर कब्जा करने के प्रयास कर रही है। बाहरी पर्यवेक्षकों के जरिये तृणमूल के वोटरों को धमकाया जा रहा है।

दूसरे दौर के मतदान में कम से कम 40 सीटों पर मतुआ समुदाय के लोग निर्णायक स्थिति में हैं। इस समुदाय के लाखों लोगों के नाम एसआईआर में कट गए हैं। इससे लोगों में नाराजगी है। यह तबका पारंपरिक रूप से भाजपा को समर्थन देता रहा है। इस समुदाय की नाराजगी को भांपते हुए ही प्रधानमंत्री उनको चुनाव बाद नागरिकता देने की गारंटी देते रहे। दूसरी ओर, ममता इसी मुद्दे पर इस समुदाय को अपने पाले में खींचने की कोशिश करती रहीं।

गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी आखिरी रैली में वादा किया है कि चुनाव के बाद भी केंद्रीय बल दो महीने तक बंगाल में बने रहेंगे। साल 2021 में चुनाव बाद हुई हिंसा के संदर्भ में उन्होंने यह बात कही थी, लेकिन सवाल है कि अगर तृणमूल कांग्रेस चौथी बार सत्ता में लौटी, तो क्या उसकी सरकार ऐसा होने देगी? बंगाल चुनाव में कई चीजें पहली बार देखने को मिली हैं, इसलिए यह तो अब 4 मई को ही पता चलेगा कि बंपर मतदान बदलाव के पक्ष में था या एसआईआर के खिलाफ?

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

तेल निर्यातक समूह के टूटने से आयातक देशों को लाभ

नरेंद्र तनेजा | पेट्रोलियम विशेषज्ञ

यहां स्कैन करें

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) का 'ओपेक' और 'ओपेक प्लस' से आगामी 1 मई से अलग होना पूरी दुनिया, विशेषकर तेल-आयातक राष्ट्रों के लिए एक सुखद घटना है। ओपेक एक ऐसा 'कार्टेल' (समूह) है, जिसके सदस्य देश तेल का उत्पादन करते हैं और अधिकता होने के कारण इसका बड़े पैमाने पर निर्यात करते हैं। यह संगठन इसीलिए बनाया गया, ताकि तेल की वैश्विक कीमतों पर वे मिलकर नियंत्रण रख सकें। इसके लिए वे अपना उत्पादन घटाने से भी नहीं हिचकते, ताकि उनका लाभ बना रहे।

यूएई इस संगठन का महत्वपूर्ण सदस्य देश है। उसके बाहर निकलने से ओपेक कमजोर होगा और तेल की कीमतों पर उसका शिकंजा ढीला पड़ सकता है। यह घटनाक्रम बताता है कि अमीरात ने तेल को लेकर भविष्य की अपनी रणनीतियों को आकार देना शुरू कर दिया है। गौरतलब है, बीते दिनों उसने तेल-ढांचे में भारी निवेश किया है। वह अभी 30 लाख बैरल तेल का रोजाना उत्पादन कर रहा है। अनुमान है कि नए निवेश के बाद दो साल के अंदर उसकी उत्पादन-क्षमता करीब 50 लाख बैरल प्रतिदिन तक हो सकती है। चूंकि ईरान युद्ध के कारण तेल की अहमियत बढ़ गई है, इसलिए संयुक्त अरब अमीरात अपने तेल पर 'अपना नियंत्रण' चाहता है। इसीलिए ओपेक छोड़ने के उसके फैसले से संगठन में हड़कंप मच गया है। यह 'ओपेक के अंत की शुरुआत' मानी जा रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में एक-दो और देश इस संगठन से किनारा कर सकते हैं।

संयुक्त अरब अमीरात अपने तेल पर अपना नियंत्रण चाहता है। इसीलिए ओपेक छोड़ने के उसके फैसले से हड़कंप मच गया है।

यूएई के इस कदम के कूटनीतिक निहितार्थ भी हैं। ओपेक में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश होने के कारण सऊदी अरब का दबाव ज्यादा रहा है। अमीरात इसके खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करता रहा है। बीते तीन साल में जब-जब सऊदी अरब ने तेल-उत्पादन घटाने की बात कही, तो उसने इसकी अवहेलना भी की। मानो यह आंतरिक मतभेद ही काफी नहीं था। ईरान युद्ध ने साफ कर दिया कि अमेरिका अकेले खाड़ी देशों की रक्षा नहीं कर सकता। अंदाजा था कि वे बेशक अमेरिका से पूरी तरह अलग नहीं होंगे, मगर उस पर अपनी निर्भरता जरूर कम करना चाहेंगे। यूएई ने इसकी शुरुआत कर दी है। उसने ऐसे देशों को देखना शुरू कर दिया है, जो उसके मित्र हैं, जिनको तेल की जरूरत है और भौगोलिक रूप से ज्यादा दूर नहीं हैं। इसीलिए भारत जैसे देशों के सामने इससे नए अवसर पैदा हो रहे हैं।

एशिया के जो चार बड़े तेल आयातक देश हैं, उनमें भारत सबसे आगे हैं। इसके बाद चीन, जापान और दक्षिण कोरिया का स्थान आता है। हम अपनी जरूरत का करीब 90 फीसदी तेल खरीदते हैं। हम रोजाना लगभग 57 लाख बैरल तेल की खपत करते हैं, जबकि हमारा आयात 52-53 लाख बैरल प्रतिदिन है। इसीलिए, हम एक तेल-अर्थव्यवस्था भी कहलाते हैं। ऐसे में, उस समूह में यदि दरार पड़ती है, जो बना ही इसलिए कि वह अधिक से अधिक लाभ कमाए और तेल की कीमतें घटने न दे, तो यह भारत के हित में है। सुखद यह भी है कि हमने बीते कुछ वर्षों से अपनी रणनीति में बड़े बदलाव किए हैं। अब हम किसी एक क्षेत्र या देश पर निर्भर नहीं हैं और करीब 41 देशों से तेल खरीद रहे हैं।

संयुक्त अरब अमीरात-भारत संबंधों में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की अबू धाबी यात्रा से भी सकारात्मक असर पड़ा है। यह दो दिवसीय दौरा अप्रैल के पहले पखवाड़े में किया गया था। यात्रा में जयशंकर ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश सौंपा था। माना जा रहा है कि उस पत्र में द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सहयोग व व्यापार बढ़ाने की बात कही गई थी। चूंकि अमीरात हमारा नजदीकी मित्र है, इसलिए इस तरह की यात्राओं से विशेषकर ऊर्जा संकट के दौर में द्विपक्षीय कारोबार को बढ़ाने में काफी मदद मिलने की उम्मीद है। यूएई में 40 लाख से अधिक भारतीयों की रिहाइश का भी अपना कूटनीतिक महत्व है।

कुल मिलाकर, यही कहना उचित होगा कि जब वैश्विक अर्थव्यवस्था की धुरी तेल हो, तो ओपेक जैसे संगठन विश्व को स्वीकार्य नहीं हो सकते, इसलिए उसका कमजोर पड़ जाना ही अच्छा है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

आत्मा से अलग कुछ नहीं

मुझसे किसी ने पूछा है कि मैं आत्मा तक कैसे पहुंच सकता हूं?

आत्मा तक पहुंचना नहीं होता है। यदि पहुंचना होता, तो उसका यही मतलब होता कि आत्मा इस स्थल और पल में नहीं है और उसे प्राप्त करना अभी बाकी है। आत्मा अनित्य है। अनित्य वस्तु के लिए यत्न करना उचित नहीं है। आप आत्मा हैं, आप पहले से वह हैं। हकीकत यह है कि आप अपनी आनंदमय अवस्था से अनभिज्ञ हैं। शुद्ध आत्मा स्वयं आनंद है। अज्ञान बीच में आकर उस पर परदा डाल देता है। सारे प्रयत्न केवल मिथ्या ज्ञान रूपी अज्ञान को दूर करने के लिए किए जाते हैं। आत्मा को देह-मन के साथ एकरूप मान लेना मिथ्या ज्ञान है।

आत्मा को जानने का अर्थ आत्मा होना है। होना ही सत्ता है, स्वयं का होना सत्ता है। अपनी न दिखने वाली आंखों के अस्तित्व की तरह, कोई भी न दिखने वाली आत्मा का इनकार नहीं करता है। जैसे आप अपनी आंखों को दर्पण में वस्तु की तरह देखते हैं, इसी प्रकार अपनी आत्मा को भी वस्तु की तरह देखना चाहते हैं, बस यही मुसीबत है। आप वस्तु-सत्ता से इतने घुल-मिल गए हैं कि आपने अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान गंवा दिया है। आत्मा को कौन जानेगा? क्या अचेतन शरीर उसे जानेगा? आप हमेशा अपने 'मैं' के बारे में बोलते और सोचते हैं, लेकिन पूछे जाने पर उसका इनकार करते हैं। आप आत्मा हैं, फिर भी पूछते हैं कि उसे कैसे जाना जाए? इसमें ईश्वर की लीला और उसकी निर्दयता कहां है?

आत्म-साक्षात्कार दूसरों की भी सहायता कर सकता है। यह हरसंभव सहायताओं में श्रेष्ठ है, यदि वह सहायता सुनार की भांति की जाए। सुनार जैसे सारे गहनों में केवल सोना देखता है, ऐसे ही ज्ञानी सब में केवल आत्मा ही देखता है। आप जब अपने आपको शरीर के साथ एकरूप मानते हैं, केवल तभी आकार व रूप दिखते हैं। जब आप अपने शरीर से परे होते हैं, तब आपकी शारीरिक चेतना के साथ दूसरे भी अदृश्य हो जाते हैं।

आप सोच रहे होंगे कि क्या पेड़, वनस्पति इत्यादि के बारे में भी यह सत्य है? इसके उत्तर के लिए विश्लेषण कीजिए कि क्या वे कभी भी आत्मा से अलग अस्तित्व रखते हैं? आप सोचते हैं कि आप उन्हें देखते हैं। विचार आत्मा से प्रकट होते हैं। ढूंढ़ निकालिए कि ऐसे विचार कहां से प्रकट होते हैं? तब विचार शांत हो जाएंगे और केवल आत्मा शेष रहेगी।

आप वस्तु-सत्ता से इतने घुल-मिल गए हैं कि आपने अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान गंवा दिया है। आत्मा को कौन जानेगा? क्या अचेतन शरीर उसे जानेगा?

आत्मा ने अहं उत्पन्न किया है और अहंकार अपने ऊपर चिपके विचारों के भार से लदा हुआ है, जो जगत्, वृक्ष, वनस्पति इत्यादि के रूप में दिख रहे हैं। वस्तुतः ये सब आत्मा के अलावा कुछ नहीं हैं। यदि आप आत्मा को देखें, तो वही सर्वदा, सर्वत्र, सर्वरूप दिखाई देगी। आत्मा से अलग कुछ नहीं है।

रमण महर्षि

शेखर कपूर | फिल्म निर्माता

क्या भविष्य में ऐसी कोई तकनीक आएगी, जिससे हमें 'डिवाइस' की जरूरत ही न पड़े? क्या हम आपस में 'सहज बुद्धि की रफ्तार' से जुड़ सकते हैं? क्या डिवाइस पर बढ़ती निर्भरता हमारी सहज बुद्धि को खत्म नहीं कर रही है?

अनुलोम-विलोम

भारत-न्यूजीलैंड समझौता

भारतीय निर्यात के लिए बढ़े अवसर

भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) सिर्फ आर्थिक करार नहीं है, बल्कि यह दोनों देशों के बीच गहरे होते भरोसे, सहयोग और भविष्य की साझा संभावनाओं का प्रतीक भी है। इस समझौते के जरिये न सिर्फ व्यापारिक रिश्तों को नई गति मिलेगी, बल्कि किसानों, व्यापारियों, छात्रों और नौकरीपेशा युवाओं के लिए भी नए दरवाजे खुलेंगे। यह समझौता ऐसे समय में हुआ है, जब वैश्विक अर्थव्यवस्था कई चुनौतियों से गुजर रही है और देशों के बीच मजबूत साझेदारी की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महसूस की जा रही है।

एफटीए के तहत न्यूजीलैंड भारतीय निर्यात पर लगभग सभी टैरिफ समाप्त कर देगा, जिससे भारतीय उत्पाद वहां सस्ते व अधिक प्रतिस्पर्द्धी बन जाएंगे। इसके जवाब में भारत भी न्यूजीलैंड से आने वाले लगभग 95 प्रतिशत उत्पादों पर शुल्क में भारी कमी करेगा। इस तरह यह समझौता द्विपक्षीय व्यापार को संतुलित और व्यापक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले पांच वर्षों में दोनों देशों ने व्यापार को पांच अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, जो वर्तमान स्तर की तुलना में एक बड़ा उछाल होगा। इस समझौते का सबसे बड़ा लाभ भारत के उन क्षेत्रों को मिलेगा, जो निर्यात पर निर्भर हैं। यहां के रेडीमेड गारमेंट्स, चमड़ा, जूते, समुद्री उत्पाद, आभूषण, हस्तशिल्प और इंजीनियरिंग सामान न्यूजीलैंड के बाजार में बिना शुल्क के प्रवेश कर सकेंगे। इससे भारतीय उत्पादों की मांग बढ़ेगी और देश के एमएसएमई सेक्टर को मजबूती मिलेगी। किसानों के लिए भी यह समझौता राहत लेकर आया है। हालांकि, भारत ने डेयरी, कॉफी, मसाले, खाद्य तेल और कुछ अन्य संवेदनशील कृषि उत्पादों को इस समझौते से बाहर रखा है, ताकि घरेलू किसानों को नुकसान न हो। यह एक संतुलित रणनीति है। दूसरी ओर, भारत को न्यूजीलैंड से लकड़ी, कोकिंग कोल और धातु स्क्रैप जैसे औद्योगिक कच्चे माल पर ड्यूटी-फ्री पहुंच मिलेगी। इससे भारतीय उद्योगों की उत्पादन लागत कम होगी और विनिर्माण क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।

यह समझौता केवल वस्तुओं के व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि सेवा क्षेत्र और मानव संसाधन के आदान-प्रदान को भी बढ़ावा देता है। भारतीय युवाओं के लिए यह एक बड़ा अवसर बनकर सामने आया है। इस डील के तहत हजारों भारतीय पेशेवरों को न्यूजीलैंड में काम करने के लिए अस्थायी वीजा मिलेंगे। इससे भारत के सेवा क्षेत्र के निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। साफ है, यह एक करार शिक्षा, व्यापार, रोजगार और कूटनीति के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ा बदलाव ला सकता है।

कांतिलाल मांडोत, टिप्पणीकार

समझौते की कमियों पर ध्यान देना जरूरी

भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता यूं तो सीधे-सीधे भारतीय हितों पर चोट नहीं करता, इसलिए यह हमारे लिए अनुकूल है, लेकिन न्यूजीलैंड में इसके खिलाफ दबे स्वर में कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं। यह संकेत है कि कहीं-न-कहीं वहां के कुछ लोग इससे नाराज हैं। चूंकि हम 'सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय' को मानने वाले देश हैं, इसलिए इस समझौते की कमियों को दूर करना हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए।

वास्तव में, न्यूजीलैंड में इस समझौता की इसलिए आलोचना हो रही है, क्योंकि इसे 'कम गुणवत्ता वाला' और 'बुरा समझौता' माना जा रहा है। आलोचना करने वाली 'न्यूजीलैंड फर्स्ट' पार्टी का तर्क है कि इसमें डेयरी निर्यात पर पर्याप्त रियायतें नहीं दी गई हैं, जबकि भारतीय उत्पादों के लिए बाजार खोल दिया गया है। कहा जा रहा है कि भारत ने न्यूजीलैंड के प्रमुख डेयरी निर्यात (दूध, पनीर, मक्खन आदि) पर शुल्क में कोई खास कमी नहीं की, जो उनके कुल माल-निर्यात का लगभग 30 प्रतिशत है। इसी तरह, न्यूजीलैंड के विपक्षी दल का मानना है कि इस समझौते से उनके देश को नुकसान ही हुआ है, क्योंकि जितना उसने गंवाया है, उस हिसाब से उसे कम की प्राप्ति हुई है। इसे उचित विचार-विमर्श के बिना आनन-फानन में अंतिम रूप दिया गया है। आलोचकों की मानें, तो इस समझौते में आव्रजन संबंधी चिंताओं को दूर करने का भरोसा भी नहीं दिखता। समझौते के तहत श्रमिकों के आगमन को लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं, जिसे न्यूजीलैंड की घरेलू राजनीति में एक संवेदनशील मुद्दा माना जाता है। एक सवाल व्यापार संतुलन का भी है। कहा जा रहा है कि भारतीय उत्पादों के लिए बाजार पूरी तरह खोल देने से, डेयरी उत्पादों में कम पहुंच के कारण, न्यूजीलैंड के किसानों को नुकसान हो सकता है। चूंकि भारत को सीमा शुल्क में भी रियायतें दी गई हैं, इसलिए तीसरे देश के माल के दुरुपयोग का खतरा हो सकता है।

साफ है, आलोचना के इन स्वरों को शांत करना जरूरी है। यह सही है कि हमने न्यूजीलैंड के हितों का कहीं अधिक ख्याल रखा है और यह भी सच है कि सबको खुश करना संभव नहीं है, फिर भी, जहां तक संभव हो, हमें कुछ लचीला रुख अपनाना चाहिए। हम एक बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और विकसित देश बनने की राह पर हैं। ऐसे में, हमारे ऊपर जिम्मेदारी कहीं अधिक होनी चाहिए। हमें इस समझौते को लेकर उठ रही तमाम शंकाओं को दूर करना चाहिए और न्यूजीलैंड के लोगों को यह विश्वास दिलाना ही चाहिए कि समझौते में उनके हितों का ख्याल रखा गया है।

दिवाकर मिश्र, टिप्पणीकार

मनचाहे कॉलेज में ऐसे मिलेगा दाखिला

सीयूईटी-यूजी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हर साल स्नातक कोर्स में प्रवेश के लिए आयोजित होता है। इस परीक्षा में बैठने के लिए इस साल लगभग 15 लाख छात्रों ने पंजीकरण कराया है। हर छात्र को पता है कि यह परीक्षा उच्च शिक्षा के द्वार खोलती है। यह परीक्षा क्या है? इसमें हाई स्कोर कैसे पाएं? मनचाहे विषय और संस्थान पाने की क्या हो रणनीति, बता रहे हैं करियर सलाहकार सोनिक सौरभ

कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी सीयूईटी-यूजी ने स्नातक में दाखिले को पूरी बदल दिया है, जिससे अब छात्रों को मनचाहे संस्थान में प्रवेश का समान अवसर मिलता है। सत्र 2026 के लिए यह परीक्षा 11 से 31 मई के बीच संभावित है, जिसमें लगभग 14.92 लाख अभ्यर्थियों का पंजीकरण हुआ है। यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी मोड में ली जाएगी।

पसंदीदा कॉलेज के लिए हाई स्कोर

12वीं के बाद श्रेष्ठ कॉलेज में दाखिले के लिए सीयूईटी अब पूरी प्रक्रिया का केंद्र बन चुका है, जहां एक कॉमन स्कोर से देशभर की यूनिवर्सिटीज में प्रवेश मिलता है। इसलिए इसे सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि सटीक तैयारी, रणनीति और काउंसलिंग के साथ समझना जरूरी है। परीक्षा में हर विषय के लिए 60 मिनट में 50 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, जिसमें लैंग्वेज, डोमेन (एनसीईआरटी आधारित) और जनरल टेस्ट शामिल हैं। अधिकतम 5 विषयों के साथ कुल स्कोर 1250 तक जा सकता है, इसलिए यहां औसत नहीं, बल्कि हाई स्कोर ही आपके पसंदीदा कॉलेज और कोर्स की कुंजी बनता है।

अहम है विषयों का चयन

सीयूईटी में अलग-अलग कोर्स (बीए ऑनर्स/प्रोग्राम, बीएससी, बीकॉम, बीटेक) के लिए विषयों का चयन अलग होता है। छात्र आमतौर पर 3 से 5 (कभी 6) विषय चुनते हैं, जिनमें एक लैंग्वेज लेना अनिवार्य है। बाकी विषय 12वीं के आधार पर होते हैं। हर विषय 250 अंकों का होता है, इसलिए कुल स्कोर चुने गए विषयों पर निर्भर करता है। ज्यादा विषय लेने से अलग-अलग कोर्स के कॉम्बिनेशन विकल्प बढ़ जाते हैं। कटऑफ कॉलेज और कोर्स के अनुसार बदलता है-कहीं अच्छा कॉलेज मिलता है तो मनपसंद विषय नहीं और कहीं विषय अच्छे होते हैं तो कॉलेज की रैंकिंग कम होती है, इसलिए मिल रहे विकल्पों में से अपने लिए बेस्ट देखना पड़ता है। छात्र अपने कोर्स और यूनिवर्सिटी की पात्रता के अनुसार विषय चुनते हैं, और इन्हीं के अंकों से उनका अंतिम सीयूईटी स्कोर बनता है। कोर्स आमतौर पर 6-8 सेमेस्टर का होता है। हर सेमेस्टर में करीब 7 विषय होते है।

उच्च स्कोर की रणनीति समझें

- हर सही उत्तर पर 5 अंक मिलते हैं, तो गलत पर 1 अंक कटता है। जबकि छोड़ दिए गए प्रश्न पर न तो अंक मिलते हैं, न कटते हैं।
- खास बात यह है कि कुछ विशेष स्थितियों में छात्रों को लाभ मिल सकता है, लेकिन अक्सर छात्र इसे नजरअंदाज कर देते हैं।
- यदि किसी प्रश्न के सभी विकल्प सही हों, तो उस प्रश्न को अटैम्प्ट करने वाले सभी छात्रों को अंक दिए जाते हैं।
- यदि किसी प्रश्न में कोई भी विकल्प सही नहीं पाया जाता और उसे ड्रॉप कर दिया जाता है, तब भी उस प्रश्न को अटैम्प्ट करने वाले सभी छात्रों को 5 अंक मिलते हैं।
- इसका सीधा मतलब यह है कि सीयूईटी केवल किताबी ज्ञान का नहीं, बल्कि स्मार्ट अटैम्प्ट और रिस्क मैनेजमेंट का भी खेल है।

विषय संरचना को ऐसे समझें

परीक्षा तीन भागों में होती है-भाषा, डोमेन विषय व जनरल टेस्ट। भाषा सेक्शन में हिंदी, अंग्रेजी सहित 33 से अधिक भाषाएं शामिल हैं। डोमेन विषय 12वीं पर आधारित होते हैं, जिनमें विज्ञान, वाणिज्य और आर्ट्स/ह्यूमैनिटीज शामिल हैं। जनरल टेस्ट में जीके, करंट अफेयर्स, रीजनिंग और बेसिक मैथ्स के प्रश्न आते हैं।

तैयारी कैसी हो

- पहले पूरा सिलेबस समझें, विषयों के टॉपिक्स की सूची बनाएं और उन्हें आसान-कठिन तथा वेटेज के आधार पर बांटें।
- तैयारी में एनसीईआरटी की भूमिका सबसे अहम होती है, खासकर डोमेन विषयों के लिए। मॉक टेस्ट सीरीज भी मददगार होते हैं।
- टाइमटेबल बनाकर पढ़ाई को दैनिक, साप्ताहिक और मासिक स्तर पर बांटें, ताकि सिलेबस समय पर पूरा हो और रिवीजन के लिए समय रहे।

तैयारी के अंतिम दिनों में : आखिरी 20-30 दिन आपकी तैयारी का परिणाम तय करते हैं। लगातार मॉक टेस्ट दें और गलतियों का विश्लेषण करें- चाहे वह कॉन्सेप्ट, समय प्रबंधन या जल्दबाजी से जुड़ी हो। रिवीजन का फोकस एनसीईआरटी और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों पर रखें, ताकि पैटर्न स्पष्ट हो। साथ ही, लंबा व थकाने वाला प्लान बनाने, बिना विश्लेषण के मॉक देते रहने, बार-बार रणनीति बदलने, नए टॉपिक्स शुरू करने और केवल रटने पर निर्भर रहने से बचें।

कहां काम आएगा स्कोर : सीयूईटी स्कोर का उपयोग देश की 200 से अधिक यूनिवर्सिटीज में हो रहा है। इसमें सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड व कई निजी विश्वविद्यालय शामिल हैं, जैसे कि दिल्ली विश्वविद्यालय, एमिटी यूनिवर्सिटी, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी आदि।

- **काउंसलिंग को हल्के में न लें :** सीयूईटी के बाद सबसे अहम चरण काउंसलिंग का होता है, जहां छोटी-सी गलती भी आपके एडमिशन को प्रभावित कर सकती है। हर यूनिवर्सिटी की प्रक्रिया अलग होती है- रजिस्ट्रेशन, कोर्स-कॉलेज की प्रेफरेंस भरना और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसके मुख्य हिस्से हैं। खास तौर पर मनचाहे संस्थानों को भरते समय ध्यान रखें। यही तय करता है कि आपको कौन-सा कॉलेज मिलेगा। यदि आप केवल ड्रीम कॉलेज भरेंगे, तो सीट न मिलने पर आप काउंसलिंग से बाहर हो सकते हैं। यदि केवल बैकअप भरेंगे, तो अच्छे अंक होने के बावजूद आप खराब कॉलेज में फंस जाएंगे। इसलिए, संतुलन ही सबसे अच्छी रणनीति है। ज्यादा से ज्यादा कॉलेज और यूनिवर्सिटी के विकल्प भरें, ताकि अवसर बढ़े।

न मिले मनचाहा स्ट्रीम तो : मॉप-अप राउंड तक बने रहें, कई बार खाली सीटों पर एडमिशन मिल जाता है। साथ ही, राज्य और निजी विश्वविद्यालयों जैसे एमिटी यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में सीधे या अलग एंट्रेंस के जरिए भी मौके तलाशें। जरूरत पड़े तो बी.वोक, कंप्यूटर, डिजाइन या डाटा जैसे स्किल-आधारित डिप्लोमा/कोर्स के जरिए आगे बढ़ सकते हैं।

जॉब/करिअर

- सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में कॉन्स्टेबल टेक्निकल एवं ट्रेड्समेन और पायनियर की भर्तियां की जाएंगी। योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

कुल पद : 9195
अंतिम तिथि : 19 मई 2026
आवेदन प्रक्रिया : आधिकारिक वेबसाइट rect.crpf.gov.in पर लॉगइन करें।

- उत्तर प्रदेश को-ऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड, लखनऊ में क्लर्क, स्टेनोग्राफर, मैनेजर समेत अन्य पद भरे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया जारी है।

कुल पद : 2085
अंतिम तिथि : 15 मई 2026
आवेदन प्रक्रिया : आधिकारिक वेबसाइट है - upcisb.upsdc.gov.in

- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अप्रेंटिस की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं।

कुल पद : 1865
अंतिम तिथि : 19 मई 2026
आवेदन प्रक्रिया : बैंक की वेबसाइट है - unionbankofindia.bank.in

- स्टाफ सेलेक्शन बोर्ड ने स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एवं डी के पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं।

कुल पद : 731
अंतिम तिथि : 15 मई 2026
आवेदन प्रक्रिया : आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर लॉगइन करें।

- महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड में असिस्टेंट फोरमैन एवं टेक्नीशियन के पदों पर आवेदन का अवसर है।

कुल पद : 500
अंतिम तिथि : 28 मई 2026
आवेदन प्रक्रिया : ऑनलाइन करना होगा। वेबसाइट है- mahanadicoal.in

- एनएचपीसी लिमिटेड में अप्रेंटिस की रिक्तियां भरी जाएंगी। इसके तहत ग्रेजुएट, डिप्लोमा एवं आईटीआई ट्रेड में भर्तियां होंगी।

कुल पद : 182
अंतिम तिथि : 06 मई 2026
आवेदन प्रक्रिया : इस वेबसाइट पर जाएं - nhpcindia.com

- उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पद भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं।

कुल पद : 100
अंतिम तिथि : 05 मई 2026
आवेदन प्रक्रिया : आधिकारिक वेबसाइट है- upanganwadibharti.in

- पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ में सीनियर रेजिडेंट समेत अन्य पदों पर नियुक्तियां होंगी।

कुल पद : 577
अंतिम तिथि : 11 मई 2026
आवेदन प्रक्रिया : वेबसाइट- pgimer.edu.in

(**नोट :** आवेदन करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट से अपने स्तर पर जरूर जांच कर लें।)

भेजें अपना सवाल

करियर या शैक्षिक कोर्स संबंधी आपके मन में कोई उलझन है या कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें अपने सवाल नीचे दी गई ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ उसके जवाब देंगे। इस ईमेल आईडी का उपयोग करें

nayiraheincareer@gmail.com

बीसीए के बाद निजी क्षेत्र में ज्यादा मौके

एक्सपर्ट टिप्स

डॉ. संजीब कुमार आचार्य
सीनियर करियर काउंसलर

- **बीसीए की डिग्री प्राप्त करने के बाद क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल सकती है? यदि नहीं, तो सरकारी नौकरी के अलावा मेरे लिए अन्य कौन से विकल्प बेहतर रहेंगे? – रोहन प्रजापति**

बीसीए पूरा करने के बाद सरकारी नौकरियों के अवसर बीटेक जैसी तकनीकी डिग्री की तुलना में कम होते हैं, क्योंकि अधिकतर पद किसी भी स्नातक के लिए खुले होते हैं। फिर भी आप एसएससी-सीजीएल, बैंकिंग पीओ/क्लर्क, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, स्टेट पीएससी और यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में आवेदन कर सकते हैं। साथ ही नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, बैंकों में आईटी ऑफिसर या सरकारी विभागों में जूनियर प्रोग्रामर जैसे तकनीकी पदों पर भी मौके मिल सकते हैं, अगर आपकी प्रोग्रामिंग मजबूत हो।

दूसरे करियर विकल्प भी तलाशें, जहां बीसीए के अच्छे अवसर मौजूद हैं, जैसे कि प्राइवेट आईटी सेक्टर में। यहां सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर, या साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल के रूप में काम कर सकते हैं। इसके लिए पायथन, जावा, क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई/एमएल जैसे कौशल जरूरी हैं, जो ज्यादा वेतन और तरक्की दिला सके। आप एमसीए, एमबीए-आईटी/ बिजनेस एनालिटिक्स या डाटा साइंस, क्लाउड, साइबर -सिक्योरिटी में सर्टिफिकेशन कर मौके बढ़ा सकते हैं। फ्रीलांसिग, स्टार्टअप या रिमोट टेक जॉब्स भी काम आएंगे।

- **मैं 11वीं में पीसीबी लेना चाहती हूं। डॉक्टर बनने के अलावा पीसीबी लेने के बाद कौन से करियर विकल्प हैं? उनसे जुड़ी प्रवेश परीक्षाओं के बारे में भी बताएं। – गुड़िया कुमारी**

आप एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीपीटी, नर्सिंग, फार्मेसी या पैरामेडिकल कोर्स कर सकती हैं। इनमें से अधिकतर मेडिकल कोर्स के लिए नीट मुख्य प्रवेश परीक्षा है। कई कॉलेज एलाएड और पैरामेडिकल कोर्स में भी नीट स्कोर स्वीकार करने लगे हैं। हालांकि, कुछ जगह एडमिशन मेरिट, राज्य स्तरीय परीक्षा या अपनी परीक्षाओं के आधार पर होता है। पीसीबी छात्रों के लिए बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री और बायोमेडिकल साइंसेज जैसे कई विकल्प उपलब्ध हैं। प्रवेश के लिए सीयूईटी और आईआईएसईआर एप्टीट्यूड टेस्ट जैसी परीक्षाएं होती हैं, जबकि इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस रिसर्च के लिए अच्छे संस्थान माने जाते हैं।

भविष्य में साइंटिफिक रिसर्च, ड्रग डेवलपमेंट या एन्वॉयरमेंटल साइंस जैसे क्षेत्र में करियर बना सकती हैं। अगर आप मैथेमेटिक्स (पीसीएमबी) भी साथ लेती हैं, तो जेईई-मेन और जेईई एडवांस्ड देकर बायोटेक इंजीनियरिंग और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में जा सकती हैं। साइकोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, फॉरेंसिक साइंस, एग्रीकल्चर और ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी जैसी सिविल सेवाओं में भी अवसर मिल सकते हैं।

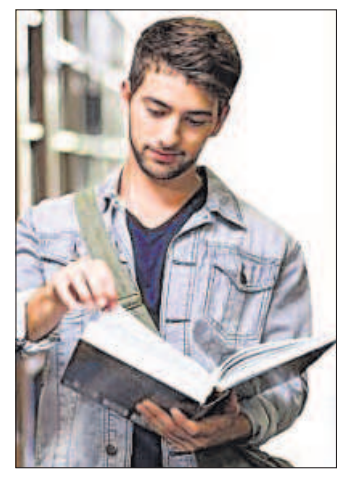

www.sanjibacharya.com

हिन्दुस्तान क्विज-4

हिन्दुस्तान अर्थात भारत की विकास यात्रा बहुआयामी रही है। इसी महायात्रा से हम पाठकों के लिए कुछ प्रश्न लेकर आए हैं, जो सामान्य ज्ञान के लिए उपयोगी हैं। पेश हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी पार्थ सारथी सेन शर्मा के दस सवाल और उनके जवाब...

1. अंग्रेजों के जमाने में उत्तर प्रदेश की राजधानी गर्मियों के दिनों में कहां स्थानांतरित हो जाती थी?
2. हिंदुस्तान में प्रकाशित होने वाले सबसे पहले अखबार का क्या नाम था?
3. किस हिंदुस्तानी ने ऑपरेशन ब्लूस्टार के विरोध में पद्मभूषण की उपाधि वापस पर दी थी?

4. श्याम बेनेगल के प्रसिद्ध दूरदर्शन धारावाहिक में जवाहरलाल नेहरू का किरदार किस अभिनेता ने निभाया था?
5. हिंदुस्तान के किस प्रसिद्ध लेखक की आत्मकथा का नाम 'रसीदी टिकट' है?
6. हिंदुस्तान के किस किले की दीवार सबसे लंबी है और पूरे विश्व में 'ग्रेट वॉल ऑफ चाइना' के बाद सबसे लंबी दीवार मानी जाती है?

7. देवताओं के राजा इंद्र देव के वाहन का क्या नाम है?
8. किस हिंदुस्तानी ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में हिंदी में भाषण दिया था?
9. किस प्रसिद्ध हिंदुस्तानी धार्मिक महात्मा का असली नाम मूलशंकर था?
10. हिंदुस्तान के किस प्रसिद्ध उर्दू शायर का असली नाम रघुपति सहाय था?

उत्तर : 1. नैनीताल 2. उदंत मार्तण्ड 3. प्रसिद्ध लेखक खुशवंत सिंह 4. रोशन सेठ 5. अमृता प्रीतम 6. कुंभलगढ़ का किला (राजस्थान) 7. ऐरावत (सफेद हाथी) 8. अटल बिहारी वाजपेयी 9. दयानंद सरस्वती 10. फिराक गोरखपुरी

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

मेष : मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। संतान सुख में वृद्धि होगी। परिवार में धार्मिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ सकती है। परिवार की बुजुर्ग महिलाओं से धन मिल सकता है।

वृष : आत्मविश्वास तो भरपूर रहेगा, परंतु मन में उतार-चढ़ाव भी हो सकते हैं। संयत रहें। माता की सेहत का ध्यान रखें। खर्चों में वृद्धि होगी। परिवार का साथ मिलेगा।

मिथुन : आत्मसंयत रहें। क्रोध के अतिरेक से बचें। कारोबार में वृद्धि होगी। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। परिवार के साथ किसी दूसरे स्थान पर भी जाना हो सकता है।

कर्क : किसी नए कारोबार की शुरुआत हो सकती है। परिवार का साथ मिलेगा। कारोबार में भागदौड़ अधिक रहेगी। रहन-सहन भी अव्यवस्थित रहेगा।

सिंह : आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे। कारोबार में बदलाव के योग बन रहे हैं। पिता का साथ मिलेगा। किसी दूसरे स्थान पर भी जाना हो सकता है। यात्रा लाभप्रद रहेगी।

कन्या : मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार में वृद्धि हो सकती है। लाभ के अवसर मिलेंगे। सेहत का ध्यान रखें।

तुला : मन परेशान रहेगा। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयास करें। घर-परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। सेहत के प्रति सचेत रहें।

वृश्चिक : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, परंतु मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। शैक्षिक कार्यों में कठिनाई आ सकती है। सचेत रहें। कारोबार में लाभ के अवसर मिलेंगे।

धनु : मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी में बदलाव के साथ तरक्की के अवसर मिलेंगे। आय में बढ़ोतरी होगी। कार्यक्षेत्र में बदलाव भी हो सकता है।

मकर : मन प्रसन्न रहेगा। आत्मविश्वास भी भरपूर रहेगा। किसी नए कारोबार की शुरुआत हो सकती है। भागदौड़ अधिक रहेगी। लाभ के अवसर भी प्राप्त होंगे।

कुंभ : आत्मसयंत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयास करें। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। बौद्धिक कार्यों से आय में वृद्धि हो सकती है। सेहत का ध्यान रखें।

मीन : आत्मविश्वास बहुत रहेगा। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। कारोबार में व्यस्तता बढ़ सकती है। परिवार के किसी बुजुर्ग से धन की प्राप्ति हो सकती है।

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋभुकांत गोस्वामी

30 अप्रैल, गुरुवार, **शक संवत् :** 10, वैशाख, (सौर) 1948 **पंजाब पंचांग :** 17, वैशाख मास प्रविष्टे 2083, **इस्लाम :** 12, जिल्काद, 1447, **विक्रमी संवत :** वैशाख शुक्ल चतुर्दशी तिथि रात्रि 09.13 मिनट तक, चित्रा नक्षत्र रात्रि 02.17 मिनट तक, वज्र योग रात्रि 08.55 मिनट तक पश्चात सिद्धि योग, चन्द्रमा कन्या राशि में दोपहर 01.14 मिनट तक उपरांत तुला राशि। **सूर्य उत्तरायण।** दोपहर 01.30 मिनट से अपराह्न 03 बजे तक राहुकालम्। भद्रा रात्रि 09.13 मिनट से। श्री नृसिंह जयन्ती। श्री छिन्नमस्ता जयन्ती। गुरु अमरदास जयंती।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

हमने काफी हद तक वास्तु के नियमानुसार ही एक घर बनवाया है। फिर भी इस घर में आकर स्वास्थ्य आदि की अत्यधिक समस्याएं चल रही हैं। – सृष्टि, धनबाद

- आपका घर वायव्य मुखी है, जो थोड़ा दिशाओं के कारण विदिशा हो गया है। आपका मुख्य द्वार असुर नामक पद में आता है, जो अत्यंत नकारात्मक द्वार होता है और घर में रहने वालों को बहुत कष्ट देता है। आपने घर में लगभग मध्य में तांबे की तार डाल दी है, यह बहुत बड़ा दोष बन गया है, क्योंकि इसके कारण आपका घर दो भागों में विभाजित हो गया है। सारा वास्तु इसके कारण बदल गया है। इस तार को निकलवाने के अलावा कोई अन्य उपाय नहीं है। इसके लिए विशेषज्ञ की सहायता लें।

वर्ग पहेली : 8314

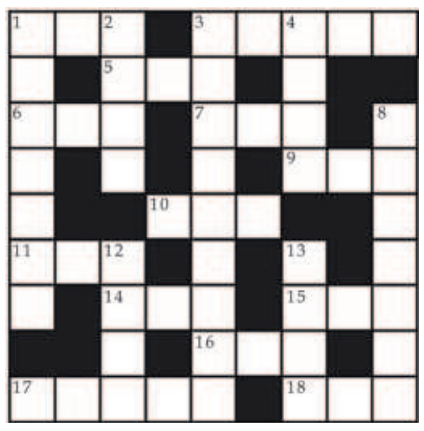

बाएं से दाएं
1. अवस्था; दशा; परिस्थिति; मौजूदा हैसियत (3)
3. अचानक हुए कष्ट से बेचैन होना (5)
5. ज्वाला; रोशनी के लिए तेल से भीगा, डंडे पर बंधा, जलता हुआ कपड़ा (3)
6. अनुचर; आज्ञापालक; चाकर; सेवा उपासना करने वाला; पुजारी; भक्त (3)
7. ऐसा स्थान जहां से तीन रास्ते निकलते हैं; तिरमुहानी (3)
9. मुग्ध होना; लुब्ध होना; सम्मोहित होना (3)
10. नम्र होना; नवना; निहुरना; विनीत होना; नीचे की ओर टेढ़ा होकर लटकना (3)
11. उमंग; हिलोर; तरंग; मौज (3)
14. क्षमतायुक्त; शक्तिशाली; समर्थ (3)
15. करने वाला; कार्यवाहक; कारण; साधन (3)
16. गति; चाल; प्रवाह; संवेग; चलने का ढंग (3)
17. कोई संबंध न रखना; पास न आना; बचना (2,3)
18. नाप लेना; पैमाइश करना; थाह लेना (3)

ऊपर से नीचे
1. अधिकार में न रहना; नियंत्रणहीन होना; वश में न रहना (2,1,4)
2. चमकना; आवेश में आना; क्रुद्ध होना (4)
3. घुट घुट कर मरना; दुर्दशा भोगना (2,2,2,3)
4. अल्पाहारी; परिमित आहार लेने वाला (4)
8. टालमटोल करना; अनसुनी करना; अड़चन पैदा करना (4,3)
12. जायकेदार; मजेदार; झोलदार; शोरबेदार; रसेदार; रसवाला; स्वादिष्ट (4)
13. आवाज देना; बुलाना; ऊंचे स्वर में संबोधन करना (4)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली
(उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहेली : 8313

सुडोकू : 8296

*कठिन

					7			6
				6		7	8	
5					9		3	
	5				8		4	9
6								3
4	2		6				1	
	4		7					5
	1	9		4				
2			9					

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3x3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 8295

3	5	8	2	7	4	9	1	6
7	9	1	6	8	5	3	2	4
6	2	4	1	3	9	7	8	5
2	4	7	3	9	1	5	6	8
1	3	6	8	5	7	2	4	9
5	8	9	4	2	6	1	7	3
4	7	5	9	6	2	8	3	1
8	1	2	5	4	3	6	9	7
9	6	3	7	1	8	4	5	2

चिंतन

रिकॉर्ड मतदान, अब नेताओं पर परफॉर्मेंस का दबाव

पश्चिम बंगाल समेत देश के पांच राज्यों में हुए हालिया चुनावों ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि भारतीय लोकतंत्र केवल एक व्यवस्था नहीं, बल्कि एक जीवंत चेतना है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा मतदान प्रतिशत इस बात का स्पष्ट संकेत है कि जनता अब राजनीति को दूर से देखने वाली भीड़ नहीं, बल्कि फैसले लेने वाली ताकत बन चुकी है। बता दें कि बंगाल के दूसरे चरण में 90 फीसदी मतदान हुआ है। वहीं, पहले चरण में 93 फीसदी से अधिक मतदान हुआ था। जब किसी चुनाव में 90 प्रतिशत के आसपास मतदान दर्ज होता है, तो यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं रहता, बल्कि यह जनादेश की गंभीरता और जनता की मंशा का स्पष्ट संदेश बन जाता है। अब इससे नेताओं पर भी परफॉर्मेंस का दबाव बनेगा कि वे किसी एक समुदाय या विशेष क्षेत्र के लिए नहीं, अपितु सभी के लिए योजना और नीतियां तैयार करें। चूंकि प्रदेश की लगभग पूरी आबादी ने मतदान में भाग लिया है। पश्चिम बंगाल में दोनों चरणों में 90 फीसदी से अधिक मतदान अपने आप में ऐतिहासिक है। यह न केवल राज्य का, बल्कि पूरे देश का एक नया रिकॉर्ड बन गया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड अब तक त्रिपुरा में 91.82% (2013) में दर्ज हुआ था। यह परिघटना बताती है कि मतदाता अब उदासीन नहीं है। वह अपने अधिकार को लेकर सजग है और सत्ता को यह बताने के लिए तैयार है कि उसकी अपेक्षाएं क्या हैं, लेकिन उच्च मतदान प्रतिशत को केवल लोकतंत्र का उत्सव मान लेना एक अधूरा विश्लेषण होगा। बंगाल की राजनीतिक पृष्ठभूमि हमेशा से संघर्ष, ध्रुवीकरण और आरोप-प्रत्यारोप से भरी रही है। इस बार भी हालात अलग नहीं दिखे। एक ओर ममता बनर्जी ने केंद्रीय बलों पर गंभीर आरोप लगाए। यहां तक कहा कि वे एक विशेष पार्टी के हित में काम कर रहे हैं। वहीं, दूसरी ओर भाजपा ने ईवीएम में छेड़छाड़ जैसे आरोपों के जरिए चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। यह स्थिति बताती है कि चुनाव केवल मतदाताओं का उत्सव नहीं, बल्कि राजनीतिक अविश्वास की परीक्षा भी है। ऐसे माहौल में चुनाव आयोग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। आयोग के लिए यह चुनाव किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं है। अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजामों के दावे तभी सार्थक माने जाएंगे, जब मतदान न केवल शांतिपूर्ण, बल्कि पूरी तरह निष्पक्ष भी साबित हो। हालांकि, इस पूरे परिदृश्य में सबसे महत्वपूर्ण संदेश जो उभरकर सामने आता है, वह है जनता का बदला हुआ रुख। अब मतदाता केवल जाति, धर्म या क्षेत्रीय समीकरणों के आधार पर वोट देने तक सीमित नहीं रह गया है। रिकॉर्ड मतदान इस बात का संकेत है कि जनता अब अपने प्रतिनिधियों से जवाबदेही चाहती है। अब चार मई को आने वाले नतीजे यह तय करेंगे कि पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुडुचेरी में सत्ता किसके हाथ जाएगी। असली फैसला तो जनता पहले ही कर चुकी है। वह यह कि अब उसे सिर्फ वादे नहीं, प्रदर्शन चाहिए। अब सरकारें घोषणाओं से नहीं, काम से आंकी जाएंगी। कुल मिलाकर रिकॉर्ड मतदान भारतीय लोकतंत्र की ताकत का प्रमाण है, लेकिन यह नेताओं के लिए एक चेतावनी भी है। यह स्पष्ट संकेत है कि जनता जाग चुकी है और अब वह हर पांच साल में सिर्फ वोट डालकर नहीं, बल्कि अपने फैसले के परिणाम भी देखना चाहती है। इसलिए आने वाली सरकारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि उस भरोसे को बनाए रखना होगा, जो जनता ने रिकॉर्ड मतदान के जरिए उन पर जताया है।

करवट

कुमार प्रशांत

जिनके फोटोग्राफ्स बोलते थे

> हम बहुत कम समय तक एक-दूसरे को जानते रहे। फिर एकदम अलग हो गए। फिर इधर के दिनों में, जब मैं दिल्ली आया तो फिर कुछ मिलना हुआ। इसलिए निजता का मेरा कोई दावा नहीं है। लेकिन 1974 से जो शुरू हुई, वह सौहार्दपूर्ण पहचान बनी रही। मैंने उनसे भी कहा था और आज भी उसे दोहराता हूं कि रघु राय के कैमरे को 1974-77 के दौर में वह संस्कार मिला जिसने उन्हें फोटोग्राफर से कहीं आगे खड़ा कर दिया। अपना कैमरा ले कर जब रघु राय जयप्रकाश नारायण व उनके आंदोलन के क़रीब पहुंचे तब उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि उनका कैमरा यहां से अपना चरित्र बदलने वाला है।

26 अप्रैल 2026 को जब रघु राय ने अपने कैमरे का शटर दबाया होगा, तब उन्हें इल्म हुआ होगा कि उनका कैमरा बंद हो गया है। अब वह न कभी खुलेगा, न कभी बोलेगा ! उनका कैमरा बोलता था। रघु राय के कैमरे में व दूसरों के कैमरे में यही फर्क था। दूसरों का कैमरा बोलता नहीं था, देखता था; रघु राय का कैमरा गूंगा होने को तैयार नहीं था। वह बोलता था। महान कनाडियन कैमराकार यूसुफ कार्श का कैमरा नहीं बोलता था, उनके पोट्रेट बोलते थे। उनके पोट्रेट के पात्रों की आंतरिक विशेषताओं को उनका कैमरा जैसे छू लेता था. वह कहता कुछ नहीं था, हमारे सामने उस व्यक्ति को खड़ा कर देता था। मैंने ऐसा ही कुछ पहली बार पटना की उस मित्र-मंडली में कहा था जिसमें रघु राय भी मौजूद थे। चेहरे पर सदा खिली रहने वाली आत्मीय मुस्कान के साथ वे मुझे सुन रहे थे : रघु राय के फोटोग्राफ्स बोलते हैं इसलिए हमें उनके पास ठहरना पड़ता है ताकि उन्हें सुन सकें; रघु राय के फोटोग्राफ्स दौड़ते हैं इसलिए हमें उनके साथ तेज दौड़ लगानी पड़ती है ताकि कहीं पीछे न छूट जाएं ! मुझे कई बार लगा है कि उनके फोटोग्राफ्स की एक श्रृंखला देखते-देखते सांस फूलने लगती है।

मैं आज कहना चाहता हूं कि रघु राय हमारे दौर के सबसे तेज रफ्तार कैमराकार थे जो गति, शब्द व चित्र, तीनों का अप्रतिम संतुलन साध पाते थे। मैं यह आज इसलिए कहना चाहता हूं, क्योंकि रघु राय अब नहीं हैं। अब वह आंख नहीं है जो कैमरे से जुड़ कर वह संसार उजागर कर जाती थी जिसे देखते हुए भी हम देख नहीं पाते थे। उनकी आंखों में कैमरा लगा था और उस कैमरे में महाभारतवाले संजय की आंख लगी थी। कई लोग कहते रहे, उनकी विदाई-लेखों में भी लिखा जा रहा है कि वे आलादर्जे के न्यूज-फोटोग्राफर थे। रघु राय के परिचय में जब ऐसा कहा जाता है तब मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई जवाहरलाल नेहरू के परिचय में कहे कि वे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। यह परिचय सच है लेकिन जवाहरलालजी का इससे बौना परिचय दूसरा हो नहीं सकता है। वे बहुत कुछ और भी थे जिसके साथ भारत के प्रधानमंत्री भी थे। रघु राय बहुत कुछ और भी थे जिसके साथ न्यूज-फोटोग्राफर भी थे।

हम बहुत कम समय तक एक-दूसरे को जानते रहे। फिर एकदम अलग हो गए। फिर इधर के दिनों में, जब मैं दिल्ली आया तो फिर कुछ मिलना हुआ। इसलिए निजता का मेरा कोई दावा नहीं है। लेकिन 1974 से जो शुरू हुई, वह सौहार्दपूर्ण पहचान बनी रही। मैंने उनसे भी कहा था और आज भी उसे दोहराता हूं कि रघु राय के कैमरे को 1974-77 के दौर में वह संस्कार मिला जिसने उन्हें फोटोग्राफर से कहीं आगे खड़ा कर दिया। अपना कैमरा ले कर जब रघु राय जयप्रकाश नारायण व उनके आंदोलन के क़रीब पहुंचे तब उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि उनका कैमरा यहां से अपना चरित्र बदलने वाला है। मुझे पता नहीं है कि रघु राय 1974 से पहले जयप्रकाश से परिचित थे या नहीं। कभी पूछा नहीं, कभी `ऐसी बात निकली नहीं। लेकिन सिताबदियारा की वह रात मुझे खूब याद है जब दिन भर की तूफानी सभाओं व सार्वजनिक जयकारों-हाहाकारों से निकल कर हम देर शाम जयप्रकाश के पैतृक गांव सिताबदियारा पहुंचे थे। अपना वह गांव और

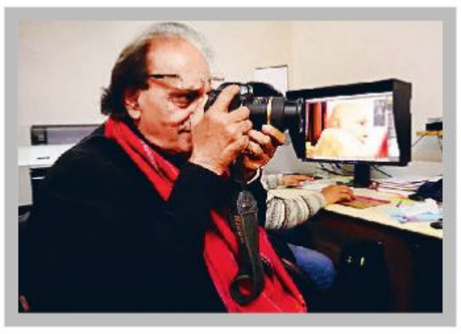

अपना वह खपड़ैल मकान जयप्रकाश को बहुत प्यारा था। उसकी उष्मा में वे विभोर हो कर रहते थे-चाहे जितना रह सकें! उस शाम बेहद थके होने के बाद भी वे वैसे ही मगन-मन थे। वहां जगह भी कम थी, सुविधाएं तो और भी कम; और उसमें औचक आ पहुंचे 10-15 शहरी मेहमान! सबकी व्यवस्था थी। सबको उनकी जगह पहुंचा कर, खाना आदि करवा कर थोड़ी राहत मिली। जयप्रकाश भी थकान आदि से निबट कर थोड़े स्थिर हुए तो सब मेहमानों की व्यवस्था आदि की जानकारी ली। बिस्तर, मच्छरदानी, पीने का पानी, बाथरूम सब पूछा : 'इनमें से कुछ होंगे जिन्हें सोने से पहले चाय-कॉपी की जरूरत होती होगी। वह सब पूछा न ?' पूछा तो था लेकिन बहुत आग्रह से नहीं, इसलिए जवाब में थोड़ा संशय था...रात भी ज्यादा हो रही है, सोने वाले सो भी गए होंगे व्यवस्थापकों का जवाब पूरा भी नहीं हुआ था कि जयप्रकाश बिस्तर से नीचे उतरे और बोले : ' चलें, जरा देख लूं !'

मेहमानों में संकोच भरी खलबली हुई। इतनी रात गए, थके जयप्रकाश एक-एक के बिस्तरे तक पहुंचे, बड़ी आत्मीयता से जो पूछना-बताना था, वह सब किया- यहां सुविधाएं कम हैं, परेशानी होगी आपको, सुबह कितने बजे उठते हैं, नहाने का गर्म पानी यहां मिल जाएगा, चाय कितने बजे लेंगे, चाय के साथ क्या लेंगे मैं देख रहा था कि रघु राय सिकुड़ते जा रहे थे। जिसके पीछे कैमरा ले कर वे सुबह से भाग रहे थे, वह अब उनके कैमरे की जद से बाहर, उनके सामने खड़ा था, और उन्हें अपने कैमरे में बंद कर रहा था।

'आपने रोका क्यों नहीं दिन भर मैंने इस बूढ़े आदमी को जवानों को मात देने वाली एनर्जी से काम करते देखा है अब हमारी बेहूदा-सी जरूरतों की चिंता में रघु राय को सूझ नहीं रहा था कि वे कैसे, क्या कहें शब्द बता नहीं पा रहे थे कि वे कैसा महसूस कर रहे थे फिर हम देर रात तक सिताबदियारा के कच्चे रास्तों पर हल्के कदमों व दबी आवाज में बात करते घूमते रहे वे एक इवेंट कवर करने आए थे, और यहां मिला उन्हें एक ऐसा व्यक्ति जो इतिहास समेटता हुआ, इतिहास बदल रहा था आप देखिए न, न यह कैमरा मेरा बनाया है, न मेरे कैमरे के सामने जो घट रहा है वह मेरा रचा है सब मुझे बना-बनाया मिला है। मैं कर तो इतना ही रहा हूं न कि शटर दबा रहा हूं रघु राय कुछ और कहते कि मैंने टोका : शटर तो मैं भी दबा सकता हूं लेकिन उसमें से रघु राय का फोटो बनेगा नहीं, क्योंकि कहां, कब व कैसे शटर दबाना है यह न मशीन को मालूम है, न मशीन के सामने घटती घटनाओं को यह तो रघु राय को ही पता है कला व कलाकार के बीच का यह रिश्ता ही अंतिम सत्य है ऐसी कितनी ही बातें उस रात हुईं जयप्रकाश कर क्या रहे हैं, लोकतंत्र के विकास में इस आंदोलन का रोल क्या है, दमन के सामने बहादुरी से खड़े इन नौजवानों की प्रेरणा क्या है जैसी कितनी ही बातें हम कर गए रघु राय तब अपने फोटो का नया एंगल खोज रहे थे। जिसे हम न्यूज-फोटोग्राफी कह कर निकल जाते हैं और जो न्यूज के साथ ही दम तोड़ जाती है, रघु राय उसके पार जाते थे क्योंकि वे क्षण को नहीं, वक्त को दर्ज करने वाले कैमराकार थे।

बिहार आंदोलन में गति व उमंग का विस्फोट हुआ था। रघु राय उसे पकड़ सके थे, क्योंकि वे उसे समझ सके थे। उनका कैमरा साक्षी-भाव नहीं रखता था, वह भागीदार बन सका था। बिहार आंदोलन के उनके फोटो का संकलन 'बिहार शोज़ द वे' आप देखें तो समझ सकेंगे कि वे लिखे शब्दों व विवरणों को व्यर्थ-सा बना देते हैं, क्योंकि वे सारे फोटोग्राफ्स बोलते भी हैं, भागते भी हैं। लेकिन आपको एकदम अलग रघु राय मिलते हैं जब आप मदर टेरेसा के पास उन्हें देखते हैं। उनका कैमरा वहां ध्यान करता मिलता है : निःशब्द प्रार्थना ! रूपाकार नहीं, करुणा ही आकार ले लेती है। संगीतकारों की उनकी श्रृंखला मुझे इसलिए बहुत प्रिय है कि कैमरे को उस तरह गाते कभी सुना नहीं था। इंदिरा गांधी का उनका अलबम एकदम अलग भाषा में बोलता है-सत्ता की धमक-चमक व आतंक का रस वहां हर ओर बिखरा मिलता है। वह सारा कुछ जो काल की हथेली पर उन्होंने बिखरा रखा था, अब सिमट चुका है। उसमें कुछ नया जोड़ने वाली आंख नहीं रही। कैमरा भी है, विषय भी हैं लेकिन रघु राय नहीं हैं। वह वादा भी अब कभी पूरा नहीं होगा जो जयपुर में गांधी-वाटिका बनाते समय उन्होंने मुझसे किया था : कुमार, आपकी गांधी-वाटिका के लिए मैंने कुछ अलग सोच रखा है मैं वह आपको दूंगा वह वाटिका भी अब श्रीहीन हो चुकी है।

बलिदान दिवस

आचार्य दीपचन्द भारद्वाज

अफ़गानों का काल बने सरदार हरि सिंह नलवा

भारतवर्ष की धरा का इतिहास पराक्रमी वीर योद्धाओं के त्याग, वीरता और बलिदान की गाथाओं से परिपूर्ण है। हमारे यहां ऐसे रणबांकुरे हुए हैं जिनका नाम सुनने मात्र से ही शत्रु कांप जाते थे। सरदार हरि सिंह नलवा भारतीय इतिहास के उन अद्वितीय योद्धाओं में गिने जाते हैं, जिनकी वीरता और पराक्रम के किस्से आज भी हमारे हृदय में प्रेरणा का संचार करते हैं। सन् 1791 को पंजाब के गुजरांवाला में जन्मे हरि सिंह नलवा बाल्यकाल से ही साहसी, निर्भीक और प्रतिभाशाली थे। इनके पिता गुरदयाल सिंह उप्पल का निधन तब हो गया था, जब वह मात्र 7 वर्ष के थे। विकट परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपने साहस, युद्ध कौशल के बल पर अपनी पहचान अर्जित की। बचपन से ही युद्ध कला में प्रवीण थे। बसंत पंचमी के अवसर पर एक बार 1805 में महाराजा रणजीत सिंह ने एक प्रतियोगिता का आयोजन करवाया। हरि

सिंह नलवा भी उस प्रतियोगिता में अपना कौशल दिखाने पहुंचे। हरि सिंह ने उस प्रतियोगिता में भाला, तीरंदाजी, घुड़सवारी में अद्भुत प्रदर्शन किया जिससे प्रभावित होकर महाराज रणजीत सिंह ने उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लिया। धीरे-धीरे महाराणा रणजीत सिंह के वे विश्वास पात्र बन गए तथा एक कुशल योद्धा और उत्कृष्ट रणनीतिकार के रूप में स्थापित हुए। एक बार महाराजा रणजीत सिंह जंगल में अपने सैनिकों के साथ शिकार करने गए और उनके साथ हरि सिंह नलवा भी थे। तभी अचानक एक बाघ ने महाराजा पर हमला कर दिया। सभी सैनिक डर गए, तभी हरि सिंह आगे निकल कर आए और शेर से भिड़ गए तथा उसके जबड़े को अपने दोनों हाथों से चीर दिया। हरि सिंह से प्रभावित होकर रणजीत सिंह ने कहा कि तुम तो राजा नल जैसे वीर बहादुर हो। इसी घटना के बाद उन्हें 'नलवा' की उपाधि मिली, जिसका अर्थ है बाघ जैसा वीर । वे ऐसे धुरंधर योद्धा थे जिसकी तुलना अंग्रेज नेपोलियन से करते थे।

हरि सिंह केवल नाम के ही सिंह नहीं थे, बल्कि उनके पराक्रम और शौर्य ने पूरे अफगानिस्तान को हिला कर रख दिया था। यह उस कालखंड की बात है जब अफगानिस्तान के लड़ाकों से भारत डरा करता था। सबसे पहले महाराजा रणजीत सिंह ने इनको 800 घुड़सवारों की सेना का सेनानायक बनाया। हरि सिंह ने बीस से अधिक युद्धों में महाराजा रणजीत सिंह की सेना का कुशल नेतृत्व किया। 1807 से 1837 तक हरि सिंह ने अफगानों के खिलाफ कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और विजय प्राप्त करके सिख साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान की। नलवा ने अफगानिस्तान पर चढ़ाई करके उनकी राजधानी काबुल तक छीन ली थी। अपनी कूटनीति और पराक्रम के बल पर खैबर दर्रे तक अफ़गानों को पीछे धकेल दिया था। यही खैबर दर्रा सदियों से विदेशी अफगान आक्रमणकारियों का प्रमुख मार्ग रहा था। इस प्रकार हरि सिंह ने भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने का सराहनीय कार्य किया। महाराजा रणजीत सिंह ने हरी सिंह नलवा को कश्मीर और पेशावर का गवर्नर नियुक्त किया, जो उनकी प्रशासनिक क्षमता का प्रमाण है। सिख साम्राज्य के विस्तार और उसको सुरक्षित बनाने में हरि सिंह नलवा का योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। वे ऐसे अजेय योद्धा थे, जिनके पराक्रम का आतंक शत्रुओं के मानस पटल पर भी छाया हुआ था। हरि सिंह ने ही जमरूद के महत्वपूर्ण किले का निर्माण करवाया था। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि - 'अफगान माताएं अपने बच्चों के रोने पर उन्हें चुप कराने के लिए कहा करती थी कि चुप हो जा, वरना नलवा आ जाएगा'। यह केवल लोककथा नहीं, बल्कि उनके अद्भुत युद्ध कौशल, साहस और निडरता का जीवंत प्रमाण है। उनकी वीरता और युद्ध कौशल की चर्चाएं चारों तरफ फैली हुई थी। युद्ध के मैदान में इस वीर योद्धा नलवा को देखते ही शत्रु मैदान छोड़ जाया करते थे। 1837 में जमरूद के युद्ध के दौरान उनकी वीरता अपने चरम पर थी। तभी अफगान सेना ने जमरूद के किले पर अचानक आक्रमण कर दिया। सीमित संसाधनों और कम सैनिकों के साथ भी हरि सिंह ने अफगान सेना का डटकर सामना किया। शारीरिक रूप से अस्वस्थ होते हुए भी हरि सिंह ने निर्भीकता से इस युद्ध को लड़ा। अंततः यह वीर योद्धा जमरूद के इस युद्ध में 30 अप्रैल 1837 को वीरगति को प्राप्त हुआ। सरदार हरि सिंह नलवा की तुलना भारत के श्रेष्ठ सेना नायकों में की जाती है। भारत के प्रति हरि सिंह नलवा की प्रतिबद्धता, त्याग, बलिदान और कर्तव्य निष्ठा इतिहास में सदैव अमर रहेगी।

(लेखक आध्यात्मिक चिंतक हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

हम जो भी करेंगे वह कर्म है

संकलित

दर्शन

'इगोसेंट्रिक' कर्म को वे कर्म कहते हैं। ऐसे कर्म को, जिसमें कर्ता मौजूद है। जिसमें कर्ता यह विचार करके ही कर रहा है कि करने वाला मैं हूं। जब तक मैं करने वाला हूं, तब तक हम जो भी करेंगे, वह कर्म है। अगर मैं संन्यास ले रहा हूं, तो संन्यास एक कर्म हो गया। अगर मैं त्याग कर रहा हूं, तो त्याग एक कर्म हो गया। अकर्म का मतलब ठीक उलटा है। अकर्म का मतलब है ऐसा कर्म, जिसमें कर्ता नहीं है। जिसमें मैं कर रहा हूं, ऐसा कोई बिंदु नहीं है। ऐसा कोई केंद्र नहीं है, जहां से यह भाव उठता है कि मैं कर रहा हूं। अगर मैं कर रहा हूं, यह खो जाए, तो सभी कर्म अकर्म है। कर्ता खो जाए तो सभी कर्म अकर्म है। इसलिए कृष्ण का कोई कर्म, कर्म नहीं है, सभी अकर्म हैं। कर्म और अकर्म के बीच में विकर्म की जगह है। विकर्म का अर्थ है, विशेष कर्म। विशेष कर्म किसे कहते हैं कृष्ण? जहां न कर्ता है, और न कर्म। फिर भी चीजें तो होंगी। फिर भी चीजें तो होंगी ही। आदमी श्वास तो लेगा ही। न कर्म है, न कर्ता है। श्वास तो लेगा ही। श्वास कर्म तो है ही। खून तो गति करेगा ही शरीर में। भोजन तो पचेगा ही। ये कहां पड़ेंगे? ये विकर्म हैं। ये मध्य में हैं। यहां न कर्ता है, न कर्म है। साधारण मनुष्य कर्म में है, संन्यासी अकर्म में है, परमात्मा विकर्म में है। वहां न कोई कर्ता है, न कोई कर्म है। वहां चीजें ऐसी ही हो रही हैं, जैसे श्वास चलती है। वहां चीजें बस हो रही हैं। यह कर्म योग का तत्व है । जो विकर्म को समझ लेगा, वह अकर्म में उतर जाएगा। कर्म हमारी स्थिति है, जैसे हम जी रहे हैं।

धैर्य से काम लेने में ही समझदारी है

संकलित

प्रेरणा

एक बार महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। उन दिनों कोई वाहन नहीं हुआ करते थे सो लोग पैदल ही मीलों की यात्रा करते थे। ऐसे ही गांव में घूमते हुए काफ़ी देर हो गयी थी। बुद्ध जी को काफ़ी प्यास लगी थी। उन्होंने अपने एक शिष्य को गांव से पानी लाने की आज्ञा दी। जब वह शिष्य गांव में अंदर गया तो उसने देखा वहां एक नदी थी जहां बहुत सारे लोग कपड़े धो रहे थे कुछ लोग नहा रहे थे तो नदी का पानी काफ़ी गंदा सा दिख रहा था। शिष्य को लगा कि गुरु जी के लिए ऐसा गंदा पानी ले जाना ठीक नहीं होगा, ये सोचकर वह वापस आ गया। महात्मा बुद्ध को बहुत प्यास लगी थी इसीलिए उन्होंने फिर से दूसरे शिष्य को पानी लाने भेजा। कुछ देर बाद वह शिष्य लौटा और पानी ले आया। महात्मा बुद्ध ने शिष्य से पूछा कि नदी का पानी तो गंदा था फिर तुम साफ पानी कैसे ले आए। शिष्य बोला की प्रभु वहां नदी का पानी वास्तव में गंदा था लेकिन लोगों के जाने के बाद मैंने कुछ देर इंतजार किया। और कुछ देर बाद मिट्टी नीचे बैठ गयी और साफ पानी उपर आ गया। बुद्ध यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और बाकी शिष्यों को भी सीख दी कि हमारा ये जो जीवन है यह पानी की तरह है। जब तक हमारे कर्म अच्छे हैं तब तक सब कुछ शुद्ध है, लेकिन जीवन में कई बार दुख और समस्या भी आते हैं जिससे जीवन रूपी पानी गंदा लगने लगता है। कुछ लोग पहले वाले शिष्य की तरह बुराई को देख कर घबरा जाते हैं और मुसीबत देखकर वापस लौट जाते हैं, वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते।

अंतर्मन

आज की पाती

तरसना न पड़ जाए जल की एक-एक बूंद के लिए

हाल ही में केंद्रीय जल आयोग ने हमें एक बहुत बड़ी चिंता में डालने वाला आंकड़ा देश के विभिन्न राज्यों के जलाशयों में घटते पानी को लेकर पेश किया है। इस आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश के लगभग 166 मुख्य जलाशयों में मात्र 41 प्रतिशत के आसपास पानी बचा है। पश्चिमी भारत, हिमाचल और उत्तराखंड में स्थिति बेहद खराब बताई गई है, यहां तो जलाशयों का जल स्तर 90 प्रतिशत के नीचे बताया गया है। केंद्रीय जल आयोग के इन चिंताजनक आंकड़ों पर आज से नहीं, बल्कि अभी से गंभीरता नहीं दिखाई गई तो देश के बहुत से राज्यों में जल संकट इस कद्र गहरा सकता है कि वहां पानी की एक-एक बूंद को तरसना पड़ सकता है। जल को अगर इसी तरह प्रदूषित व बर्बाद किया जाता रहा, तो संकट पैदा होगा। - *राजेश सोनी, भाटापारा*

ट्रेंड

सब कुछ महंगा होगा

चुनाव की राहत खत्म, महंगाई की मार अब शुरू होने वाली है! सावधान हो जाइए - पेट्रोल, डीजल, सब कुछ महंगा हो जाएगा। जब तेल सस्ता था, मोदी सरकार ने मुनाफा कमाया। अब जब यह महंगा हो गया है, तो इसका बोझ आप पर पड़ेगा।

-**राहुल गांधी,** सांसद, कांग्रेस

विशेषाधिकार की प्रवृत्ति

जब महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करने का समय आया, तो महिला-विरोधी विपक्ष ने गरिमा और न्याय की बजाय विलंब और व्यवधान को चुना। यह संकोच नहीं है। यह विशेषाधिकार को बनाए रखने की प्रवृत्ति है।

-**रेखा गुप्ता,** सीएम, नई दिल्ली

दोहरी विकास प्रणाली

हमारी दोहरी विकास प्रणाली वाली सरकार महिलाओं की उन्नति के लिए निरंतर प्रयासरत है। हम न केवल आर्थिक स्वतंत्रता के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं, बल्कि शिक्षा और रोजगार अवसरों में आने वाली बाधाओं को भी दूर कर रहे हैं।

-**मोहन चरण माझी,** सीएम, ओडिशा

10 गुना अधिक सीटें

गुजरात में हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, उन्हें जेल भेजा गया, लेकिन फिर भी उन्होंने दृढ़ता से चुनाव लड़ा। आम आदमी पार्टी ने पिछली बार की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक सीटें जीती हैं।

-**अरविंद केजरीवाल,** पूर्व सीएम, नई दिल्ली

करंट अफेयर

श्रीलंका के चेम्मानी में फिर शुरू होगी सामूहिक कब्रों की खुदाई

श्रीलंका की एक अदालत ने जाफना के बाहरी इलाके चेम्मानी में स्थित एक सामूहिक कब्र की खुदाई का काम फिर से शुरू करने का आदेश दिया है, जो पहली बार 1990 के दशक में लिट्टे संघर्ष के दौरान चर्चा में आयी थी और इसकी खुदाई का काम सात महीने पहले रोक दिया गया था। न्याय मंत्रालय द्वारा धनराशि फिर से आवंटित करने में देरी के कारण उत्तरी प्रांत के चेम्मानी में खुदाई का काम पिछले साल सितंबर में रुक गया था। जाफना मजिस्ट्रेट कोर्ट को मंगलवार को बताया गया कि 21 लाख श्रीलंकाई रुपये (एलकेआर) का आवंटन उपलब्ध करा दिया गया है ताकि काम फिर से शुरू किया जा सके। अदालत ने यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली और रोमानिया के राजनयिक प्रतिनिधियों को खुदाई स्थल पर निरीक्षण के लिए उपस्थित रहने की अनुमति दी। खुदाई कार्य के 45 दिनों के बाद जब दूसरे चरण का काम रोक दिया गया तब तक 240 कंकाल अवशेष निकाले जा चुके थे। खुदाई में कंकालों के अलावा, 14 हड्डियों का ढेर और शिशुओं के लिए दूध की बोतलें, एक गुड़िया, खिलौने और बच्चों के थैले तथा जूते जैसी वस्तुएं भी मिलीं।

ऑफ बीट

रोबोट मैराथन दौड़ सकते हैं टेबल टेनिस खेल सकते हैं

एक 'ह्यूमनॉइड' रोबोट ने हाल ही में हाफ मैराथन दौड़कर और मानव विश्व रिकॉर्ड को पीछे छोड़कर दुनिया भर में सुर्खियां बटोरीं। लगभग उसी समय, एआई-संचालित एक रोबोट ने टेबल टेनिस में एक शीर्ष खिलाड़ी को भी हरा दिया। रोबोट को खेल सिखाने की प्रक्रिया मानव खिलाड़ियों से पूरी तरह अलग होती है। रोबोट को 'सिमुलेशन', 'डेटा' और नियंत्रण 'एल्गोरिदम' के जरिए प्रशिक्षित किया जाता है। इंजीनियर वर्चुअल वातावरण तैयार करते हैं, जहां रोबोट लाखों बार अभ्यास कर सकते हैं। वे वस्तुओं को ट्रैक करना, गति का अनुमान लगाना और शरीर का समन्वय करना सीखते हैं। तेज गति वाले खेल जैसे टेबल टेनिस में यह चुनौती और कठिन हो जाती है, जहां रोबोट को गेंद की दिशा का अनुमान लगाकर कुछ ही क्षणों में सटीक प्रतिक्रिया देनी होती है। इसके लिए कंप्यूटर विजन, मशीन लर्निंग और रीयल-टाइम कंट्रोल का घनिष्ठ समन्वय जरूरी है। हाल के वर्षों में सिम-टू-रियल तकनीक ने इस क्षेत्र में प्रगति को काफी तेज किया है जिसमें 'सिमुलेशन' में सीखी गई क्षमताओं को वास्तविकता में लागू किया जाता है। रोबोट बास्केटबॉल और फुटबॉल जैसे खेलों में भी अब केवल गेंद को पहचानने तक सीमित नहीं हैं।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

मुख्यमंत्री सैनी और प्रदेश अध्यक्ष बड़ौली ने नगर निकाय चुनाव 2026 का संकल्प पत्र जारी किया

यह संकल्प पत्र शहर के संतुलित विकास का रोडमैप है : मुख्यमंत्री नायब

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहन लाल बड़ौली ने बुधवार को भाजपा के प्रदेश कार्यालय पंचकमल में पंचकूला, अंबाला, सोनीपत, रेवाड़ी, सांपला और उकलाना में होने वाले नगर निकाय, नगरपरिषद, नगरपालिका चुनाव 2026 के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र में 21 प्रमुख वादे किए गए हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने एक-एक वादे को 100 प्रतिशत पूरा करने का भरोसा दिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कांग्रेस व अन्य दलों से आए वरिष्ठ नेताओं, पूर्व विधायक और पूर्व मंत्रियों और सरपंचों को उनके 200 से अधिक समर्थकों के साथ पार्टी का पटका पहनाकर भाजपा में शामिल किया।

नगर निकाय चुनाव के संकल्प पत्र विमोचन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भाजपा के लिए संकल्प पत्र सिर्फ घोषणा नहीं, बल्कि जनता के प्रति जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र में जनभावना होती है, संकल्प पत्र हमारे लिए भगवान का रूप है और इसमें किए गए एक-एक वादे को पूरा करना हमारी सरकार का दायित्व है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह संकल्प पत्र उस विश्वास का प्रतीक है जो हरियाणा की जनता ने बार-बार भाजपा पर जताया है। भाजपा का संकल्प पत्र प्रदेश के संतुलित विकास का रोडमैप है। संकल्प पत्र के हर वादे को पूरा करना हमारी सरकार का दायित्व है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 2024 के विधानसभा चुनाव में किए गए 217 संकल्पों में से हमारी सरकार ने 63 वादो को पूरा किया है, जबकि बचे हुए संकल्पों पर तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि पांच वर्षों में हमारी सरकार सभी वादे पूरे करेगी।

हर संकल्प 100 प्रतिशत पूरा होगा : मोहन लाल

हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि निकाय चुनाव लोकतंत्र का महत्वपूर्ण पर्व है और भाजपा का उद्देश्य अपने संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू करना है। उन्होंने कहा कि पार्टी का विजन स्पष्ट है और संकल्प पत्र उसी सोच का प्रतिबिंब है, जिसे जमीन पर उतारने का कार्य नायब सैनी सरकार कर रही है। बड़ौली ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान जारी संकल्प पत्र के 63 वादों को सरकार पूरा कर चुकी है, जबकि शेष वादों को भी जल्द ही पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 10 मई को तीन मेयर, एक परिषद और तीन नगरपालिकाओं के चुनाव में जनता का विश्वास भाजपा के साथ है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि संकल्प पत्र के हर वादे को पूरी तरह लागू किया जाएगा।

इन वरिष्ठ नेताओं और सरपंचों ने जताई भाजपा में आस्था

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री राजकुमार वाल्मिकी, तिगांव विधानसभा से तीन बार चुनाव लड़ चुके गिरीराज शर्मा, हिसार से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयसिंह बिश्नोई, भिवानी से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगदीश मंडोलीवाल, रोहतक से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय परमार, गुरुग्राम से बसपा के वरिष्ठ नेता रहे श्याम लाल और पंचकूला हरियाणा बैरागी सभा के अध्यक्ष शिव पंवार ने भाजपा की सदस्यता ली है।

आईएमटी के लिए किसानों ने सरकार द्वारा तय दरों पर भूमि देने पर जताई सहमति

नारायणगढ़ में स्थापित होगा आईएमटी, सैनी से मिले किसान

> आईएमटी स्थापना की प्रक्रिया शुरू होने पर किसानों ने मुख्यमंत्री का मिठाई खिलाकर जताया आभार

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

हरियाणा में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने नारायणगढ़ में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) स्थापित करने का निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार के अनुसार इस पहल से न केवल क्षेत्र के समग्र विकास को गति मिलेगी, बल्कि प्रदेश को औद्योगिक दृष्टि से और अधिक सशक्त बनाने में भी मदद मिलेगी। इस संबंध में बुधवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से नारायणगढ़ क्षेत्र के किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की और बैठक में हिस्सा लिया।

आईएमटी के लिए किसानों से भूमि की दरों में संबंध में विस्तार से चर्चा की गई और किसानों ने सरकार द्वारा तय की गई दरों पर सहमति जताई। इससे आईएमटी के लिए नारायणगढ़ में लगभग 450 एकड़ भूमि उपलब्ध होगी। आईएमटी स्थापना की प्रक्रिया प्रारंभ होने पर किसानों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए उनका मुंह मीठा कर स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने किसानों के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि यह कदम क्षेत्र के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंबाला में पहले से ही आईएमटी विकसित करने का कार्य तेज गति से चल रहा है। अब नारायणगढ़ में भी आईएमटी विकसित होने से इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। गुरुग्राम की तर्ज पर अंबाला क्षेत्र को भी आधुनिक और विकसित औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।

पुलिस कर्मियों को कैपेसिटी बिल्डिंग का दिया जाएगा प्रशिक्षण

अपराधिक गतिविधियों रोकने के लिए पुलिस को नवीनतम तकनीकी से युक्त किया जाएगाः नायब

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विजन 2047 के तहत सेवा, पुलिस एवं जेल विभाग द्वारा बनाए गए शार्ट टर्म एक्शन प्लान रोड़मैप की विस्तार से समीक्षा की और उन्हें इसमें ओर बेहतर बनाने के सुझाव दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा विजन 2047 में साइबर क्राइम को पूर्ण रूप से रोकने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किया जाएगा। रात्रि के समय कार्य करने वाली महिलाओं को घर तक छोड़ने के कार्य के लिए योजना बनाई जाए। इसके लिए महिलाएं पोर्टल के माध्यम से पुलिस को अवगत करवाएंगी। क्राइम पर अंकुश लगाने और अपराध की दर कम लाने के लिए वृहद स्तर पर कार्य किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉयल 112 सुविधा को पुख्ता किया जाएगा और नए वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि डिजिटल अपराध पर अंकुश लगाने के लिए क्राईम सेल में बैंक कर्मी बैठे, जब भी उनके पास अपराध की कॉल आती है तो संबंधित बैंक के खाता को तुरंत बंद कर दिया जाए जिससे अपराध पर अंकुश लगेगा है। बाल सुरक्षा पर विशेष ध्यान देकर इसमें जागरूकता अभियान के साथ कांउसलर भी नियुक्त किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अपराधिक गतिविधियों पर काबू पाने के लिए पुलिस को नवीनतम तकनीकी से युक्त होना चाहिए। पुलिस को जनता का मित्र बनकर कार्य करना है।

पंजाब के धानक समाज ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिलकर बताई अपनी समस्याएं

पंजाब में भाजपा सरकार बनने पर आमजन को देंगे हरियाणा जैसा सुशासनः नायब सिंह सैनी

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंजाब में भाजपा सरकार बनने के बाद वहां के लोगों को हरियाणा की तरह सुशासन मिलेगा। हरियाणा की तरह ही पंजाब के वंचित वर्ग को भी प्लाट, मकान, बच्चों को शिक्षा, छात्रवृत्ति व इलाज सहित सभी सुविधाएं मिलेंगी। सैनी ने यह बात अपने आवास 'संत कबीर कुटीर' में पंजाब के विभिन्न जिलों से आए धानक समाज के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करते हुए कही। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल के आग्रह पर 30 जून को संत कबीर दास जी के प्रकट दिवस पर पंजाब में वंचित अनुसूचित जाति (डीएससी समाज) द्वारा आयोजित किए जाने वाले समारोह में आने का न्यौता भी स्वीकार किया। इस अवसर पर पंजाब में लोकसभा का चुनाव लड़े मदनलाल खटक, मुख्यमंत्री के ओएसडी भारत भूषण भारती व महेंद्र सिंह सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। पंजाब में धानक समाज के अध्यक्ष सतीश खुंडिया ने समाज की समस्याएं बताते हुए कहा कि समाज के पढ़े-लिखे युवकों को रोजगार नहीं मिल रहा है और वे मंडियों में बोरियां ढोने को मजबूर हैं।

कॉरपोरेट बोर्डरूम को जलवायु जोखिमों को अपने निर्णयों में शामिल करना चाहिए

भारत के योजना निर्माण के तरीके को बदलने का दमखम रखता 'क्रेविस' : पीयूष गोयल

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को जलवायु परिवर्तन के तेजी से बढ़ते खतरे के बीच ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (सीईईडब्ल्यू) द्वारा बनाए गए स्वदेशी 'क्लाइमेट रेजिलिएंस एनालिटिक्स एंड विजुअलाइजेशन इंटेलिजेंस सिस्टम (क्रेविस)' को लांच किया है। जिसकी मदद से लगातार गर्म होती दुनिया में भारत के लिए अपनी योजनाओं को बनाना संभव हो सकेगा क्रेविस कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) पर आधारित एक प्लेटफार्म है। जो उपयोगकर्ता को पूछे गए प्रश्नों को लेकर सटीक और स्त्रोतों पर आधारित जानकारी देता है। इसे रोहिणी नीलेकणी फिलैंथ्रोपीज, एचएसबीसी फाउंडेशन, स्पेक्ट्रम इंपैक्ट, इंडिया क्लाइमेट कोलैबोरेटिव और रेनमैटर फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। वहीं, इस कार्यक्रम को 'जलवायु परिवर्तन के साथ लचीलापन बढ़ाना' जैसे विषय के साथ एक संवाद का नाम दिया गया था। जिसके केंद्र में 'विकसित भारत 2047 का लक्ष्य था।

भारत की आज की हकीकत जलवायु परिवर्तन

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कार्यक्रम के दौरान दिए अपने संबोधन में कहा कि तापमान में होती बढ़ोतरी, गर्म दिनों की बढ़ती संख्या और भारी बारिश की लगातार होती घटनाएं ये साफ संकेत देती हैं कि जलवायु परिवर्तन भारत के लिए मौजूदा समय की वास्तविकता है। जो हमारी अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित कर रही है। उन्होंने बीते बुधवार की रात का उदाहरण देते हुए कहा कि यह अप्रैल के महीने की सबसे गर्म रातों में से एक महसूस हुई है। रात के समय में गर्मी से मानव शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्योंकि यह सूर्यास्त के बाद भी शरीर को गर्मी से छुटकारा पाने से रोकती हैं। प्रत्यक्ष रूप से जिसका प्रभाव श्रमिकों की उत्पादकता, बुनियादी ढांचे की क्षमता और व्यापक आर्थिक लचीलेपन पर पड़ता है। उन्होंने उद्योग जगत और उसमें भी कॉरपोरेट बोर्डरूम को जलवायु जोखिमों को अपने जरूरी निर्णयों में शामिल करने की अपील की है। गोयल ने स्पष्ट किया कि बीते एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने जलवायु कार्रवाई को केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक आर्थिक रूप से व्यवहार्य योजना बनाने की दिशा में काम किया है।

डीपीआई में एक अहम कड़ी क्रेविस

उन्होंने यह भी कहा कि एआई द्वारा संचालित क्रेविस प्लेटफार्म सार्वजनिक जलवायु सूचनाओं के क्षेत्र में दुनियाभर के लिए भारत के लिए एक अनूठी पेशकश साबित हो सकता है। यह देश के बढ़ते डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जिसने पहले ही यूपीआई, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) और वैक्सीन मैत्री जैसी सफलताओं को देखा है। इसके अलावा मुझे उम्मीद है कि कंपनियां निवेश के मार्गदर्शन, जोखिमों के आकलन और प्रत्येक चुनौती को आर्थिक रूप से व्यवहार्य अवसर में बदलने के लिए क्रेविस जैसे प्लेटफार्म का उपयोग करेंगी।

2030 तक 500 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा का लक्ष्य

भारत अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में वैश्विक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले देशों में से एक है। जी-20 देशों में वह लगातार पहले से तीसरे स्थान पर बना हुआ है। हमने अपने नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में 260 गीगावाट के लक्ष्य को 8 साल पहले ही हासिल कर लिया है। 2014 में पीएम मोदी के नेतृत्व में हुए सरकार गठन के बाद हमने आगामी 9 से 10 वर्षों में 20 गीगावाट का लक्ष्य रखा था। जिसे प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में बढ़ाकर 100 गीगावाट करते हुए समय पर प्राप्त कर लिया गया है। अब भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने पीएम मोदी की कॉप-21 से लेकर जलवायु के मामले में हुए कई अन्य वैश्विक सम्मेलनों में निभाई गई अहम भूमिका का भी उल्लेख किया। जिससे विकसित, विकासशील और अल्पविकसित देश एक साथ आए तथा सभी को अपने लक्ष्य निर्धारित करने की आजादी मिली।

बढ़ेगी गर्म दिनों की संख्या

प्लेटफार्म के मुताबिक, तेजी से होते जलवायु परिवर्तन के कारण 1981-2010 के जलवायु आधार की तुलना में अगले दो दशकों में भारत में प्रतिवर्ष अतिरिक्त 15 से 40 अत्यधिक गर्म दिन देखे जा सकते हैं। जबकि कई क्षेत्रों में असामान्य रूप से गर्म रातों में भी सालाना 20 से 40 दिनों की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। क्रेविस यूजर्स को एकीकृत जोखिम विश्लेषण करने के लिए जलवायु के आंकड़ों को विभिन्न क्षेत्रीय आंकड़ों के साथ मसलन बिजली का बुनियादी ढांचा, कृषि, भूमि उपयोग और जनस्वास्थ्य को जोड़कर देखने और समझने की सुविधा भी प्रदान करता है।

बेहतर सूचनाएं सुलभ होनी चाहिए

डॉ. अरुणाभा घोष (सीईओ, सीईईडब्ल्यू) ने बताया कि हमारी कोशिश यही है कि किस प्रकार से बेहतर सूचनाएं व्यापक रूप से सुलभ होनी चाहिए। प्लेटफार्म हमारे जलवायु लचीलेपन के 12 वर्षों के कार्यों पर आधारित है। जिसे मैं एक गतिशील एआई प्रणाली मानता हूं।

निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा बने क्रेविस

डॉ. विश्वास चितले (फेलो, सीईईडब्ल्यू) ने कहा कि क्रेविस का धरातल पर प्रभाव तभी आ सकता है। जब इसे निर्णय लेने की प्रक्रिया में नियमित रूप से शामिल किया जाए। ये जटिल क्लाइमेट इंटेलिजेंस को नीति-निर्माताओं, वित्तीय विशेषज्ञों, पत्रकारों के लिए सरल-सुलभ बनाता है। सीईईडब्ल्यू के टेक्नोलॉजी-एआई लीड वैभव चुग ने भी संबोधित किया।

40 वर्षों से अधिक के आंकड़े का किया इस्तेमाल

क्रेविस प्लेटफार्म में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारतीय वन सर्वेक्षण, आईआईटी दिल्ली, आईआईटीएम पुणे और अन्य संस्थानों के 40 से अधिक वर्षों के भरोसेमंद आंकड़ों की मदद से वर्ष 2070 तक का अनुमान लगाया जा सकता है। साथ ही यह 279 संकेतकों के आधार पर जिला, ग्रिड और राज्य स्तर पर जलवायु के आंकड़े उपलब्ध कराता है। जिन्हें तापमान, वर्षा और नमी से संबंधित 20 से ज्यादा विश्लेषण अनुकूल मापदंडों के रूप में शामिल किया गया है। इसमें अत्यधिक गर्मी वाले दिन, भारी बारिश की घटनाएं, सूखे की गंभीरता और सबसे लंबी अवधियां शामिल हैं। क्रेविस एक गतिशील प्रणाली होगी। जिसके बुनियादी डेटा सेट में अपडेट के साथ-साथ उसे रिफ्रेश भी किया जाएगा। इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि ये सिस्टम तेजी से अनिश्चित हो रहे भविष्य में जलवायु को ध्यान में रखकर योजनाओं का निर्माण करने के लिए एक लगातार विकसित होने वाला संसाधन बना रहे।

दिल्ली हाई कोर्ट में ऑनलाइन सुनवाई

कथित तौर पर अश्लील वीडियो प्ले होने लगे, 'हैकिंग' के दावे

> दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई के दौरान एक असामान्य घटना सामने आई। सुनवाई के बीच में ही कथित तौर पर बार-बार अश्लील वीडियो प्ले होने लगे

एजेंसी ⏭ नई दिल्ली

दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई के दौरान एक असामान्य घटना सामने आई। अदालत में कथित तौर पर बार-बार अश्लील वीडियो प्ले होने लगे। ये वीडियो वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के जरिए ब्रॉडकास्ट हुए। यह कंटेंट यूजर्स श्रीधर सरनोबत और शीतजीत सिंह के अकाउंट से चले। घटना के तुरंत बाद अदालत ने एहतियातन वीसी सिस्टम को बंद कर दिया ताकि किसी भी तरह की रुकावट या दुरुपयोग को आगे रोका जा सके। कुछ मिनटों बाद जब सिस्टम को दोबारा ऑन किया गया तो फिर से पोर्न वीडियो चलने लगे।

वीसी सिस्टम पर साइबर हमले की आशंका बढ़ी

वीसी को बंद कर दिया गया है। इस मैसेज के बाद कोर्ट के वीसी सिस्टम पर साइबर हमले की आशंका और मजबूत हो गई है। शुरुआती संकेतों के आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट के वीसी इंटरफेस पर संभावित साइबर अटैक की जांच की जा रही है।

बेंगलुरु में बारिश का कहर

अस्पताल की दीवार गिरने से 7 की मौत

एजेंसी ⏭ बेंगलुरु

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बुधवार शाम भारी बारिश और तेज हवाओं ने तबाही मचाई है। शिवाजीनगर इलाके में स्थित बोवरिंग और लेडी कर्जन अस्पताल की बड़ी चारदीवारी अचानक ढह गई। इसहादसे में कम से कम 7लोगों की जान चली गई है। मलबे के नीचे दबने से कई अन्य लोग घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया गया है। राहत की बात यह है कि डॉक्टरों ने घायलों की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई है।

सीएम सिद्धारमैया ने किया मुआवजे का ऐलान

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी घटनास्थल का दौरा किया और मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने प्रशासन को राहत कार्य तेज करने और प्रभावितों को हर संभव मदद मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने मुआवजे के तौर पर मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख देने का ऐलान किया है। शहर में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है।

उन्नाव में डंपर की टक्कर से 6 की मौत

उन्नाव। बिहार-बक्सर मार्ग पर बुधवार को एक भीषण हादसे ने पूरे जिले को दहला दिया। मां चंडिका के दरबार में 3 साल के मासूम शुभ का मुंडन संस्कार कराकर लौट रहे परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। बेकाबू डंपर ने बोलेरो को ऐसी टक्कर मारी कि अमंगल हो गया।

चिंतपूर्णी में खाई में गिरी कार, 4 लोग जिंदा जले!

ऊना। हिमाचल प्रदेश के ऊना में एक कार खाई में गिरने से 4 लोगों की मौत की आशंका है। चिंतपूर्णी के भरवाईं में यह हादसा हुआ। कार में 4 लोग सवार थे और सभी के जिंदा जलने की आशंका है। पुलिस ने मौके पर राहत और बचाव अभियान शुरू किया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट बेंच का बड़ा फैसला

'बधाई' किन्नरों का हक नहीं वे इलाका तय नहीं कर सकते

एजेंसी ⏭ लखनऊ

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने किन्नरों की रिट याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में गोंडा जिले में बधाई या जजमानी के लिए सुरक्षा और उनका इलाका तय करने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि कोई भी कानूनी मंजूरी के बिना पैसा इकट्ठा करने कानूनी,मौलिक अधिकार का दावा नहीं कर सकता। जस्टिस आलोक माथुर,जस्टिस अमिताभ कुमार राय की बेंच में रेखा देवी ने किन्नरों के बीच झगड़े रोकने, बधाई को खास इलाका घोषित करने की मांग की थी।

यह कानूनन जायज नहीं

याचिकाकर्ता का कहना था कि किन्नरों के पास शुभ अवसरों पर बधाई लेने का परंपरागत अधिकार रहा है। किन्नरों के बीच इलाकों को लेकर टकराव से झड़पें हुई हैं। कोर्ट ने कहा,कानूनी आधार के अभाव में ऐसे अधिकारों को कानूनन जायज नहीं ठहराया जा सकता।

सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश मामले में सुनवाई

सुधार के नाम पर धर्म की मूल भावना से छेड़छाड़ ठीक नहीं

एजेंसी ⏭ नई दिल्ली

सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम सवाल उठाया। कोर्ट ने पूछा कि उत्तर भारत में रहने वाला कोई गैर-आस्थावान व्यक्ति आखिर किस आधार पर सबरीमाला मंदिर में प्रवेश का अधिकार मांग सकता है? कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सामाजिक सुधार के नाम पर धर्म की मूल संरचना को कमजोर नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने कहा कि भारत की सभ्यता और धार्मिक इतिहास को नजरअंदाज करना संभव नहीं है। संविधान के अनुच्छेद भी इसी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से विकसित हुए हैं। वर्तमान को समझने के लिए अतीत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट बोला- गैर-आस्थावान किस आधार पर प्रवेश का अधिकार मांगेगा

इंदिरा जयसिंह ने रखा पक्ष

वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने दलील दी कि मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर पूर्व फैसला अब भी प्रभावी है और उस पर कोई रोक नहीं लगी है। इसके बावजूद महिलाओं को मंदिर में प्रवेश नहीं मिल पा रहा, जिसका कारण राज्य सरकार का पर्याप्त सहयोग न होना बताया गया।

आस्था बनाम अधिकार पर फोकस

पीठ ने कहा कि मंदिर प्रवेश के अधिकार से जुड़े मामलों में यह देखना जरूरी है कि दावा करने वाला व्यक्ति भक्त है या नहीं। अदालत ने संकेत दिया कि धार्मिक स्थलों से जुड़े मामलों में आस्था का पहलू भी अहम भूमिका निभाता है।

अदालत ने जटिल बताया

कोर्ट ने इस पर स्पष्ट किया कि महिला को उसके सामाजिक वर्ग के कारण नहीं, बल्कि आयु समूह के आधार पर रोका गया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि विविधता ही भारत की ताकत है और संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक संप्रदायों को अपने मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार भी दिया गया है। कोर्ट ने यह भी माना कि किसी धार्मिक प्रथा को आवश्यक या गैर-आवश्यक घोषित करना न्यायालय के लिए बेहद जटिल कार्य है।

संपादकीय जागरण

गुरुवार, 30 अप्रैल, 2026: वैशाख शुक्ल - 14 वि. 2083

परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है

छात्रों की आत्महत्याएं

यह समय की मांग थी कि उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की आत्महत्या को लेकर शिक्षा मंत्रालय सभी संस्थानों को सतर्क करते हुए उन्हें छात्रों की काउंसिलिंग करने और तय एसओपी अर्थात मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करने को कहता, लेकिन केवल इतना ही पर्याप्त नहीं। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में वह तंत्र पर्याप्त क्षमता, संवेदनशीलता और संसाधनों के साथ सक्रिय है या नहीं, जिस पर अवसाद ग्रस्त या किसी अन्य समस्या से घिरे छात्रों की काउंसिलिंग करने का उत्तरदायित्व होता है। उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों की आत्महत्याओं पर समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर चिंता जताने और उन्हें रोकने की आवश्यकता पर बल देने के बाद भी बात बनती दिख नहीं रही है। यह सामान्य बात नहीं कि आइआइटी खड़गपुर में पिछले डेढ़ वर्ष में नौ छात्रों ने आत्महत्या की। इसी तरह एनआइटी कुरुक्षेत्र में बीते दो महीनों में तीन छात्रों और एक छात्रा ने अपनी जान दे दी। इन दोनों शिक्षा संस्थानों में इतने कम समय में इतने अधिक विद्यार्थियों की आत्महत्या सामान्य बात नहीं। दुर्भाग्य से विभिन्न शिक्षा संस्थानों में छात्रों की आत्महत्या के मामले रह-रहकर सामने आते ही रहते हैं। ये मामले यही बताते हैं कि हमारे उच्च शिक्षा संस्थानों और विशेष रूप से उनके छात्रावासों में वैसा स्वस्थ और सकारात्मक वातावरण नहीं कि किसी कारण से परेशान कोई छात्र अपने प्राण त्यागने जैसा अतिवादी कदम न उठाने पाए।

छात्र-छात्राएं भिन्न-भिन्न कारणों से आत्महत्या करते हैं। कोई परीक्षा में लगातार असफलता से निराश होकर अपनी जान दे देता है, कोई नए माहौल में खुद को समायोजित न कर पाने के कारण, कोई हीनभावना से घिर जाने के चलते और कोई अपने साथ जातिगत, क्षेत्रगत भेदभाव के कारण। कुछ मामलों में कोई छात्र अपने साथी छात्रों द्वारा ही दुर्व्यवहार का शिकार होकर आत्महत्या कर लेता है। कई बार यह दुर्व्यवहार रैगिंग के रूप में होता है। इसके अलावा अन्य कारणों से भी छात्र आत्महत्या करते हैं। उन्हें ऐसा करने से तभी रोका जा सकता है, जब उनकी निराशा, उदासी, अकेलेपन अथवा उनके बदले व्यवहार को समय रहते भांपा जा सके और उनकी सही तरह काउंसिलिंग की जा सके। चूंकि अधिकांश उच्च शिक्षण संस्थानों में अलग-अलग क्षेत्रों और पृष्ठभूमि के छात्र आते हैं, इसलिए कई बार उनमें आपसी समन्वय और सद्भाव कायम नहीं हो पाता। ऐसा अनिवार्य रूप से हो, इसके लिए शिक्षा संस्थानों के प्रबंध तंत्र को पहले दिन से ही सक्रिय रहना चाहिए। उन्हें अपने संस्थान के छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की निरंतर जांच को लेकर भी सजगता का परिचय देना चाहिए।

सुधारनी होगी व्यवस्था

भाजपा के पार्षद प्रवेश वाही दिल्ली के नए महापौर चुने गए हैं। आम आदमी पार्टी द्वारा चुनाव के बहिष्कार की घोषणा के कारण उनकी जीत पहले ही तय मानी जा रही थी। नए महापौर के रूप में उनके सामने दिल्ली नगर निगम के कामकाज को दुरुस्त करने और 'विकसित दिल्ली' के संकल्प के अनुरूप काम करने की बड़ी चुनौती है। निगम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य शहर की सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करना है। स्वच्छ और हरित दिल्ली अब केवल नारा बनकर रह गया है। गलियों-मोहल्लों की तो बात छोड़िए, मुख्य सड़कों, महत्वपूर्ण बाजारों और आवासीय क्षेत्रों में भी सफाई व्यवस्था बेहद खराब है। सड़कों के किनारे गंदगी फैली रहती है। गाजीपुर, भलस्वा और ओखला में कूड़े के पहाड़ हटाने का वादा निगम के लिए चुनौती बना हुआ है।

दिल्ली नगर निगम की स्थिति सुधारने के लिए प्रभावी और त्वरित कदम उठाने की आवश्यकता है

नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सड़कों की बदहाली सफाई व्यवस्था में सुधार और वायु प्रदूषण की रोकथाम दोनों में बाधक बन रही है। स्थिति सुधारने के लिए प्रभावी और त्वरित कदम उठाने की आवश्यकता है। नालों की सफाई में लापरवाही के कारण हर वर्ष मानसून में दिल्लीवासियों को जलभराव का सामना करना पड़ता है। भाजपा की सत्ता में फिर वापसी के बाद नगर निगम के कामकाज में सुधार करना होगा।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

अब ये 4 मई को ही पता चलेगा कि किसका 'पसीना' निकला और किसका 'तेल'!!

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या बातचीत से आनाकानी कर रहे ईरान ने अमेरिका पर दबाव बढ़ा दिया है?

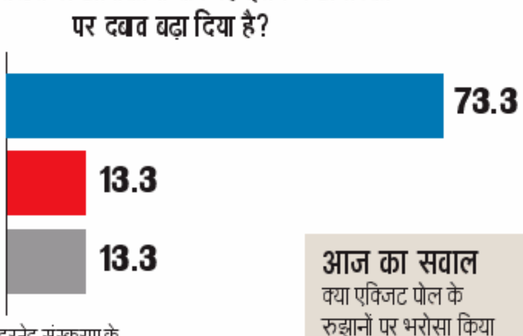

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। (सभी आकड़े प्रतिशत)

आज का सवाल
क्या एक्जिट पोल के रुझानों पर भरोसा किया जा सकता है?

केजरीवाल का बिखरता कुनबा

राज कुमार सिंह

जिस रफ्तार से आप ने दो राज्यों की सत्ता और राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल किया, उसी गति से उसमें आंतरिक असंतोष भी उभरता गया

वैकल्पिक राजनीति के सपने दिखाते हुए चमत्कारिक रफ्तार से दिल्ली और पंजाब की सत्ता कांग्रेस से छीनने वाली आम आदमी पार्टी (आप) के दस राज्यसभा सदस्यों में से सात का भाजपा में शामिल होने का फैसला पार्टी के भटकाव का प्रमाण भी है। हालांकि तीन बागियों ने ही कार्यालय जाकर भाजपा का लड्डू खाया, पर राज्यसभा में आप के नेता संजय सिंह द्वारा उनकी सदस्यता समाप्ति के लिए पत्र लिखे जाने के बावजूद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सातों बागियों के भाजपा में विलय को मंजूरी दे दी। जाहिर है 'विभाजन बनाम दलबदल' की लड़ाई लंबी चलेगी, लेकिन उससे आप के आंतरिक संकट, असंतोष और बगावत पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। स्वाति मालीवाल अरसे से आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध मोर्चा खोले हुए थीं तो राघव चड्ढा ने भी राज्यसभा में उपनेता पद से हटाए जाने के बाद खुद को 'घायल' और इसीलिए 'घातक' बताते हुए 'सैलाब' लाने का एलान कर दिया था। इसलिए केजरीवाल के साथ ही उनकी राजनीति को गंभीरता से लेने वालों को भी इस प्रयोग की विफलता का विश्लेषण करना चाहिए। यह भटकाव अचानक नहीं आया।

सत्ता के गलियारों में प्रवेश के साथ ही आप में भटकाव और उसके चलते अलगाव शुरू हो गया था। आप आलाकमान ने पार्टी छोड़ गए सांसदों को पंजाब का 'गद्दार' करार दिया, पर यह नहीं बताया कि वे खुद कब और किसके 'वफादार' रहे? राघव, स्वाति और संदीप पाठक को आंदोलनकारी आप का सिपाही मान भी लें तो क्रिकेटर हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रमजीत साहनी और अशोक मित्तल को राज्यसभा सदस्यता किस निष्ठा के पुरस्कारस्वरूप दी गई? कभी मोहल्ला सभा की राय से पार्षद-विधायक प्रत्याशी चुनने की बात करने वाले केजरीवाल ने संसद के उच्च सदन की सदस्यता बांटने की कुछ तो कसौटी रखी होगी।

कारोबारी अशोक मित्तल वही हैं, जिन्हें केजरीवाल ने राघव को हटाकर राज्यसभा में पार्टी का उप नेता बनाया था, पर दोनों ने ही पांच अन्य के साथ 'झाड़ू' छोड़कर 'कमल' चुन लिया। इनके अलावा भी जो लोग राज्यसभा भेजे गए, उनकी निष्ठा पर लगातार उठते रहे सवालों से केजरीवाल मुंह चुराते रहे। केजरीवाल को सही आदमी की पहचान नहीं या फिर उनकी कसौटियां दल और विचारधारा के प्रति निष्ठा से इतर कुछ और हैं? खुद को 'ईमानदार' घोषित करते हुए केजरीवाल तमाम परंपरागत दलों और नेताओं के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपपत्र जारी करते रहे, पर आप में अंतहीन बगावत और अलगाव खुद उन्हें कठघरे में खड़ा करता है। विरोधियों की मानें तो जिस आप को सत्ता राजनीति के चरित्र में बदलाव का वाहक बनना चाहिए था, वह केजरीवाल की निरंकुश सत्ता का औजार बनकर रह गई। जिस रफ्तार से आप ने दो राज्यों की सत्ता और राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल किया, उसी गति से उसमें आंतरिक असंतोष उभरता गया। कम उम्र में सीए और फिर विधायक-सांसद बने राघव चड्ढा को जिस तरह राज्यसभा में उपनेता पद से हटाते हुए पत्र लिखा गया कि उन्हें पार्टी की ओर से बोलने का समय न दिया जाए, वह नेतृत्व से बढ़ती कटुता का प्रमाण है। जिन राघव पर पंजाब में 'सुपर सीएम' की तरह काम करने के आरोप लगे, वह अचानक इतना नापसंद कैसे हो गए? क्या निजी रिश्ते ही आप में राजनीतिक हैसियत तय करते हैं? ऐसे सवाल तभी से उठ रहे हैं, जब दिल्ली में प्रचंड बहुमत से सत्ता मिलने के बाद प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव और कुमार विश्वास जैसे संस्थापक सदस्यों का अलगाव हुआ था, पर जवाब आज तक नहीं मिले।

अवधेश राजपूत

'आपरेशन लोटस' की भनक मिलने पर ही राघव को उपनेता पद से हटाने की बात कही जा रही है, पर जिन अशोक मित्तल को उनकी कुर्सी दी गई, वह भी भाजपा से जा मिले, शायद ईडी के छापों से डर से। कारोबारी हमेशा मुनाफे का ही सौदा करेगा। केजरीवाल और राघव के बीच दूरियां बढ़ने की खबरें अरसे से थीं। जब केजरीवाल कथित शराब घोटाले में जेल भेजे गए, तब राघव आंखों का इलाज कराने लंदन चले गए। जब दिल्ली की एक अदालत द्वारा शराब घोटाले में आरोपमुक्ति पर केजरीवाल ने खुद को फिर 'ईमानदार' घोषित किया, तब भी राघव ने खुशी जताने की जहमत नहीं उठाई। आप के मुखर नेता रहे संदीप पाठक द्वारा भाजपा में जाना चौंकाता है, पर केजरीवाल के राजनीतिक प्रबंधन पर सवालिया निशान भी लगाता है। यह नसीहत स्वाभाविक है कि आप छोड़ने वालों को राज्यसभा सदस्यता भी छोड़ देनी चाहिए, पर जब राजनीति का लक्ष्य ही सत्ता है तो उसे पाने के बाद कौन छोड़ देगा? दूसरों को आरोप लगते ही पदत्याग की नसीहत देने वाले केजरीवाल जेल जाने के बाद भी लंबे समय तक दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहे थे, जबकि उसी बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी के साथ ही इस्तीफा देकर अलग मिसाल पेश की थी। विधानसभा चुनाव होने पर दोनों राज्यों के मतदाताओं ने भी अलग-अलग जनादेश दिया।

आप में टूट से राज्यसभा में भाजपा के लिए बहुमत की राह आसान होगी, पर उसका लक्ष्य पंजाब और गुजरात है। गुजरात में भाजपा के दशकों से दबदबे के चलते तात्कालिक चुनौती नहीं, पर 13 के पार पहुंच गया आप का मत प्रतिशत खतरे का संकेत है। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ भाजपा का गठबंधन बिजयी समीकरण था, लेकिन अलगाव के बाद दोनों हाशिए पर चले गए। आप प्रचंड बहुमत से सत्ता में है तो कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष क्रमशः कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़ भाजपा में आ चुके हैं। पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पौत्र रवनीत सिंह बिट्टू भाजपा से लोकसभा तो नहीं पहुंचे, पर राज्यसभा के रास्ते केंद्रीय मंत्री बना दिए गए। आप छोड़ भाजपाई बने राज्यसभा सदस्यों में से किसी का भी जनाधार नहीं, लेकिन उनके जरिये आप में बड़े विभाजन से विधानसभा चुनाव से पहले भगवंत मान सरकार खतरे में पड़ी तो भाजपा का राजनीतिक स्थिरता का कार्ड चल सकता है। दिल्ली के बाद पंजाब की सत्ता भी हाथ से फिसलना केजरीवाल और आप के राजनीतिक भविष्य पर बड़ा सवालिया निशान होगा।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)
response@jagran.com

वैश्विक समाधान में समर्थ यूपीआइ

रोहित यादव

जब दुनिया में जंग हो तब रुपये का प्रवाह रुकना नहीं चाहिए और यूपीआइ से इसमें अपेक्षित सफलता मिलेगी

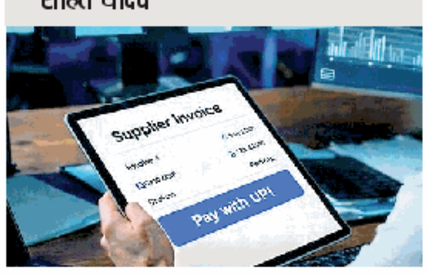

यूपीआइ पर बढ़ता दुनिया का भरोसा ● फाइल

इस फरवरी में जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला किया तो पश्चिम एशिया में हड़कंप मच गया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजरायल, बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात पर सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दागे तथा स्ट्रेट आफ होर्मुज बंद कर दिया। यह वह समुद्री रास्ता है, जिससे दुनिया का 20 प्रतिशत तेल और अरबों डालर का व्यापार होता है। बैंकिंग के रास्ते धीमे पड़ गए, पैसे भेजना मुश्किल हो गया। 40 दिनों की भीषण लड़ाई के बाद दो हफ्ते का युद्धविराम हुआ, लेकिन उसके विस्तार के बाद भी स्थिति नाजुक बनी हुई है। इस जंग ने दुनिया की आर्थिक व्यवस्था को तहस-नहस कर दिया। होर्मुज बंद होने से तेल के दाम आसमान छूने लग गए। शिपिंग कंपनियां रास्ता बदलने पर मजबूर हो गईं और सबसे बड़ी तकलीफ यह रही कि भारत के लाखों श्रमिक जो यूएई, कुवैत, बहरीन और सऊदी अरब में काम करते हैं, उनके परिवारों तक पैसे भेजना मुश्किल हो गया। पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था संकट में आ गई।

यह पहली बार नहीं जब दुनिया ने देखा कि वित्तीय व्यवस्था को हथियार बनाया जा सकता है। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस को स्विफ्ट से बाहर कर दिया था। इस व्यवस्था के जरिये दुनिया के बैंक आपस में पैसे भेजते हैं। सीधे शब्दों में यह बैंकों का वाट्सएप है। रूस के स्विफ्ट से बाहर होने के बाद रूसी लोग दुनिया से कट गए। अब ईरान पर भी कड़े प्रतिबंध हैं।

भारत ने यूपीआइ यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को 2016 में तब शुरू किया था, जब दुनिया में इस तरह के संकटों की कल्पना भी मुश्किल थी। नेशनल पेमेंट्स कार्पोरेशन आफ इंडिया यानी एनपीसीआइ ने यह व्यवस्था इसलिए बनाई थी, ताकि हर भारतीय को सस्ता, तेज और आसान डिजिटल भुगतान मिल सके। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यही यूपीआइ एक दिन दुनिया के लिए स्विफ्ट का सबसे बड़ा निष्पक्ष विकल्प बन सकता है। रूस-यूक्रेन युद्ध और अब अमेरिका-इजरायल और ईरान की जंग ने यह साबित कर दिया कि भारत ने जो व्यवस्था अपने नागरिकों के लिए बनाई थी, वह आज पूरी दुनिया की जरूरत है। स्विफ्ट ने वादा किया था कि वह निष्पक्ष रहेगा, लेकिन राजनीति आई तो उसने पक्ष लिया। यूपीआइ किसी के हाथ का हथियार नहीं और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। यूपीआइ जिसे आप फोन पे, गूगल पे या पेटीएम के जरिये रोज इस्तेमाल करते हैं, दुनिया की सबसे तेज और सबसे सस्ती भुगतान व्यवस्था है। अब यह देश की सीमाएं पार कर रही है। सिंगापुर, यूएई, फ्रांस और मारीशस जैसे कई देशों से यूपीआइ का जुड़ाव हो चुका है।

भारत दुनिया में सबसे अधिक विदेशी पैसा मंगाने वाला देश है। हर साल करीब 11 लाख करोड़ रुपये भारतीय विदेश से अपने घर धनराशि भेजते हैं। लंदन में बैठी नर्स, ह्यूस्टन का इंजीनियर, दुबई का दुकानदार सब अपने परिवार को पैसे भेजते हैं। पुराने तरीकों से पैसे भेजने में 6-7 प्रतिशत तक राशि कट जाती है। यूपीआइ के जरिये यह खर्च लगभग खत्म हो सकता है।

जब दुनिया में जंग हो तब पैसा रुकना नहीं चाहिए। यूपीआइ यही सुनिश्चित करने का काम कर रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या रूस या चीन ने भी ऐसा कुछ नहीं बनाया? बनाया तो, लेकिन दुनिया ने उन्हें नहीं अपनाया, क्योंकि भरोसा नहीं था। ईरान के खिलाफ युद्ध में यही देखा गया कि जो देश अमेरिका के निशाने पर हैं, उनकी भुगतान व्यवस्था दुनिया स्वीकार नहीं करती। भारत पर भरोसे के चलते कई देश यूपीआइ से जुड़ने को तैयार हैं। इस युद्ध ने यह भी साफ किया कि दुनिया डालर पर निर्भरता कम करना चाहती है। भारत की यूपीआइ सेटलमेंट व्यवस्था इसका एक व्यावहारिक जवाब है।

कुछ लोग सोचते हैं कि अगर भारत अपनी यूपीआइ तकनीक दूसरे देशों को दे रहा है तो वे इसे कापी कर लेंगे। यह सोच सही नहीं। तकनीक कापी हो सकती है, लेकिन नेटवर्क नहीं। जैसे वाट्सएप की तकनीक कोई भी बना सकता है लेकिन उसके करोड़ों उपयोगकर्ता कोई नहीं छीन सकता। यूपीआइ का नेटवर्क, उसके करोड़ों उपयोगकर्ता और उसकी साख-यही भारत की असली पूंजी है। आज भारत प्रोजेक्ट नेक्सस जैसी वैश्विक पहलों में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। प्रोजेक्ट नेक्सस का मतलब है दुनिया के अलग-अलग देशों की फास्ट पेमेंट व्यवस्थाओं को एक साथ जोड़ना। यह स्विफ्ट का एक खुला और निष्पक्ष विकल्प बन सकता है, जिसे कोई एक देश बंद नहीं कर सकता।

अभी यूपीआइ वैश्विक स्तर पर पूरी तरह सरल नहीं बन पाया है। विदेश में रहने वाले भारतीयों को अभी भी भारतीय सिम कार्ड की जरूरत पड़ती है। सभी देशों में सभी दुकानों पर यूपीआइ नहीं चलता, लेकिन रिजर्व बैंक और एनपीसीआइ इस पर काम कर रहे हैं। जल्द ही ये रुकावटें भी दूर होंगी। आज दुनिया जिस तरह अनिश्चितता से भरी है, उसमें यूपीआइ की जरूरत और भी ज्यादा है। युद्ध का मैदान अब सिर्फ जमीन पर नहीं, वह बैंकों में, पेमेंट सिस्टम में और डिजिटल नेटवर्क में भी है। अमेरिका-इजरायल और ईरान की जंग ने फिर साबित किया कि जब दुनिया बंट जाती है तो पैसों की निष्पक्ष व्यवस्था सबसे बड़ी जरूरत बन जाती है। भारत का यूपीआइ वही निष्पक्ष व्यवस्था है।

(लेखक नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट स्टडीज, मुंबई के स्कूल आफ बिजनेस मैनेजमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

सकारात्मकता की सार्थकता

सकारात्मक सोच का अर्थ है रचनात्मक मानसिकता के साथ चुनौतियों का सामना करना, अपने समक्ष समाधान खोजना और किसी भी स्थिति से सर्वश्रेष्ठ परिणामों को सुनिश्चित करना। सकारात्मकता से हमें नई दृष्टि और परिधि प्राप्त होती है। इससे हमारा आत्मविस्तार होता है तथा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य लाभ मिलता है। सकारात्मकता से मन में पवित्र भावों का जागरण होने लगता है, दोष ढूंढ़ने की प्रवृत्ति नष्ट होती है। हमारी दृष्टि में दूसरे का सुख स्थान पाने लगता है। अपने कर्मों के प्रति पूज्य भाव का उदय होता है। नकारात्मकता से हम छिद्रान्वेषी हो जाते हैं और तब सारा संसार बुराइयों में लिप्त दिखाई देने लगता है तथा स्वयं के दोषमुक्त होने की प्रवृत्ति समाप्त होती जाती है। सकारात्मकता से विषम परिस्थितियों में धैर्य बना रहता है। सकारात्मक व्यक्ति में सदैव यह विश्वास बना रहता है कि मैं कठिन परिस्थितियों में भी उनसे पार पाकर अवश्य सफल हो जाऊंगा।

वास्तव में सफलता की कुंजी सकारात्मकता ही है। सकारात्मकता से ओतप्रोत व्यक्ति के शब्दकोश में 'असंभव' शब्द नहीं होता है। वह परिस्थितियों से जूझते हुए अपने लक्ष्य को पा ही लेता है। सकारात्मकता आत्मविश्वास की आधारशिला है। सकारात्मक सोच से दुखों को दूर किया जा सकता है। सुमति ही सकारात्मकता है और कुमति नकारात्मकता। जिसने सुमति का आश्रय लिया, अपना कल्याण सिद्ध कर लिया और जो कुमति के साथ रहा, उसने अपना सर्वस्व नाश कर लिया।

सकारात्मकता ही हमें दूसरों के लिए जीने की प्रेरणा देती है तथा सुखद समानुभूति कराती है, जबकि नकारात्मकता हमें संकीर्ण बनाकर छोटा कर देती है। नकारात्कमता के चलते ही हम स्वार्थ के वशीभूत होकर रह जाते हैं। ध्यान रहे कि धैर्यशील व्यक्ति असफलताओं से धैर्य नहीं खोते और अपने सकारात्मक विचारों के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। सचमुच सकारात्मकता सार्थक जीवन का मूलमंत्र है, जो हमें हमारे उद्देश्य तक पहुंचाती है।

गौरीशंकर वैश्य

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

बंगाल के नतीजों पर टिकी निगाहें

'ममता के सामने गढ़ बचाने की चुनौती' शीर्षक से लिखे आलेख में राहुल वर्मा ने बंगाल विधानसभा चुनाव का समग्रता में विश्लेषण किया है। बंगाल विधानसभा चुनाव देश की राजनीति का केंद्र बना हुआ है। दूसरे चरण के मतदान के बाद मुकाबला और रोचक हो गया है। राज्य में लंबे समय से राजनीतिक हिंसा और तीखी चुनावी प्रतिस्पर्धा का माहौल रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने अपना मजबूत जनाधार बचाने की चुनौती है, वहीं भाजपा सत्ता परिवर्तन के लक्ष्य के साथ जुटी रही। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। यदि ममता बनर्जी की चौथी बार वापसी होती है, तो राष्ट्रीय पटल पर भाजपा के विरुद्ध उनकी छवि और मजबूत होगी। यदि भाजपा सत्ता परिवर्तन में सफल होती है, तो यह टीएमसी के अस्तित्व के लिए खतरे की घंटी होगी। राज्य में भारी मतदान प्रतिशत यह संकेत देता है कि जनता लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी निभाना चाहती है। केंद्रीय बलों की तैनाती से मतदाताओं में सुरक्षा भाव बढ़ा। अब देखना यह है कि क्या ममता अपना गढ़ बचा पाती है, या भाजपा नया इतिहास रचेगी?

हिमांशु शेखर-केसपा, गयाजी

दुविधा में अमेरिका

भारतीय जनमानस में एक गहरी लोकोक्ति है 'दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम'। यह कहावत तब चरितार्थ होती है, जब कोई महाशक्ति रणनीतिक लालच और दुविधा में फंसकर न केवल अपने लक्ष्य खो देती है, बल्कि अपनी वैश्विक साख भी दांव पर लगा देती है। वर्तमान में अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान नीति इसी का जीवंत उदाहरण है। इजरायल-ईरान संघर्ष की आग में घी डालकर मध्य-पूर्व के संसाधनों और सत्ता पर वर्चस्व जमाने का अमेरिकी सपना अब एक महंगे दुस्वप्न में बदलता दिख रहा है। ट्रंप प्रशासन ने ईरान को कमजोर समझकर इस आस में युद्ध की चिंगारी को हवा दी कि वे वहां के यूरेनियम भंडारों, कच्चे तेल के कुओं और सत्ता संरचना पर काबिज होकर दुनिया को अपने इशारों पर नचाएंगे। वाशिंगटन को लगा कि ईरान भी वेनेजुएला की तरह प्रतिबंधों के बोझ तले ढह जाएगा। लेकिन ईरान की प्रतिरोधक क्षमता और उसकी भौगोलिक सामरिक शक्ति का आकलन करने में अमेरिका से भारी चूक हुई है। आज स्थिति यह है कि अमेरिका युद्ध से सम्मानजनक निकास के लिए हर तरह की कूटनीतिक पैंतरेबाजी और पर्दे के पीछे से समझौते की राह तलाश रहा है। इस युद्ध की सबसे बड़ी कीमत अमेरिकी जनता चुका रही है। एक ताजा आकलन के अनुसार, अमेरिका इस संघर्ष में अब तक पांच लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि फूंक चुका है। इसमें केवल सैन्य साजो-सामान ही नहीं, बल्कि भूमध्य सागर और लाल सागर में तैनात विमानवाहक पोतों का भारी-भरकम परिचालन खर्च भी शामिल है। इस युद्ध से अमेरिका की केवल आर्थिक क्षति ही नहीं हो रही, बल्कि उसकी सुपरपावर वाली छवि भी धूमिल हुई है।

युगल किशोर राही, ग्रेटर नोएडा

केजरीवाल की अभिलाषा

निस्संदेह भारतीय न्याय व्यवस्था में प्राविधान है कि ट्रायल कोर्ट के निर्णय को हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। इसी तर्ज पर दिल्ली शराब नीति घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ सीबीआइ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई है। हाई कोर्ट ने इस पर नोटिस जारी कर सभी आरोपियों से जवाब मांगा है। इसमें बुराई क्या है? इस केस से संबंधित जज बदलने से न्याय व्यवस्था की कार्य प्रणाली पर ही सवालिया निशान लग जाएगा। फिर तो कोई भी नेता अपने मन मुताबिक देश के मुख्य चुनाव आयुक्त, कैग, केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल आदि की कार्यशैली पर दबाव बनाकर और बेवजह सवालिया निशान लगाकर पूरे देश में अराजकता और हाय-तौबा का माहौल बनाने की पुरजोर कोशिशें कर सकता है। आज अरविंद केजरीवाल सत्याग्रह की शरण में है, मतलब सत्य का आग्रह। क्या हमारी न्याय व्यवस्था इतनी पंगु और लचर है? निस्संदेह एक बात तो दोनों नेताओं की हास्यास्पद है कि हम न्याय व्यवस्था का सम्मान करते हैं लेकिन जज स्वर्ण कांता शर्मा के फैसले की नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर कट्टर ईमानदारी वाली राजनीतिक गोटियां फिट की जा रही हो। निश्चित ही देश की सरकार एक देश एक संविधान के मूल सिद्धांत पर ही कार्यरत है।

दीपक गौतम, सोनीपत

पोस्ट

बंगाल में कौन सा 'एम' फैक्टर काम करेगा? महिला या मुसलमान? इस बार महिला फैक्टर भारी रहा मुसलमान फैक्टर पर। डा. स्वदेश सिंह @swadesh171

बंगाल राजनीतिक रूप से सबसे हिंसक राज्य है। यहां राजनीतिक विरोधियों को दुश्मन की तरह माना जाता है। यहां साम्यवादी विरासत अभी भी कायम है।

जे. गोपालकृष्णन @jgopikrishnan70

संयुक्त अरब अमीरात-यूएई ओपेक के ढर्रे को लेकर लंबे समय से नाखुश था। ओपेक देश अक्सर तेल की कीमतें बढ़ाने के लिए उत्पादन में कटौती का दांव आजमाते आए हैं, जबकि यूएई उत्पादन क्षमता बढ़ाना चाहता है। यूएई के इस कदम से तेल उत्पादक देशों की एकता टूटेगी तो दाम घटने की संभावना भी बढ़ेगी।

दिबांग@dibang

मुंबई में जिहाद के नाम पर निर्दोष लोगों को निशाना बनाना देश के सामाजिक ताने-बाने पर हमला है। किसी भी तरह के कट्टरपंथ को सामान्य नहीं माना जा सकता, न उसे माफ किया जा सकता है। जीरो टालरेंस का यही अर्थ होना चाहिए।

अभिषेक सिंघवी @DrAMSinghvi

जनपथ

दीदी एक्जिट पोल में हुई दिख रहीं साफ,
पोजीशन में भाजपा पहुंच गई है टाप।
पहुंच गई है टाप चली ना गुंडागर्दी,
'सिंघम' आया काम भले वह था बिनवर्दी!
बिना भूमिका बात समझ लीजै यह सीधी,
बोरिया-बिस्तर बांध जा रहीं अबकी दीदी!!

ओम प्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित संपादक (दिल्ली एनसीआर)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 120- 4615800, E- mail:delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 36 अंक 285

पर्यटन संग आर्थिकी को भी गति देगा गंगा एक्सप्रेसवे

36,230 करोड़ रुपये है परियोजना लागत (भूमि अधिग्रहण सहित)

- भारत के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे में से एक, गंगा एक्सप्रेसवे 594 किमी (6 लेन, 8 लेन तक विस्तारित करने योग्य) तक फैला है।
- यह मेरठ को प्रयागराज से जोड़ता है और इसकी परिधि में 12 जिले और 519 गांव हैं।
- यूपीडा द्वारा पीपीपी माडल के तहत रिकार्ड तीन साल और तीन महीने में इसे विकसित किया गया

कनेक्टिविटी और क्षमता

- यात्रा का समय 11 घंटे से घटकर 6 घंटे
- औसत गति 50-60 किमी प्रति घंटा से बढ़कर 100 किमी प्रति घंटा
- माल और यात्री गलियारों की कनेक्टिविटी में सुधार
- अनुमानित ईंधन बचत 30%

आर्थिक प्रभाव

- वार्षिक लॉजिस्टिक्स बचत का अनुमान 25,000-30,000 करोड़
- उत्तर प्रदेश के जीडीपी में 1 लाख करोड़ से अधिक की वृद्धि की क्षमता
- 3 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे
- औद्योगिक उत्पादन और भूमि मूल्य वृद्धि से राज्य के राजस्व में होगी वृद्धि

औद्योगिक और इन्फ्रास्ट्रक्चर लिंक

- मिर्जापुर में बिजली परियोजनाओं को जोड़ता है
- कानपुर में रक्षा विनिर्माण केंद्र को जोड़ता है
- रायबरेली में रेल केंद्रों तक पहुंच में सुलभ
- लखनऊ हवाई अड्डे से बेहतर कनेक्टिविटी
- सभी 12 जिलों में 11 औद्योगिक गलियारों की योजना

594 किलोमीटर लंबाई है मेरठ से प्रयागराज तक

12 जिलों के पर्यटन स्थलों के लिए आसान होगा सफर

27 इंडस्ट्रियल क्लस्टर और लाजिस्टिक हब खोलेंगे निवेश व रोजगार के नए द्वार

ड्रोन से लिया गया गंगा एक्सप्रेसवे के इंटरचेंज का चित्र ● यूपीडा

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पश्चिम से पूरब कर 12 जिलों से गुजरने वाला गंगा एक्सप्रेसवे पर्यटन के साथ प्रदेश की आर्थिकी को भी गति देगा। मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाले इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से पर्यटकों के लिए धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पर्यावरण पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होगी। इससे व्यापार, निवेश, रोजगार और क्षेत्रीय विकास को भी नई गति मिलेगी।

पर्यटन विभाग के अनुसार गंगा एक्सप्रेसवे से सबसे अधिक लाभ मेरठ जिले के हस्तिनापुर को मिल सकता है। महाभारत काल से जुड़ा हस्तिनापुर जैन धर्म का भी प्रमुख तीर्थस्थल है। बेहतर सड़क संपर्क से दिल्ली-एनसीआर के शहरों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। पांडेश्वर महादेव मंदिर, करण मंदिर, उल्टा खेड़ा उत्खनन स्थल और हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य जैसे स्थल अब नई पहचान पाएंगे।

संभल क्षेत्र में भी धार्मिक पर्यटन को बल मिलेगा। हापुड़ के ब्रजघाट गढ़मुक्तेश्वर, बुलंदशहर के अवंतिका देवी मंदिर, अमरोहा के वासुदेव मंदिर, बदायूं के श्रीरामचंद्र विराजमान मंदिर और शाहजहांपुर के परशुराम मंदिर जैसे स्थलों को भी लाभ मिलेगा।

बागपत के लाक्षागृह जैसे ऐतिहासिक स्थलों के पर्यटन महत्व में भी वृद्धि होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरदोई के बनेश्वर महादेव मंदिर, उन्नाव के नवाबगंज ईको-टूरिज्म क्षेत्र, रायबरेली के चामुंडा शक्तिपीठ, प्रतापगढ़ के मां ज्वाला देवी धाम और प्रयागराज तक यह मार्ग धार्मिक तथा प्राकृतिक पर्यटन को एक साथ जोड़ता है। प्रयागराज ब्लैक बक रिजर्व जैसे स्थलों तक पहुंच आसान होने से पर्यावरण पर्यटन को भी गति मिलेगी।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि देश की प्राचीन सभ्यता का उद्गम और उत्कर्ष गंगा के तटों पर ही हुआ है। उसी गंगा मां के समानांतर विकसित गंगा एक्सप्रेसवे विकास की एक नई गाथा है। इससे पर्यटन मानचित्र का और विस्तार होगा। यह जैन सर्किट, महाभारत सर्किट, कल्कि धाम संभल और आसपास के ईको-टूरिज्म स्थलों को भी नई ऊर्जा प्रदान करेगा।

वर्तमान में यूपी में संचालित एक्सप्रेसवे (किलोमीटर)

यमुना एक्सप्रेसवे	165
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे	302
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे	341
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे	296
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे	91
नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे	25
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे	96

(इन सभी एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 1316 किलोमीटर है।)

देश में प्रदेश के एक्सप्रेसवे नेटवर्क की भागीदारी

- देश के एक्सप्रेसवे नेटवर्क में अब 60 प्रतिशत होगी यूपी की हिस्सेदारी।
- राज्य में 1910 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे नेटवर्क हुआ तैयार।
- मई में लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे के लोकार्पण बाद हो जाएगी 1973 किमी कुल लंबाई।
- लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करा रहा है।
- अन्य एक्सप्रेसवे का निर्माण उप्र एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने कराया।

एनसीआर से सुबह निकलिए, संगम में डुबकी लगा देर शाम तक लौटिए

ठाकुर डीपी आर्य ● जागरण

हापुड़: दिल्ली-एनसीआर के लाखों लोगों के लिए अब प्रयागराज का सफर आसान हो गया है। गंगा एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के साथ ही हापुड़ जिले ने इस सुहाने सफर का नया दरवाजा खोल दिया है। अब प्रयागराज के लिए सुबह घर से निकलकर और फिर संगम में स्नान कर उसी दिन देर शाम तक घर वापसी भी आसानी से की जा सकेगी। यानि सुबह को प्रयागराज जाइए और संगम स्नान करके शाम तक वापस आ जाइए। इससे प्रयागराज वीकेंड डेस्टीनेशन बन गया है।

इस एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और हरियाणा के लोगों के लिए भी बेहद सुविधाजनक साबित होगा। हापुड़ के सिंभावली क्षेत्र से दिल्ली-गाजियाबाद और हरियाणा के लोगों को सीधा इंटरचेंज मिलेगा। वहीं, ग्रेटर नोएडा, पूर्वी दिल्ली और जेवर क्षेत्र के यात्रियों के लिए सदरपुर इंटरचेंज अप-डाउन का आसान विकल्प बनेगा।

एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन दौड़ सकेंगे। धार्मिक दृष्टि से भी यह एक्सप्रेसवे बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। प्रयागराज में संगम स्नान के लिए अब लोगों को कई दिन की योजना नहीं बनानी पड़ेगी। सुबह जल्दी निकलकर संगम में स्नान और दर्शन करने के बाद शाम तक घर लौटना संभव होगा। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि यात्रा का खर्च भी कम आएगा। हापुड़ के लिए यह एक्सप्रेसवे विकास की नई राह भी खोल रहा है। बेहतर कनेक्टिविटी से यहां व्यापार, पर्यटन और निवेश के नए अवसर पैदा होंगे।

दिल्ली-नोएडा के यात्रियों के लिए-

- दिल्ली-लखनऊ हाईवे यानि एनएच-9 पर हापुड़ से 25 किमी आगे सिंभावली के पास गंगा एक्सप्रेसवे पर चढ़ने की सुविधा।
- हरियाणा-बागपत से पेरीफेरल एक्सप्रेसवे से डासना पर उतरकर एनएच-9 पर पहुंचें और फिर सिंभावली से गंगा एक्सप्रेसवे।
- अमरोहा-बिजनौर के लोगों के लिए गजरौला से एनएच-9 पर पहुंचे और 30 किमी चलकर सिंभावली से गंगा एक्सप्रेसवे।
- बुलंदशहर, ग्रेटर नोएडा, जेवर क्षेत्र व हरियाणा से बुलंदशहर-स्याना पहुंचें। स्याना से पांच किमी पर सदरपुर से गंगा एक्सप्रेसवे।

एक लाख किसानों के योगदान से साकार हुआ एक्सप्रेसवे

मल्लावां में गंगा एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के अवसर पर संबोधित करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ● जागरण

पंकज मिश्र ● जागरण

हरदोई: गंगा एक्सप्रेसवे के लोकार्पण अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के योगदान को विशेष रूप से सराहा। उन्होंने कहा कि 12 जनपदों के एक लाख से अधिक किसानों ने अपनी भूमि देकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो इस परियोजना की सफलता का आधार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 18,000 एकड़ भूमि किसानों से प्राप्त कर इस महत्वाकांक्षी परियोजना को साकार किया गया जबकि इसके किनारे विकसित होने वाले इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल क्लस्टर और लाजिस्टिक हब के लिए करीब 7,000 एकड़ अतिरिक्त भूमि ली गई है। पारदर्शी नीति और सहभागिता के कारण यह परियोजना समयबद्ध तरीके से पूरी हो सकी।

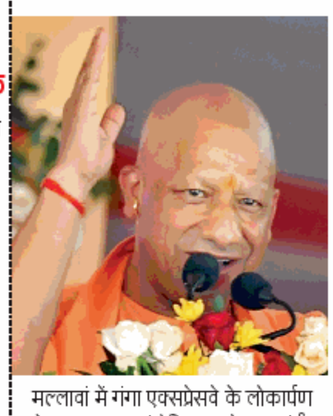

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई आधारशिला बुधवार को लोकार्पण के साथ साकार रूप ले चुकी है। कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के बावजूद परियोजना की रफ्तार नहीं रुकी। निरंतर कार्य करते हुए इसे निर्धारित समय में पूरा किया गया। एक्सप्रेसवे केवल आवागमन को तेज करने का माध्यम नहीं हैं, बल्कि ये प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाले इंजन बन चुके हैं। गंगा एक्सप्रेसवे किसानों की उन्नति, युवाओं को रोजगार, आस्था और संस्कृति के संरक्षण तथा प्रदेश की समग्र समृद्धि का प्रमुख माध्यम बनेगा। उन्होंने यह भी बताया कि एक्सप्रेसवे के साथ 27 स्थानों पर इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल क्लस्टर और लाजिस्टिक हब विकसित किए जा रहे हैं, जिससे निवेश के नए अवसर पैदा होंगे।

फिलहाल मुफ्त में करें यात्रा

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : गंगा एक्सप्रेसवे पर बुधवार आधी रात से वाहनों का आवागमन शुरू हो गया। लेकिन किसी भी वाहन से फिलहाल टोल वसूली नहीं की जा रही है। सूत्रों के अनुसार 10-15 दिनों तक एक्सप्रेसवे को टोल मुक्त रखा जाएगा। राज्य सरकार स्पष्ट करेगी कि कब से टोल वसूली होगी।

टोल टैक्स दरें (एक तरफ से)

दो पहिया, तीन पहिया वाहन, पंजीकृत ट्रैक्टर	905 रुपये
कार, जीप, हल्के वाहन	1800 रुपये
हल्के व्यावसायिक वाहन व मिनी बस	2840 रुपये
भारी निर्माण मशीनरी व तीन से छह एक्सेल तक के वाहन	8760 रुपये

एक नजर में

'आमने-सामने की टक्कर में एक पक्ष को दोषी बता तय नहीं कर सकते लापरवाही'

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आमने सामने की टक्कर के मामले में मोटर दुर्घटना दावों में एक पक्ष को दोषी ठहराकर लापरवाही तय नहीं की जा सकती। इसके बजाय इसमें शामिल सभी पक्षों के आचरण का संतुलित, निष्पक्ष और तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। वर्ष 2009 के एक जानलेवा सड़क दुर्घटना मामले में मुआवजे के दावों को खारिज करने का फ़ैसला रद करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और विजय बिश्नोई की पीठ ने माना कि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) और पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा रोडवेज के बस चालक की भूमिका की ठीक से जांच किए बिना दुर्घटना का पूरा दोष सिर्फ मृत कार चालक पर डाल दिया, जो एक गलती थी। (आइएएनएस)

आंधी, वज्रपात से यूपी और बिहार में 17 लोगों की मौत

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश व बिहार में बुधवार को बदले मौसम ने कहर बरपाया। धूलभरी आंधी, बारिश, ओलावृष्टि व आकाशीय बिजली से उप्र में 13 व बिहार में तीन महिलाओं समेत चार लोगों की मौत हो गई। यूपी में सर्वाधिक असर अवध क्षेत्र में रहा। सबसे ज्यादा नुकसान सुलतानपुर में हुआ। बल्दीराय क्षेत्र में पेड़ व छप्पर गिरने से एक बालिका समेत छह लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को पूर्वी उप्र में 30 से 40 किमी व पश्चिमी उप्र में 50 से 60 किमी प्रति घंटे की गति से हवा चल सकती हैं। (जागरण टीम)

तीस्ता सीतलवाड़ का पासपोर्ट जारी करने की याचिका खारिज

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ का पासपोर्ट जारी करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। सीतलवाड़ ने अपने पासपोर्ट की रिहाई की मांग की थी, जो 2002 के गोधरा दंगों के मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए दस्तावेजों के कथित निर्माण के मामले में जमानत की शर्त के रूप में एक अदालत में जमा किया गया था। उनकी याचिका की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता, सतीश चंद्र शर्मा और आलोक अराधे की पीठ के समक्ष हुई। (प्रेट्र)

छात्रों की आत्महत्याएं उच्च शिक्षण संस्थानों पर खड़े कर रही सवाल

- सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यूजीसी ने इसी वर्ष जारी की थी गाइडलाइन
- प्रत्येक छात्र के मानसिक स्वास्थ्य पर नजर रखने का दिया था प्लान
- इस महीने आइआइटी खड़गपुर में दो छात्रों की आत्महत्या की घटनाएं आई सामने

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट के दखल और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के दिशा-निर्देशों के बाद भी उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की आत्महत्या की घटनाएं थम नहीं रही हैं। पिछले दो महीनों में एनआइटी कुरुक्षेत्र में चार छात्रों की आत्महत्या की घटना के बाद आइआइटी खड़गपुर में भी एक महीने में ही दो छात्रों की आत्महत्या की घटनाएं हुईं हैं। सवाल यह भी है कि यदि आत्महत्या रोकने के लिए गाइडलाइन है तो ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं।

साफ है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में ना तो किसी गाइडलाइन का पालन हो रहा, न ही इन घटनाओं को रोकने के लिए कोई इच्छाशक्ति दिखाई दे रही है। वहीं शिक्षा मंत्रालय का रवैया भी इसे लेकर सवालों के घेरे में है, क्योंकि गाइडलाइन के बाद उनसे संस्थानों में अमल को जांचने पर ध्यान नहीं दिया। यही वजह है कि संस्थानों में छात्रों की महीने भर में आत्महत्या की कई घटनाएं देखने को मिल रही हैं।

यूजीसी ने छात्रों की आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए इस साल जनवरी में गाइडलाइन तब जारी की थी, जब देश की कुल आबादी के करीब 10.6 प्रतिशत लोग मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित है, इनमें से 18 से 29 आयुवर्ग के करीब आठ प्रतिशत युवा गंभीर मानसिक स्वास्थ्य की समस्या से घिरे हुए है। वहीं एनसीआरबी (नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो) की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में कुल होने वाली आत्महत्याओं में करीब 7.6 प्रतिशत मामले छात्रों के हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र की मानसिक स्थिति पर नजर रखने के लिए प्रत्येक पांच सौ छात्रों पर एक मेंटर शिक्षक की तैनाती होगी।

किसी भी छात्र के अवसाद ग्रस्त दिखने पर तुरंत उसकी काउंसलिंग करेंगे। प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान को छात्रों की संख्या के अनुपात में मनोचिकित्सक भी तैनात करने होंगे। इस दौरान छात्रों को पढ़ाई से जुड़े तनाव को दूर करने के लिए जरूरी मदद दी जाएगी।

चार आत्महत्याओं के बाद कुरुक्षेत्र एनआइटी बंद, छात्रों में भय का माहौल

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र: पिछले दो महीनों में चार विद्यार्थियों की आत्महत्या के बाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआइटी) को बंद कर दिया गया है। इस स्थिति के कारण विद्यार्थियों में प्लेसमेंट से वंचित रहने का भय बढ़ गया है।

एनआइटी में तीसरे वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षाएं पांच-छह मई से शुरू होने वाली थीं, लेकिन अब ये परीक्षाएं अगस्त में होंगी। इससे जुलाई के अंत में कैंपस प्लेसमेंट के लिए आने वाली कंपनियों की चयन प्रक्रिया में ये विद्यार्थी अपनी जगह नहीं बना पाएंगे। इससे चिंतित विद्यार्थी एनआइटी प्रशासन से जल्द परीक्षाएं करवाने की गुहार लगा रहे हैं। इस अनदेखी को लेकर एक आडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है, प्रसारित आडियो में विद्यार्थी एनआइटी की महिला अधिकारी से परीक्षाएं समय पर करवाने की गुहार लगा रहे हैं और आफलाइन व आनलाइन किसी भी माध्यम से परीक्षा देने के लिए तैयार हैं।

'तीसरी बार गर्भधारण पर भी मिले मातृत्व अवकाश'

चेन्नई, प्रेट्र : मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार को मातृत्व लाभ, विशेष रूप से तीसरी गर्भावस्था के लिए कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश की स्वीकृति में कोई भेदभाव नहीं दिखाना चाहिए। पीठ ने कहा कि पहली, दूसरी हो या तीसरी गर्भावस्था हो उसमें पीड़ा समान होगी और महिलाओं को प्रसव पूर्व और प्रसव पश्चात देखभाल की आवश्यकता होती है। इसलिए, सरकार को तीसरी गर्भावस्था के लिए मातृत्व अवकाश की स्वीकृति में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं दिखाना चाहिए।

जस्टिस आर. सुरेश कुमार और एन.सेंथिल कुमार की एक पीठ ने 28 अप्रैल को शायी निशा की याचिका को स्वीकार करते हुए यह निर्णय दिया। पीठ ने 27 मार्च 2026 को विलुपुरम के प्रधान जिला न्यायाधीश के आदेशों को रद कर दिया, जिसने याचिकाकर्ता द्वारा 2 फरवरी, 2026 से एक फरवरी, 2027 तक मातृत्व अवकाश की मांग को अस्वीकार कर दिया था।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, पी-2, सैक्टर - ओमेगा-1, ग्रेटर नौएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर-201308 (उ0प्र0)
दूरभाष नं0 0120-2395153/57/58 टॉल फ्री नंबर : 18001808296, वेबसाइट : www.yamunaexpresswayauthority.com

पत्रांक : वाई.ई.ए./भूलेख/800/2026 — **सार्वजनिक सूचना** — दिनांक : 29.04.2026

निम्नलिखित भूमि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आपसी सहमति के आधार पर काश्तकारों से क्रय किया जाना प्रस्तावित है। क्रय हेतु काश्तकार, गाटा संख्या, क्षेत्रफल व काश्तकार का हिस्सा निम्नलिखित तालिका में अंकित है —

औद्योगिक सैक्टर-08, ग्राम दस्तमपुर

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	खसरा संख्या	खसरे का कुल क्षेत्रफल (है0 में)	खातेदार का नाम व पता	तहसील से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर काश्तकार का हिस्सा (है0 में)	काश्तकार का विक्रय हेतु क्षेत्रफल (है0 में)
1.	दस्तमपुर (सै0-8)	216	133	0.6900	श्रीमती चन्द्रकान्ता पत्नी अनूपचंद निवासी अब्दुलपुर माजरा मारेहरा	सम्पूर्ण भाग	0.6900

उपरोक्त भूमि क्रय किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो वह लिखित रूप में 15 दिन के अन्दर अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

डिप्टी कलेक्टर

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मास्टर प्लान के अतिरिक्त प्लॉटिंग/हाउसिंग/कॉलोनी या किसी भी प्रकार का अन्य निर्माण पूरी तरह से अवैध है। सामान्यजन इस प्रकार की खरीद - फरोख्त से पूर्णतः सचेत रहें तथा कॉलोनाइजर के भ्रामक विज्ञापनों से बचें। अधिक जानकारी के लिए प्राधिकरण की वेबसाइट www.yamunaexpresswayauthority.com देखें।

सुधार के नाम पर धर्म को खत्म नहीं किया जा सकता

- उत्तर भारत का कोई नास्तिक कैसे कर सकता है सबरीमाला में प्रवेश की मांग : सुप्रीम कोर्ट
- यह भी देखना होगा कि आस्थावान कर रहा अधिकार का दावा या गैर-आस्थावान

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह सुधार के नाम पर किसी धर्म को खत्म नहीं कर सकता और आस्था व अंतरात्मा से जुड़े मामलों को न्यायिक बहस का विषय नहीं बनाया जा सकता। शीर्ष अदालत ने सवाल उठाया कि उत्तर भारत का कोई नास्तिक सबरीमाला मंदिर में प्रवेश का अधिकार कैसे मांग सकता है? कोर्ट ने कहा कि मंदिरों में प्रवेश के अधिकार पर फैसला करते समय उसे यह भी देखना होगा कि अधिकार का दावा कोई आस्थावान कर रहा है या गैर-आस्थावान।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली नौ जजों की संविधान पीठ ने ये टिप्पणियां सबरीमाला मंदिर समेत विभिन्न धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव और विभिन्न धर्मों की धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे व सीमा से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कीं। पीठ ने कहा कि कुछ बातें समय के साथ स्पष्ट होकर धर्म का अनिवार्य हिस्सा बन गई हैं। कोर्ट ने यूसीसी लागू करने की संवैधानिक आकांक्षा का जिक्र किया और पूछा कि अगर सरकार इस संबंध में कानून बनाने में विफल रहती है, तो क्या न्यायपालिका ऐसा कर सकती है? पीठ में शामिल जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि अलग-अलग राज्यों ने विवाह व उत्तराधिकार संबंधी अधिकारों को रेगुलेट करने के लिए यूसीसी जैसे कानून बनाए हैं। जब समाज इसके लिए तैयार हो जाएगा, तब संसद भी इसे लागू कर देगी। सबरीमाला मंदिर में प्रवेश का अधिकार मांगने वाली दो महिलाओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने दलील दी कि हर राज्य ने मंदिरों में प्रवेश संबंधी कानून बनाए हैं। जस्टिस जोयमाल्या बागची ने पूछा कि गैर-हिंदू धार्मिक संस्थानों के संबंध में ऐसा कानून नहीं है; ऐसे में क्या अदालत गैर-हिंदू संस्थानों के लिए भी ऐसे निर्देश जारी कर सकती है, या उसे विधायिका के निर्णय का इंतजार करना चाहिए?

> सुधार के नाम पर धर्म को खोखला न करें... उन रीति-रिवाजों और परंपराओं को न छेड़ें जो सदियों से चली आ रही हैं। ऐसा करना किसी धर्म को खत्म करने जैसा होगा, जिसका हम हिस्सा नहीं बनना चाहते। अंतरात्मा के मामले किसी पंथनिरपेक्ष अदालत में बहस का विषय नहीं हो सकते।
>
> **- जस्टिस बीवी नागरत्ना**

'भोजशाला परिसर में मंदिर तोड़ मस्जिद बनाने का कोई साक्ष्य नहीं'

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला के धार्मिक स्वरूप को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में चल रही याचिकाओं पर बुधवार को भी सुनवाई जारी रही। मस्जिद पक्ष के वकीलों ने दावा किया कि ऐसा कोई साक्ष्य रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं है, जिससे साबित हो कि मस्जिद बनाने के लिए मंदिर तोड़ा गया था। सौ वर्ष से अधिक समय तक धार पर मुस्लिम शासकों का शासन रहा। इस दौरान उन्होंने कई इमारतों के निर्माण में मलबे का उपयोग हुआ। उनका आरोप है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) भोजशाला को लेकर चल रही याचिकाओं में अलग-अलग जवाब दे रहा है। मस्जिद में अगर श्लोक मिले हैं तो अरबी में उकेरी बातें भी मिली हैं। कोर्ट ने एएसआइ के वकील से कहा कि मस्जिद पक्ष के तर्क सुनने के बाद वे अपने तर्क रखें। मस्जिद पक्ष के एडवोकेट एनए शेख ने पुराने राजस्व रिकार्ड का हवाला देते हुए कहा कि पुराने खसरों के अवलोकन से स्पष्ट है कि सर्वे नंबर 313 राजस्व रिकार्ड में मस्जिद और सर्वे नंबर 312 मस्जिद वाला के नाम से दर्ज था।

कार्यालय जिलाधिकारी/लाईसेंस प्राधिकारी, हापुड़

संख्या 193/जि.आ.अधि./व्यवस्थापन/2026-27/हापुड़/ — दिनांक: 29 अप्रैल, 2026

विज्ञप्ति

वित्तीय वर्ष 2026-27 की आबकारी नीति विषयक शासनादेश संख्या-9/2026/82 ई-2/तेरह -2026-01/2026-2018003 दिनांक 12.02.2026 एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के अर्द्धशासकीय पत्रांक-2443-518/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति (संशो)/2026-2027 दिनांक: 12 फरवरी, 2026 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद हापुड़ में तृतीय चरण की ई-लाटरी से अवशेष देशी शराब की-01 दुकान-हरोडा एवं मॉडल शाप्स की-01 दुकान गढ़ रोड हापुड़ (मौहल्ला साकेत) का व्यवस्थापन आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 प्रयागराज के पत्र संख्या-1130-1204/दस-लाइसेंस 367/सुझाव आबकारी नीति (संशो.)/2026-27/दिनांक: 27.04.2026 द्वारा "ई-लाटरी का चतुर्थ चरण (ई-लाटरी के तृतीय चरण के पश्चात् व्यवस्थापन हेतु अवशेष समस्त दुकानों हेतु) वर्ष 2025-26 हेतु निर्धारित एम.जी.क्यू./निर्धारित बेसिक लाईसेंस फीस की दर/लाइसेंस फीस/वार्षिक राजस्व (जिसका मासिक/त्रैमासिक विभाजन यथास्थिति नीति के प्रस्तर-1.1.2 (ख) अथवा प्रस्तर-1.6.1 के अनुसार किया जायेगा।) के 85 प्रतिशत पर होगा", के आधार पर कराये जाने के निर्देश दिये गये है। किन्तु जनपद हापुड़ में तृतीय चरण की ई-लाटरी में आवंटित देशी शराब की 02 दुकान क्रमशः सबली, नानपुर देवली रोड के अनुज्ञापियों द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत दिनांक 28.04.2026 की सायं 05:00 बजे तक देयताओं को जमा नहीं करने पर अन्तिम रूप से व्यवस्थापन नहीं हो सका, जिस कारण देशी शराब की-02 दुकानों का व्यवस्थापन चतुर्थ चरण की ई-लाटरी में तृतीय चरण की ई-लाटरी हेतु देयताओं के आधार पर होगा। इस प्रकार जनपद में चतुर्थ चरण की ई-लाटरी हेतु **देशी शराब की-03 दुकानों एवं मॉडल शाप्स की-01 दुकान (कुल 04 दुकानों)** को ई-लाटरी हेतु सम्मिलित किया गया है।

ई-लाटरी हेतु आवेदन पत्र **दिनांक 30.04.2026 को (मध्यान्ह 12:00 बजे) से दिनांक 04.05.2026 को सायं 05:00 बजे)** तक ई-लाटरी पोर्टल **https://exciseelotteryup.upsdc.gov.in** पर ऑनलाइन आमंत्रित किये जाने हैं, तथा **दुकानों की ई-लाटरी दिनांक 07.05.2026 को समय प्रातः 11:00 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार हापुड़ में निर्धारित समय पर सम्पन्न की जायेगी।**

जनपद में देशी शराब एवं माडल शाप्स की फुटकर बिक्री की दुकानों को ई-लाटरी के माध्यम से प्राप्त करने हेतु इच्छुक आवेदक जनपद की दुकानों की सूची, अन्य आवश्यक विवरण एवं शर्तों सहित जनपद की वेबसाईट **https://hapur.nic.in** तथा ई-लाटरी पोर्टल **https://exciseelotteryup.upsdc.gov.in** पर देखी जा सकती है।

(कविता मीना), कलेक्टर/लाईसेंस प्राधिकारी, हापुड़

अमर उजाला

प्रवाह

78

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक

स्थापना : 18 अप्रैल 1948 • आगरा

नई दिल्ली ■ बृहस्पतिवार, 30 अप्रैल 2026

समय आ गया है कि टिकाऊ भविष्य के लिए हम नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करें।
-मार्था माएदा

ऐसे वक्त में, जब भू-राजनीतिक तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य पर अनिश्चितता पहले से ही तेल बाजार को अस्थिर बनाए हुए है, तब यूएई का ओपेक से बाहर निकलने का निर्णय वैश्विक ऊर्जा राजनीति में एक अहम मोड़ है। लेकिन यह स्थिति भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं के लिए नए दरवाजे खोल सकती है।

ओपेक में दरार

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) का खाड़ी के तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक और व्यापक ओपेक समूह से अलग होने का निर्णय सिर्फ एक सदस्य देश का प्रस्थान नहीं, बल्कि वैश्विक ऊर्जा राजनीति में एक अहम मोड़ है। यह उस तेल-व्यवस्था में आ रही दरारों का भी संकेत है, जो दशकों से दुनिया में कच्चे तेल की कीमतों को नियंत्रित करने में केंद्रीय भूमिका निभाती आ रही है। यह फैसला ऐसे समय आया है, जब पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव, होर्मुज जलडमरूमध्य पर अनिश्चितता और वैश्विक मुद्रास्फीति पहले से ही तेल बाजार को अस्थिर बनाए हुए है। जाहिर है कि इससे वैश्विक तेल कीमतों, ऊर्जा सुरक्षा और आयातक देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर असर से जुड़े कई सवाल उठ रहे हैं। दरअसल, यूएई लंबे समय से ओपेक की उत्पादन-सीमा नीति से असहज था। उसने पिछले कुछ वर्षों में अपने तेल उत्पादन ढांचे में भारी निवेश किया है, लेकिन ओपेक की उत्पादन सीमा नीति के चलते वह अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहा था और यही असंतोष उसके अलग राह चुनने का कारण माना जा रहा है। ओपेक से बाहर होने पर अब वह इसकी शर्तों से मुक्त होकर खुद ही यह तय कर सकता है कि उसे कब, किसे और कितना तेल बेचना है। चूंकि, यूएई ओपेक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक सदस्य देश था और समूह के उत्पादन में करीब 12 फीसदी का योगदान करता था, ऐसे में, उसका बाहर निकलना ओपेक की आपूर्ति क्षमता को प्रभावित जरूर करेगा। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। अगर ओपेक की शर्तों से मुक्त यूएई वैश्विक तेल बाजार को अतिरिक्त आपूर्ति करता है, तो इससे तेल की कीमतों में कमी आ सकती है। यह स्थिति भारत जैसे उन देशों के लिए विशेष तौर पर फायदेमंद है, जो ऊर्जा के आयात पर निर्भर हैं। गौरतलब है कि भारत अपने ऊर्जा सुरक्षा संबंधी लक्ष्यों से निपटने के लिए लंबे समय से ओपेक देशों से तेल के उत्पादन में बढ़ोतरी करने की मांग करता रहा है। इसकी कुल तेल जरूरतों का तकरीबन 40 फीसदी हिस्सा

ओपेक देशों पर निर्भर है और कुल तेल आयात का करीब दसवां हिस्सा यूएई से होता है। ऐसे में, अगर ओपेक की पकड़ ढीली होने से वैश्विक तेल बाजार अधिक प्रतिस्पर्धी बनता है, तो भारत को भी अपना आयात बिल घटाने, चालू खाते पर दबाव कम करने और महंगाई को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, यह देखते हुए कि वैश्विक ऊर्जा बाजार कभी भी स्थिर नहीं रहता, वह निरंतर भू-राजनीतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय बदलावों से प्रभावित होता रहता है, बेहतर होगा कि भारत समेत सभी आयातक देश इस अवसर का उपयोग अपनी ऊर्जा निर्भरता को कम करने में करें।

चुनौतियां अभी बाकी हैं

पश्चिम एशियाई संकट ने ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। पिछले एक दशक में भारत ने इस संबंध में जो भी रणनीतिक विकल्प बनाए हैं, उनसे कुछ हद तक मजबूती तो आई है, लेकिन वर्तमान चुनौतियों के मद्देनजर ढांचागत कमजोरियों को दूर करना ही होगा।

भुवन चंद्र त्रिपाठी
गेल के पूर्व सीएमडी

पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव ने एक बार फिर ऊर्जा सुरक्षा को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। जहां तक भारत की बात है, तो यह आपूर्ति पक्ष के तनाव की परीक्षा है, जो न सिर्फ बढ़ती कीमतों के एक और चक्र को, बल्कि हमारी गहरी ढांचागत कमजोरियों को भी उजागर करता है। यह एकीकृत राष्ट्रीय ऊर्जा नीति की आवश्यकता पर जोर देता है, ताकि अल्पकालिक आपूर्ति सुरक्षा और दीर्घकालिक ऊर्जा संक्रमण लक्ष्यों के बीच तालमेल बना रहे। यह मौजूदा और उभरते ईंधनों के बीच विकसित हो रहे ऊर्जा मिश्रण के बारे में स्पष्टता प्रदान करेगा।

आज भारत एक ऐसे अभूतपूर्व पथ पर अग्रसर है, जहां हम एक ही समय में ऊर्जा की पहुंच का विस्तार कर रहे हैं, कार्बन उत्सर्जन कम कर रहे हैं और औद्योगीकरण की गति को तेज कर रहे हैं। हमें पारंपरिक ऊर्जा नियोजन के बजाय एक एकीकृत नीतिगत दृष्टिकोण की आवश्यकता है। वैश्विक स्तर पर, ऊर्जा संक्रमण मौजूदा स्रोतों से हटकर नहीं हो रहा है, बल्कि सभी स्रोतों का विस्तार हो रहा है, जिसमें बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पारंपरिक ईंधनों के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को भी जोड़ा जा रहा है। भारत की संघीय संरचना को देखते हुए, ऊर्जा संक्रमण के परिणाम राज्य-स्तरीय कार्यान्वयन पर भी निर्भर करते हैं। निवेश को सुगम बनाने और तत्परता से लेकर, भूमि की उपलब्धता, ग्रिड की तैयारी और राज्य के टैरिफ डिजाइन तक, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ तालमेल बिठाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिलहाल, व्यापक स्तर पर यह व्यवस्था स्थिर प्रतीत होती है।

सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि हमारी आपूर्ति पर्याप्त है और मौजूदा व्यवधानों को संभाला जा सकता है। लेकिन जब हम उपभोक्ता स्तर पर देखते हैं, तो हमें तनाव के संकेत दिखाई देते हैं, विशेष रूप से एलपीजी की उपलब्धता में, जहां स्थानीय स्तर पर कमी सामने आई है और रिफिलिंग में

देरी हो रही है। भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का 60 फीसदी आयात करता है, जो कि सबसे ज्यादा संवेदनशील हिस्सा है, क्योंकि इसका लगभग 90 फीसदी हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर आता है। तेल के विपरीत, एलपीजी के लिए हमारे आपूर्ति के स्रोत अलग-अलग जगहों से नहीं थे, जिस वजह से मौजूदा संकट में आपूर्ति की आखिरी कड़ी पर काफी दबाव पड़ा। जैसे ही खाड़ी देशों से एलपीजी की आपूर्ति कम हुई, भारत ने एक ही हफ्ते में अमेरिका से लगभग 170,000 टन एलपीजी आयात की।

आज ऊर्जा राष्ट्रीय संप्रभुता का एक अहम मुद्दा है, जहां हमारी रणनीतिक प्राथमिकताएं बुनियादी ढांचे की सुरक्षा, आपूर्ति को सुरक्षित करना और उसकी निरंतरता सुनिश्चित करना होनी चाहिए। हम मूल रूप से आयात पर निर्भर हैं। हमारी कच्चे तेल की लगभग 90 फीसदी और प्राकृतिक गैस की लगभग 50 फीसदी जरूरतें दूसरे देशों से पूरी होती हैं। इसका एक बड़ा हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर आता है। आयात पर निर्भर व्यवस्था में आपूर्ति का जोखिम होता ही है। यह कोई यदा-कदा होने वाली घटना नहीं है। गैस और एलपीजी के मामले में, सीमित लचीलेपन और अविकसित भंडारण ढांचे के कारण, यह बात विशेष रूप से प्रासंगिक हो जाती है। पहले इस तरह के संकट ज्यादातर कीमतों में उतार-चढ़ाव की वजह से आते थे, लेकिन इस बार की रुकावट जितनी लागत से जुड़ी है, उतनी ही उपलब्धता से भी।

कतर भारत के 40 फीसदी से अधिक एलएनजी आयात की पूर्ति करता है, जिससे इस क्षेत्र में होने वाली किसी भी रुकावट का असर बेहद गंभीर हो जाता है। तरल ईंधनों के विपरीत, गैस और एलपीजी के लिए पर्याप्त भंडारण क्षमता की कमी इसे आपूर्ति में होने वाले अचानक के झटकों के प्रति अधिक संवेदनशील बना देती है। गैस के मामले में, भारत का मौजूदा लचीलापन कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह एक दशक पहले लिए गए उन रणनीतिक फैसलों का नतीजा है, जब तेल की कीमतें 110 डॉलर से ऊपर थीं। 2010 के आसपास हमने अपने दो मुख्य दबाव बिंदुओं को हल करने के प्रयास किए-कीमतों को तेल से अलग करना और भौगोलिक एकाग्रता।

कीमतों में आया बदलाव अहम था। बेहतर मूल्य-निर्धारण तंत्र और अनुबंध डिजाइन के जरिये करीब तीन अरब डॉलर की बचत हुई है। ये महत्वपूर्ण और बड़ी उपलब्धियां हैं, पर रणनीतिक गैस व एलपीजी भंडारण का अभाव एक ढांचागत कमजोरी बना हुआ है। गैस के लिए विशेष भंडारण बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है, जैसे कि भूमिगत गुफाएं, खाली जलाशय आदि, जिनमें अधिक पूंजी लगती है और वे भूवैज्ञानिक सीमाओं से बंधे होते हैं। इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से आपूर्ति में छोटी-मोटी रुकावटें भी किल्लत का कारण बन सकती हैं; सरकारी नीतियां बफर्स (सुरक्षित भंडार) बनाने के बजाय राशनिंग पर आधारित होती हैं; और समायोजन का मुख्य तंत्र औद्योगिक उत्पादन पर निर्भर करता है।

इस बीच, सुरक्षित भंडार बनाए रखने के लिए विभिन्न वैकल्पिक तरीकों पर भी विचार किया जा सकता है। लेकिन ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक समन्वित और बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसे केवल एक ही उपाय से पूरा नहीं किया जा सकता। सबसे पहले, हमें अपने घरेलू उत्पादन को मजबूत करना होगा। दूसरा, आपूर्ति में विविधीकरण। इससे भारत को लंबे समय तक ऊर्जा मिलती रहती है और आपूर्ति के स्रोत भी विविध हो जाते हैं। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर/लॉजिस्टिक्स पर नियंत्रण। चौथा, रणनीतिक भंडारण को प्राथमिकता देना। गैस/एलपीजी भंडारण के बुनियादी ढांचे की कमी अब एक वास्तविक एवं व्यावहारिक बाधा बन चुकी है। इस संदर्भ में, भारत को लचीलापन, पीकिंग सपोर्ट और बैकअप प्रदान करने के लिए संतुलनकारी ईंधनों की जरूरत है और यहीं पर प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने और अपने ऊर्जा मिश्रण में विविधता लाने की दिशा में काफी प्रगति की है। कार्बन उत्सर्जन में कमी और नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ाए जा रहे कदम आवश्यक और अनिवार्य हैं। मौजूदा संकट ऊर्जा और भू-राजनीति के बीच के जुड़ाव को दर्शाता है, और यह कोई असामान्य बात नहीं है। पिछले लगभग एक दशक में भारत ने विविधीकरण और मूल्य-निर्धारण के संबंध में जो रणनीतिक विकल्प अपनाए हैं, उनसे एक निश्चित स्तर की मजबूती पैदा हुई है, लेकिन इस मामले में अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है।

जीवन धारा

लुईस हे

गुलाब का फूल जब नन्ही कली होता है, वह तब भी सुंदर होता है। पूरा खिलने पर उसकी सुंदरता और निखर आती है। जब उसकी आखिरी पंखुड़ी गिर रही होती है, तब भी उसकी खूबसूरती अपने आप में अनोखी और देखने लायक होती है।

गुलाब के फूल जैसा बनने की कोशिश करें

अक्सर जीवन की भागदौड़ में हम यह भूल जाते हैं कि हम स्वयं के लिए कितने अनमोल हैं और कभी-कभी हमें लगता है कि हमारे अंदर खुद से प्यार करने की कमी है। ऐसे में, यह समझना जरूरी है कि यह नकारात्मक विचार हमारे भीतर आया कहां से। हम एक खुशहाल और मासूम बच्चे से, जिसे खुद पर पूरा भरोसा था, एक ऐसे दुखी इन्सान कैसे बन गए, जो खुद को कमतर समझता है और जिसे लगता है कि उसमें कोई न कोई कमी है? एक गुलाब के बारे में सोचिए। जब वह एक नन्ही कली होता है, तब भी वह सुंदर होता है। जब वह पूरा खिल जाता है, तब उसकी सुंदरता और निखर आती है। जब उसकी आखिरी पंखुड़ी गिर रही होती है, तब भी उसकी अपनी एक अनोखी खूबसूरती होती है।

हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही है। हम हमेशा पूर्ण, सुंदर और हर वक्त बदलते रहते हैं। हमारे पास जो समझ, जागरूकता और ज्ञान है, उसके आधार पर हम अपना सबसे अच्छा कर रहे होते हैं। जैसे-जैसे हमें और ज्यादा समझ, जागरूकता और ज्ञान मिलेगा, हम चीजों को अलग तरीके से और बेहतर करेंगे। अब समय आ गया है कि हम अपने अतीत को थोड़ा और गहराई से देखें, और उन मान्यताओं पर नजर डालें, जो अब तक हमें चला रही थीं। अगर आप किसी कमरे को अच्छी तरह से साफ करना चाहते हैं, तो आप उसमें रखी हर चीज को उठाकर देखेंगे और जांचेंगे। कुछ चीजों को आप प्यार से देखेंगे, और उन्हें पोंछकर नई सुंदरता देंगे। कुछ चीजें आपको ऐसी भी दिखेंगी, जिन्हें फिर से ठीक करने या मरम्मत की जरूरत है, और आप उन्हें ठीक करने के लिए एक नोट बना लेंगे। कुछ चीजें ऐसी भी होंगी, जिनकी अब आपको जरूरत नहीं रहेगी, तब उन्हें छोड़ देना ही सही रहेगा। ठीक यही प्रक्रिया हमारे मन के साथ भी लागू होती है। जो विचार और मान्यताएं अब हमारे काम की नहीं हैं, उन्हें छोड़ देना चाहिए। इसके लिए गुस्सा या संघर्ष करने की जरूरत नहीं है।

कुछ सीमित करने वाली मान्यताएं होती हैं, जैसे 'मैं अच्छा नहीं हूं।' यह अक्सर बचपन के अनुभवों से आती है-जैसे किसी का बार-बार यह कहना कि तुम पर्याप्त नहीं हो। ऐसे में, व्यक्ति जीवन भर किसी की स्वीकृति पाने के लिए संघर्ष करता रहता है, लेकिन भीतर का दर्द उसे बार-बार असफलता की ओर ले जाता है। कई बार हम किसी के प्रेम और स्वीकृति की चाह में खुद को ही खो देते हैं। आलोचना, तुलना और डर हमें यह विश्वास दिला देते हैं कि जीवन कठिन और खतरनाक है। पर सच्चाई यह है कि यह सब सीखी हुई धारणाएं हैं, और जो सीखा गया है, उसे बदला भी जा सकता है। अब समय है कि हम अपने मन को नए, सकारात्मक विचारों से भरें और खुद को उसी प्रेम और स्वीकृति के साथ देखें, जिसके हम हमेशा से हकदार रहे हैं।

-यू कैन हील योर लाइफ के अनूदित अंश

दायरों में बंधकर न रहें

सूत्र

हम हमेशा से पूर्ण और योग्य हैं, लेकिन पुराने अनुभवों और मान्यताओं ने हमें सीमित कर दिया है, अब समय है उन्हें पहचानकर छोड़ देने का, खुद को स्वीकार करने का, और नए सकारात्मक विचारों के साथ अपने जीवन को प्रेम, आत्मविश्वास तथा सच्ची खुशी से भरने का, क्योंकि जो बदला जा सकता है, वही हमारी नई शुरुआत बन सकता है।

दूसरा पहलू

आगरा के अजीम शायर ने जिंदगी को एक सफर बताया है और यही संदेश यूरोप तक फैले जिप्सी भी देते हैं।

नजीर, *बंजारानामा* और मंजिल की ओर बढ़ता मुसाफिर

क्या मसनद तकिया, मुल्क मकां, क्या चौकी, कुर्सी, तख्त-छतर।
सब ठाठ पड़ा रह जावेगा, जब लाद चलेगा बंजारा।

आगरा के अजीम शायर नजीर अकबराबादी ने जब *बंजारानामा* नज्म लिखी, तब उनके मन में मनुष्य की नश्वरता का भाव ही रहा होगा। वह कहना चाहते हैं कि सब कुछ यहीं रह जाएगा, बस मनुष्य अपने कर्मों की गठरी लादे किसी मुसाफिर की तरह अपनी मंजिल (मौत) की तरफ धीरे-धीरे बढ़ रहा है। इसी नज्म का यह छोटा-सा हिस्सा है। नजीर ने इन्सान की तुलना बंजारे से इसलिए की, क्योंकि उनका कोई घर नहीं होता। बंजारों पर दो बेहतरीन किताबें लिखी गई हैं, एक है डेविड मैकरिची की *अकाउंट्स ऑफ द जिप्सीज इन इंडिया*। दूसरी है, आरएल टर्नर की *द पोजीशन ऑफ द रोमानी इन इंडो-आर्यन*। फिरदौसी ने *शाहनामा* में लिखा है कि पांचवीं शताब्दी में सासानियन शासक बेहराम गुर ने दस हजार भारतीय बंजारों को फारस में रहने की पेशकश की थी। ये संगीत में निपुण थे। आठवीं शताब्दी में जब अरबों ने सिंध पर कब्जा किया, तो वहां रहने वाले बंजारे यूरोप और अफ्रीका तक चले गए। 810 ईस्वी में वे कुस्तुनतूनिया (मौजूदा इस्तांबुल) में देखे गए। बाइजेंटाइन इतिहासकारों ने उन्हें 'अथीनगनोई' कहा। 15वीं शताब्दी में बंजारे मिस्र में भी देखे गए।

भूपेंद्र कुमार

नजीर ने इन्सान की तुलना बंजारे से इसलिए की, क्योंकि उनका कोई घर नहीं होता। पूर्वी यूरोप के रोमा जिप्सी भी भारत से ही गए थे।

भारत के डोम, सिकलीगर, सांसी बंजारों का संबंध यूरोप के रोमाओं से माना जाता है। रोमानी भाषा की जड़ें संस्कृत में हैं और इसमें पंजाबी, राजस्थानी और हिंदी की झलक मिलती है।

यहां यह जानना दिलचस्प होगा कि रोमा जिप्सी, जो पूर्वी यूरोप में आज भी देखे जाते हैं, वे भी भारत से ही गए थे। 1427 ईस्वी में चेकोस्लोवाकिया (अब चेक और स्लोवाकिया अलग देश हैं) से जब जिप्सियों का पहला दल फ्रांस पहुंचा, तो उन्हें 'बोहेमियन' कहा गया। पुर्तगाल में उन्हें 'सिगोनोस' नाम दिया गया। डेनमार्क और स्वीडन में उन्हें 'तारतार' कहा गया। तुर्क उन्हें 'शिनगानी' कहते थे, यानी सिंधु नदी के मुहाने पर रहने वाली जनजाति। पर सबसे लोकप्रिय जिप्सी शब्द का उद्गम मिस्र (इजिप्ट) से माना जाता है। दूसरे विश्वयुद्ध में नाजियों ने इन पर कहर बरपाया।

भारत के डोम, सिकलीगर, सांसी बंजारों का संबंध यूरोप के रोमाओं से माना जाता है। रोमानी भाषा की जड़ें संस्कृत में हैं और इसमें पंजाबी, राजस्थानी और हिंदी की झलक मिलती है। 18वीं शताब्दी में जब आगरा में नजीर ने बंजारों को रूपक बनाकर लिखा, तो मानो वह पूरी दुनिया को ही नश्वरता और मुसाफिर बने रहने का संदेश दे रहे थे।

आंकड़े

संस्थागत प्रसव

भारत में पहले ज्यादातर बच्चे घर पर ही जन्म लेते थे, पर अब अधिकतर प्रसव अस्पतालों में होने लगे हैं। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बड़ी सफलता है।

2025-26	96.2
2021-22	95.5
2019-21	88.6
2007-08	46.9
2005-06	38.7

आंकड़े भारत में होने वाले संस्थागत प्रसव के, प्रतिशत में। | स्रोत : राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण

वृत्तासुर के वध के बाद शेष राक्षस समुद्र में छिपकर देवताओं और ऋषियों को सताने लगे, तब ऋषि अगस्त्य ने एक ही घूंट में समुद्र का सारा जल पी लिया।

देवताओं के संकटमोचक

पौराणिक कथाओं के अनुसार, ऋषि अगस्त्य का जन्म अत्यंत अद्भुत और दिव्य रूप से हुआ था। उन्हें 'घटयोनि' (घड़े से उत्पन्न) कहा जाता है, क्योंकि वह देवी उर्वशी को देखकर मित्र और वरुण देव के तेज से उत्पन्न हुए थे, जिसे एक दिव्य कलश (घड़े) में स्थापित किया गया था। अगस्त्य ऋषि तपस्वी और शिवभक्त थे। उन्होंने काशी में रहकर भगवान शिव की उपासना की और अपनी तपशक्ति से अनेक कार्य संपन्न किए।

एक बार की बात है। वृत्तासुर के वध के बाद शेष राक्षस समुद्र में छिपकर देवताओं और ऋषियों को सताने लगे, तब देवता अत्यंत चिंतित हुए। वे भगवान विष्णु के पास गए, जिन्होंने उन्हें अगस्त्य ऋषि की शरण में जाने को कहा। देवताओं की प्रार्थना सुनकर अगस्त्य ऋषि समुद्र तट पर पहुंचे। उन्होंने अपने योगबल और तप से समुद्र का सारा जल पी लिया। देखते ही देखते समुद्र का तल दिखाई देने लगा।

अंतर्यात्रा
संकलित

अब राक्षसों के पास छिपने का कोई स्थान नहीं बचा था। देवताओं ने तुरंत उन पर आक्रमण कर उनका संहार कर दिया और संसार को उनके भय से मुक्त किया। अगस्त्य ऋषि की यह अद्भुत लीला उनकी अपार तपशक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 30 अप्रैल, 1953

देश को अपना समझें न कि किसी दल को

जनतंत्र की सफलता जनता की जागरुकता पर निर्भर

देश में गरीबी का बोलबाला है

पटना की सभा में डाक्टर मुखर्जी का भाषण

भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि देश में गरीबी का बोलबाला है। जनता की जागरुकता पर ही जनतंत्र की सफलता निर्भर करती है। उन्होंने नागरिकों से कहा कि देश को अपना समझें, न कि किसी दल को।

बच्चे जाएं, तो जाएं कहां

मध्य प्रदेश में श्योपुर के हाईवे पर छोड़ी गई दो साल की बच्ची की घटना इस बात का प्रमाण है कि समाज में बच्चों की सुरक्षा और सम्मान, दोनों गंभीर खतरे में हैं।

क्षमा शर्मा

मुद्दा

हाल ही में, एक व्यापारी युगल ने दो साल की एक बच्ची को श्योपुर, मध्य प्रदेश के हाईवे पर छोड़ दिया। यह परिवार गुना में रहता है। बच्ची को अकेली देख, किसी भले इन्सान ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से उस कार को खोज निकाला, जिसने बच्ची को छोड़ा था। बच्ची को एक स्वयंसेवी संस्था के हवाले करके पुलिस ने इसकी जांच शुरू की, तो पता चला कि बच्ची को गोद लिया गया था। उसके असली माता-पिता मानते थे कि वह उनके लिए अशुभ है। जांच आगे बढ़ी, तो चौंकाने वाली बात पता चली कि दरअसल बच्ची को एक ब्यूटी पार्लर से एक लाख रुपये में खरीदा गया था, यानी बच्चों की खरीद-फरोख्त का कारोबार चल रहा था। इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हुईं।

जब से यह समाचार पढ़ा, तब से न जाने कितनी डरावनी बातें मन में उथल-पुथल मचाने लगीं। बच्ची के

माता-पिता कौन थे, वह कहां से आई, क्या उसे चुराया गया, जैसा कि अक्सर होता है। अपने देश में बच्चों की चोरी आम बात है। अस्पतालों तक से नवजात गायब हो जाते हैं। बच्ची हाईवे पर अकेली थी और यदि वह सड़क के बीच चली गई होती, तो गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाती, अथवा हाईवे से नीचे गिर सकती थी, किसी जंगली जानवर का शिकार बन जाती या उसका अपहरण हो जाता। कोई उसके साथ दुष्कर्म कर सकता था। उसे खरीदने वाले माता-पिता से कोई पूछे कि अगर ऐसा ही करना था, तो उसे अपनाया ही क्यों?

वैसे भी वे बच्चे, जिन्होंने अभी-अभी दुनिया में आंखें खोली हैं, उन्हें नहीं पता कि भविष्य क्या है। कोई उन्हें कूड़े के ढेर में फेंक देता है। कोई खेत में छोड़ जाता है। किसी को अस्पताल में ही छोड़कर भाग लिया जाता है। अपने जन्म के लिए ये मासूम बच्चे जिम्मेदार नहीं होते, लेकिन हर तरह की आफत इन्हीं के सिर आती है। ऐसे बच्चों में अधिसंख्य बच्चे वे होते हैं, जो अविवाहित मां की कोख से जन्म लेते हैं। समाज की इज्जत किसी की जान से भी ज्यादा है। विवाह के मंत्र नहीं पढ़े गए, इसलिए बच्चों को इस तरह जन्मते ही फेंकना कहां का न्याय है?

आपको याद ही होगा कि *महाभारत* की कथा में कर्ण ने कुंती को इस बात के लिए कभी माफ नहीं किया था। हालांकि, अकेली मां ही तो इसके लिए जिम्मेदार नहीं होती। एक तरफ हम बड़े अहंकार से क्षमा, दया, ममता, करुणा की बातें करते हैं, लेकिन इन बच्चों के मामले में ये सारे मूल्य कहां लोप हो जाते हैं?

ये बच्चे बड़े भी हो जाएं, तो भी इनमें से अनेक अपने जैविक माता-पिता की तलाश करते हैं। कई बच्चे, जो विदेशियों द्वारा गोद लिए गए, वे भारत में आकर ऐसा कर चुके हैं। वैसे भी अनाथालयों की हालत किसी से छिपी नहीं है। इसके अलावा, दुनिया के सारे रिश्ते ताऊ-ताई, चाचा-चाची, बुआ, दादा-दादी, नाना-नानी, मामा-मामी, उनके बाल-बच्चों से संबंध माता-पिता के कारण ही निर्धारित होते हैं। जरा सोचें, जिन बच्चों को जन्मते ही त्याग दिया गया, उनका कौन है?

एक बार किसी नवयुवक ने एक दिल दहलाने वाला अनुभव साझा किया था। उसने बताया कि वह एक अनाथालय में गया। वहां उसने एक बेहद कमजोर और बीमार बच्चे को देखा। जब अनाथालय के संचालक से इस बारे में पूछा, तो उसने हंसते हुए कहा कि उसके बारे में क्या पूछते हो! वह तो बस दो-चार दिन में मर जाएगा। उसकी बात सुनकर वह युवक विचलित हो उठा। वह हर रोज उस बच्चे को देखने जाने लगा। उसने बच्चे के इलाज की पेशकश भी की, मगर संचालक इसके लिए राजी नहीं हुआ। जब संचालक ने युवक को रोज आते देखा, तो उसने बच्चे को कहीं छिपा दिया, लेकिन युवक फिर भी नहीं माना। उसने पुलिस में शिकायत की। बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं उसने अर्जी दी कि वह बच्चे को गोद लेना चाहता है। तमाम भागदौड़ के बाद बच्चा उसे मिल सका। उचित देखभाल और लाड़-दुलार के कारण बच्चा ठीक होने लगा। वह ठीक से खाने-पीने भी लगा। उस युवक का कहना था कि उसके जीवन का मूल उद्देश्य बच्चे को अच्छी जिंदगी देना है। इसलिए वह उसकी जिम्मेदारी खुद उठाएगा। कभी विवाह नहीं करेगा। लेकिन समाज में ऐसे कितने लोग होंगे? जिस युगल ने बच्ची को इस तरह हाईवे पर अकेला छोड़ा, क्या उन्हें जरा-सी भी दया नहीं आई?

वे बच्चे, जिन्हें चुराया जाता है, उनमें से ऐसे कितने होंगे, जो अपने माता-पिता के पास वापस पहुंच सकते होंगे? एक तरफ बच्चों को फेंका जाता है, तो दूसरी तरफ उन्हें चुराया जाता है। आखिर वे जाएं, तो जाएं कहां।

edit@amarujala.com

ट्रंप के ईरान पर नाकेबंदी को आगे बढ़ाने के निर्देश ने आपूर्ति को लेकर बढ़ाई चिंता

कच्चा तेल एक माह के उच्च स्तर पर रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा

अमर उजाला ब्यूरो/एजेंसी

लंदन/मुंबई। होर्मुज जलडमरूमध्य मार्ग के जरिये आपूर्ति में लंबे समय तक बाधा की चिंताओं से बुधवार को वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें पांच फीसदी से अधिक बढ़कर एक महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गईं। कच्चे तेल में उछाल का असर भारतीय रुपये पर भी देखने को मिला और यह डॉलर के मुकाबले 20 पैसे टूटकर अपने अब तक के सबसे निचले स्तर 94.88 पर बंद हुआ।

दरअसल, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सहयोगियों को ईरान पर नाकेबंदी को और आगे बढ़ाने की तैयारी करने का निर्देश दिया है। इससे पश्चिम एशिया के इस अहम तेल उत्पादक क्षेत्र से आपूर्ति में रुकावटें और लंबे समय तक बनी रहने की आशंका है।

इस रिपोर्ट के बाद वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड की कीमतें 6.08 डॉलर या 5.5 फीसदी बढ़कर 117.34 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गईं। यह 31 मार्च के बाद ब्रेंट क्रूड का एक महीने का उच्च स्तर है। यूएस डब्ल्यूटीआई क्रूड भी 5.26 डॉलर या 5.3 फीसदी उछलकर 105.19 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया। इसके साथ ही, तेल में आठ दिनों से तेजी का सिलसिला जारी है।

रुपये में बना रहेगा उतार-चढ़ाव

क्रूड की कीमतों में उछाल के साथ विदेशी निवेशकों की लगातार पूंजी निकासी से भी बुधवार को रुपये में गिरावट आई। फॉरेक्स कारोबारियों ने कहा, क्रूड 115 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बना हुआ है, जिससे भारत के आयात खर्च पर असर पड़ने की आशंका है। पश्चिम एशिया संकट और इसके व्यापक संघर्ष में बदलने की आशंकाओं ने भी निवेशकों की चिंता बढ़ाई है। आने वाले समय में रुपये में उतार-चढ़ाव बना रहेगा।

■ अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 94.79 पर खुला और कारोबार के दौरान 94.88 के निचले स्तर तक गया। इससे पहले रुपया 27 मार्च को 94.85 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ था।

सोना 1,500 रुपये सस्ता

दिल्ली सराफा बाजार में बुधवार को सोना 1,500 रुपये सस्ता होकर 1,52,800 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर आ गया। सोने में यह गिरावट मुनाफावसूली के कारण आई, क्योंकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दर के बारे में फैसले से पहले कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने महंगाई को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। हालांकि, चांदी की कीमतों में 500 रुपये की तेजी देखी गई और यह 2,44,500 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव बंद हुई।

सेंसेक्स 609 अंक चढ़ा, एग्जिट पोल का दिखेगा असर

एशियाई बाजारों में मजबूती और एफएमसीजी, वाहन एवं दूरसंचार शेयरों में खरीदारी से बुधवार को सेंसेक्स उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में 609.45 अंक उछलकर 77,496.36 पर बंद हुआ। दिन में यह 1,095.6 अंक तक चढ़ गया था। निफ्टी 181.95 अंक बढ़कर 24,177.65 पर बंद हुआ।

■ **बीएनके कैपिटल के रिसर्च हेड रचित खंडेलवाल ने कहा,** एग्जिट पोल के नतीजों में बंगाल में भाजपा के प्रति झुकाव के साथ त्रिशंकु विधानसभा की संभावना और केरल में कांग्रेस की जीत का अनुमान जताया गया है। ये अनुमान बाजारों में एक सकारात्मक भावना पैदा कर रहे हैं।

एनपीएस संचय से करोड़ों कामगारों का सुरक्षित होगा भविष्य

पीएफआरडी की पूरी तैयारी...जल्द लॉन्च होगी योजना, पेंशन के दायरे में आएंगे असंगठित क्षेत्र के कामगार

शुभम शंखधर

नई दिल्ली। देश में लंबे समय तक पेंशन को एक ऐसी सुविधा माना गया, जो सिर्फ सरकारी या बड़ी कंपनियों में काम करने वालों तक सीमित रही। लेकिन, बदलते आर्थिक परिदृश्य में अब यह सोच तेजी से टूट रही है।

पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) इसी दिशा में अहम कदम उठाते हुए एनपीएस संचय शुरू करने जा रहा है। योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के करोड़ों कामगारों को पेंशन के दायरे में लाना है।

पीएफआरडीए के चेयरमैन एस रमन ने अमर उजाला बोनस को विशेष बातचीत में कहा, एनपीएस संचय राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के ढांचे पर आधारित है। इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। जल्द ही यह देशभर में लॉन्च होगी। योजना की बड़ी खासियत इसकी सरलता है। आमतौर पर निवेश में इक्विटी, डेट और सरकारी बॉन्ड्स के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन, एनपीएस संचय में यह जिम्मेदारी खुद सिस्टम निभाएगा।

50 करोड़ कामगारों के लिए बनेगी उम्मीद

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, देश में करीब 50 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र से जुड़े हैं। केंद्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर 31.63 करोड़ श्रमिक पंजीकृत हैं, जो पीएफ और ईएसआई के दायरे में नहीं आते। **रिटायरमेंट के बाद इनके पास नियमित आय का कोई साधन नहीं है, जिनमें 54 फीसदी से अधिक महिलाएं हैं।** असंगठित क्षेत्र के कामगारों में रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, छोटे दुकानदार, दिहाड़ी मजदूर और कृषि कार्यों से जुड़े श्रमिक शामिल हैं, जो अक्सर रिटायरमेंट प्लानिंग से दूर रह जाते हैं। एनपीएस संचय इन्हीं लोगों के लिए एक उम्मीद बनकर उभरेगी।

सरकारी कर्मियों के एनपीएस मॉडल की तर्ज पर काम करेगी नई योजना

पीएफआरडीए चेयरमैन के मुताबिक, यह योजना सरकारी कर्मचारियों के एनपीएस मॉडल की तरह ही काम करेगी, जहां फंड का एलोकेशन पहले से तय अनुपात में होता है। इससे निवेशकों को यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कब और कितना दलाव करना है। इसका सीधा फायदा यह होगा कि असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी भी नियमित बचत और निवेश के जरिये एक सुरक्षित रिटायरमेंट फंड तैयार कर सकेंगे।

एनपीएस संचय सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह उन लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास है, जिनके पास रिटायरमेंट के बाद नियमित आय के साधन नहीं हैं। **-एस रमन, चेयरमैन, पीएफआरडीए**

ईरान युद्ध से महंगाई और व्यापार पर बढ़ा जोखिम

वित्त मंत्रालय ने रिपोर्ट में जताई चिंता...कहा, मजबूत घरेलू मांग और निवेश से मिल रहा सहारा

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से आपूर्ति पक्ष को बड़ा झटका लगने से महंगाई, व्यापार और वित्तीय प्रवाह पर जोखिम बढ़ गया है। हालांकि, मजबूत घरेलू मांग, नीतिगत समर्थन, सुदृढ़ वित्तीय प्रणाली और सार्वजनिक निवेश से अर्थव्यवस्था को कुछ हद तक सुरक्षा मिलेगी।

वित्त मंत्रालय ने बुधवार को जारी अप्रैल की मासिक आर्थिक समीक्षा में कहा, ऊर्जा और उर्वरक आपूर्ति को लेकर लंबी अनिश्चितता देश की वृहद आर्थिक स्थिरता की मजबूती की परीक्षा ले सकती है। रिपोर्ट में ईरान संकट के बीच आपूर्ति पक्ष से जुड़े झटके की चेतावनी देते हुए कहा गया है कि बढ़ती कीमतों और आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार धीमी होने से मांग में कमी भी चिंता का विषय है। कंपनियों के बढ़ती लागत का बोझ उपभोक्ताओं पर डालने से महंगाई बढ़ने का भी खतरा बना हुआ है। इसका असर कच्चे माल से अंतिम उत्पाद बनाने वाले प्रसंस्करण और विपणन उद्योगों पर व्यापक रूप से पड़ेगा। एजेंसी

अल नीनो का असर भी बढ़ा सकता है चुनौतियां

रिपोर्ट में अल नीनो के प्रभाव से इस साल दक्षिण-पश्चिम मानसून सामान्य से कम रहने की आशंका जताई गई है। ऐसा होने से अधिकांश जिलों में औसत से कम बारिश हो सकती है। मंत्रालय ने कहा, खाड़ी क्षेत्र में तेल एवं गैस के आपूर्ति ढांचे को सामान्य होने में कई महीने लग सकते हैं। अगर इसके साथ कमजोर मानसून भी जुड़ता है, तो महंगाई का दबाव और बढ़ सकता है।

न्यूज डायरी

ईरान युद्ध के कारण टल सकता है जियो का आईपीओ

नई दिल्ली। क्रेडिटसाइट्स ने बुधवार को कहा, रिलायंस इंडस्ट्रीज की डिजिटल इकाई जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ ईरान युद्ध के कारण 2026-27 की दूसरी छमाही तक टल सकता है। रिलायंस प्रबंधन ने संकेत दिया था कि इश्यू जल्द आ सकता है, लेकिन निश्चित तारीख नहीं बताई गई। आईपीओ के मई में आने की चर्चा है। एजेंसी

मीशो को 14.29 करोड़ का जीएसटी नोटिस

नई दिल्ली। ई-कॉमर्स मंच मीशो को 14.29 करोड़ का जीएसटी मांग नोटिस मिला है। कंपनी ने बताया, उसे 29 अप्रैल को अक्तूबर, 2018 और मार्च, 2020 के बीच कुछ विक्रेता लेनदेन पर स्रोत पर जुटाए कर मामले में सीजीएसटी थाणे कमिश्नरेट के कमिश्नर से नोटिस मिला है। वह आदेश को चुनौती देगी। ब्यूरो

बजाज फाइनेंस देगी छह रुपये का लाभांश

नई दिल्ली। बजाज फाइनेंस का वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में शुद्ध मुनाफा 22 फीसदी बढ़कर 5,553 करोड़ रुपये पहुंच गया। कुल आय में 21 फीसदी वृद्धि रही। कंपनी ने बुधवार को बताया, उसके बोर्ड ने 2025-26 के लिए 6 रुपये प्रति शेयर लाभांश देने की सिफारिश की है। एजेंसी

बैंक प्राकृतिक आपदा में कर्जदारों को खुद दे सकेंगे राहत : आरबीआई

मुंबई। आरबीआई ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत उपायों पर संशोधित दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा, बैंक अब उधारकर्ताओं के अनुरोध का इंतजार किए बिना ही उन्हें राहत दे सकेंगे। नए नियम एक जुलाई, 2026 से लागू होंगे।

केंद्रीय बैंक ने नए निर्देश में कहा, कर्जदाताओं को सभी पात्र उधारकर्ताओं को अपने स्तर पर ही राहत देने की अनुमति होगी। हालांकि, ग्राहक चाहें तो प्राकृतिक आपदा घोषित होने के 135 दिनों के भीतर इससे बाहर निकल सकते हैं। नए नियम वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, एनबीएफसी, लघु वित्त बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों पर लागू होंगे। नए नियमों के तहत, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बैंक अस्थायी परिसरों से शाखाएं चला सकेंगे। सैटेलाइट ऑफिस, एक्सटेंशन काउंटर या मोबाइल बैंकिंग के जरिये सेवाएं बहाल कर सकेंगे। आरबीआई ने कहा, बैंक अपने विवेक से एक वर्ष तक शुल्क और अन्य मदों में छूट या कटौती कर सकते हैं। राहत सिर्फ उन खातों को मिलेगी, जो स्टैंडर्ड श्रेणी में हैं और आपदा के समय 30 दिन से अधिक बकाया में नहीं थे। बैंकों को ऐसे खातों पर बकाया कर्ज का अतिरिक्त पांच फीसदी प्रावधान करना होगा। एजेंसी

विजय आनंद होंगे सिटी यूनियन बैंक के नए एमडी-सीईओ

नई दिल्ली। विजय आनंद एक मई से सिटी यूनियन बैंक के एमडी-सीईओ का कार्यभार संभालेंगे। उनके पास बैंकिंग क्षेत्र में तीन दशक का अनुभव है। वह आईसीआईसीआई बैंक, बार्कले और आरबीएल बैंक जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। पिछले दो वर्षों से सिटी यूनियन बैंक से जुड़े रहे हैं। ब्यूरो

सोने में निवेश मांग ने पहली बार आभूषणों को पीछे छोड़ा

विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट...देश में बदल रहा सोने की मांग का रुझान, मार्च तिमाही में कुल मांग 151 टन

नई दिल्ली। देश में सोने की मांग इस साल जनवरी-मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 10 फीसदी बढ़कर 151 टन पहुंच गई। इसकी प्रमुख वजह सोने की कीमतों में तेज उछाल के बीच निवेश मांग में मजबूत वृद्धि है। इसके साथ ही, भारत में सोने में निवेश की मांग ने पहली बार आभूषणों की खरीद को पीछे छोड़ दिया। विश्व स्वर्ण परिषद (डब्ल्यूजीसी) ने बुधवार को जारी रिपोर्ट में कहा, देश में सोने की मांग का रुझान बदल रहा है। अब आभूषण के बजाय निवेश के लिए खरीदारी तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि जनवरी-मार्च तिमाही में सोने की छड़ों, सिक्कों और ईटीएफ (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड) के जरिये निवेश मांग 54 फीसदी बढ़कर 82 टन पहुंच गई, जबकि आभूषण की मांग 19 फीसदी घटकर 66 टन रह गई। **पूरे वर्ष में सोने की मांग 650-750 टन के बीच रहने का अनुमान है। 2025 में यह 712 टन रहा था।** ब्यूरो

तीन माह में 2.27 लाख करोड़ की खरीद

मूल्य के लिहाज से 2026 की जनवरी-मार्च तिमाही में सोने की कुल मांग सालाना आधार पर 99 फीसदी बढ़कर 2,27,500 करोड़ रुपये (25 अरब डॉलर) के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। आभूषणों की मांग भी एक साल पहले के 68,050 करोड़ रुपये से 47 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 99,920 करोड़ रुपये पहुंच गई।

सोने की छड़ों, सिक्कों और ईटीएफ में 437% तक वृद्धि

मूल्य के लिहाज से सोने की छड़ों और सिक्कों की मांग जनवरी-मार्च तिमाही में 142 फीसदी बढ़कर 94,130 करोड़ रुपये पहुंच गई। गोल्ड ईटीएफ में 30,000 करोड़ रुपये का निवेश आया, जो सालाना आधार पर 437 फीसदी अधिक है।

■ सोने का कुल आयात 39 फीसदी बढ़कर 196.4 टन पहुंच गया।

■ **मार्च तिमाही में दुनियाभर के केंद्रीय बैंकों ने कुल 244 टन सोने की खरीदारी की।**

अमर उजाला **Job Alert**
Real-time job alerts
amarujala.com/jobs

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अप्रेंटिसशिप के लिए योग्य उम्मीदवार करें आवेदन

1865 पद

आवेदन की अंतिम तिथि : 19 मई, 2026
आयु-सीमा : न्यूनतम 20 वर्ष व अधिकतम 28 वर्ष निर्धारित
यहां आवेदन करें : unionbankofindia.co.in

यूपीएसएसएससी, लखनऊ ■ 243 पद
प्लाटून कमांडर व अन्य पदों पर आवेदन आमंत्रित
आवेदन की अंतिम तिथि : 06 जुलाई, 2026
योग्यताएं : स्नातक व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें : upsssc.gov.in

पीजीआईएमईआर में रिक्तियां ■ 134 पद
सीनियर रेजिडेंट व अन्य पदों पर निकली भर्ती
आवेदन की अंतिम तिथि : 11 मई, 2026
आयु-सीमा : अधिकतम उम्र 45 वर्ष निर्धारित
यहां आवेदन करें : pgimer.edu.in

मेकॉन लिमिटेड में मौके ■ 103 पद
इंजीनियर व असिस्टेंट इंजीनियर के पद रिक्त
आवेदन की अंतिम तिथि : 11 मई, 2026
योग्यताएं : बीई/बीटेक व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें : careers.meconlimited.co.in

भारतीय रिजर्व बैंक ■ 60 पद
ग्रेड-बी ऑफिसर के पदों पर रोजगार के अवसर
आवेदन की अंतिम तिथि : 20 मई, 2026
आयु-सीमा : न्यूनतम 21 वर्ष व अधिकतम उम्र 30 वर्ष निर्धारित
यहां आवेदन करें : ibpsreg.ibps.in/rbisbmar26/

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ■ 10 पद
डिप्टी मैनेजर के पदों पर नौकरी के मौके
आवेदन की अंतिम तिथि : 12 मई, 2026
योग्यताएं : बीई/बीटेक/बीएससी व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें : engineersindia.com

योग्य उम्मीदवार करें आवेदन ...
रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड : कंसल्टेंट का पद रिक्त।
- आवेदन की अंतिम तिथि : 16 मई, 2026
- railtel.in/careers

भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल : प्रधान तकनीकी अधिकारी आदि के पद खाली।
- आवेदन की अंतिम तिथि : 10 मई, 2026
- iiserb.ac.in

अपनी प्रतिक्रियाओं और सुझावों के लिए हमें udaan@amarujala.com पर ई-मेल करें।

एजुकेशन & कॅरिअर

आपको पूरी सीढ़ी देखने की जरूरत नहीं है, बस पहला कदम उठाएं।

बोर्ड नतीजों के बाद आगे की राह

दसवीं के बाद विषयों के चुनाव में दुविधा स्वाभाविक है, ऐसे में अभिभावकों की भूमिका बेहद अहम हो जाती है।

सुनंदा राव
कॅरिअर सलाहकार

बोर्ड परीक्षा के परिणाम आ चुके हैं। कुछ छात्र अपने आगे के लक्ष्य और विषय तय कर चुके होंगे, लेकिन कइयों के सामने अब भी सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि आगे क्या पढ़ें और कौन-से विषय चुनें। यह दुविधा स्वाभाविक है, क्योंकि दसवीं के बाद लिया गया निर्णय केवल दो साल की पढ़ाई तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आगे की उच्च शिक्षा, कॅरिअर और जीवन की दिशा भी तय करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस उम्र में लिया गया फैसला बच्चों के आत्मविश्वास और भविष्य दोनों को गहराई से प्रभावित करता है। ऐसे में माता-पिता और अभिभावकों की भूमिका बेहद अहम हो जाती है।

■ बच्चों से करें खुलकर बात

14-15 वर्ष की उम्र में बच्चों के लिए अपने भविष्य की स्पष्ट योजना बनाना आसान नहीं होता। ऐसे में अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों से खुलकर बातचीत करें और उनकी रुचि, शौक तथा पसंद को समझें। कई बार बच्चे अपने मन की बात सीधे नहीं कह पाते, इसलिए उनसे मित्रवत व्यवहार करना जरूरी है। यह बच्चों की रुचि के क्षेत्रों को समझने और उन पर चर्चा करने का एक रचनात्मक तरीका हो सकता है।

■ हर बच्चा है खास

हर बच्चे की सोच अलग होती है और उसके सपने भी अलग होते हैं। जरूरी नहीं कि वह वही विषय चुने जो माता-पिता चाहते हैं। अभिभावक उन्हें सही दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन अपने विचार थोपने से बचना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, यदि बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है, तो उसे गणित चुनने की सलाह दी जा सकती है। लेकिन अंतिम निर्णय बच्चे का ही होना चाहिए। सही मार्गदर्शन और सहयोग से ही बच्चे अपने भविष्य की मजबूत नींव रख सकते हैं।

■ काउंसलर की लें मदद

स्कूल के कॅरिअर काउंसलर बच्चों को सही दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यदि स्कूल में काउंसलर उपलब्ध हैं, तो बच्चों को उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए प्रोत्साहित करें। साथ ही, जिन क्षेत्रों में बच्चे की रुचि हो, उन क्षेत्रों में कार्य कर रहे लोगों से बातचीत करवाना भी फायदेमंद हो सकता है। इससे बच्चों को वास्तविक अनुभव और स्पष्टता मिलती है।

- *दसवीं के बाद विषयों का चयन बच्चों के भविष्य, कॅरिअर व उच्च शिक्षा को प्रभावित करता है।*
- *अभिभावक बच्चों से खुलकर बात करें और उनकी रुचि, शौक तथा पसंद को समझें।*
- *बच्चे के लक्ष्य को ध्यान में रखकर विषयों का चयन किया जाए।*
- *सही मार्गदर्शन और सहयोग से ही बच्चे अपने भविष्य की मजबूत नींव रख सकते हैं।*

■ ऐसे करें विषयों का चयन

अभिभावकों को यह समझना चाहिए कि उनका बच्चा स्कूल के अंतिम दो वर्षों में क्या हासिल करना चाहता है। क्या वह विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए उच्च अंक प्राप्त करना चाहता है, या फिर किसी व्यावसायिक और कौशल आधारित क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है? आज के समय में पढ़ाई और कॅरिअर के कई विकल्प उपलब्ध हैं। इसलिए यह जरूरी है कि बच्चे के लक्ष्य को ध्यान में रखकर विषयों का चयन किया जाए।

इंटर्नशिप प्रोग्राम

एप मार्केटिंग इंटर्नशिप

- **संस्थान :** सरज इनोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
- **अवधि :** दो माह
- **स्टाइपेंड :** रुपये 25000 प्रतिमाह
- **लाभ :** इंटर्नशिप प्रमाणपत्र, व्यावहारिक अनुभव आदि
- **आवेदन की अंतिम तिथि :** 14 मई, 2026
- **आधिकारिक लिंक :** tinyurl.com/3r996ywt

आवेदन आमंत्रित

जॉब इंटरव्यू- टिप्स टू गेट सिलेक्टेड

- **पहल :** एनएसडीसी अकादमी
- **पात्रताएं :** 12वीं पास, आईटीआई, डिप्लोमा
- **आयु :** 14 वर्ष से अधिक
- **कार्यक्षेत्र :** कार्यालय प्रबंधन एवं व्यावसायिक कौशल
- **प्रमाणन प्रकार :** सहभागिता का प्रमाणपत्र
- **भाषा :** अंग्रेजी
- **आधिकारिक लिंक :** tinyurl.com/36955eeu

एग्जाम अलर्ट

जेएसएससी इंटरमीडिएट शिक्षक परीक्षा

- **परीक्षा की तिथि :** 05-07 मई, 2026
- यह परीक्षा तीन पत्र के लिए आयोजित की जाएगी। पत्र-एक व पत्र-दो से 100-100 अंकों के 100-100 प्रश्न व पत्र-तीन में 200 अंकों के 200 प्रश्न पूछे जाएंगे।
- **यहां से प्रवेश-पत्र डाउनलोड करें** jssc.jharkhand.gov.in

आरआरबी एनटीपीसी इंटर लेवल परीक्षा

- **परीक्षा की तिथि :** 07-09 मई, 2026 (संभावित)
- इस परीक्षा में सामान्य जागरूकता से 40 प्रश्न, गणित से 30 प्रश्न व सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि एक घंटा तीस मिनट निर्धारित है।
- **यहां से प्रवेश-पत्र डाउनलोड करें** tinyurl.com/yz3sxz8w

खुद को परखें

1. हाल ही में खबरों में देखने को मिले 'पुष्कर्मेमा कुराज' का मतलब क्या है?
   (a) सायनोबैक्टीरिया की नव-खोजी प्रजाति
   (b) आक्रामक खरपतवार
   (c) दुर्लभ औषधीय पौधा
   (d) मछली की नव-खोजी प्रजाति
2. बेनी मेनाशे समुदाय मुख्य रूप से भारत के किन राज्यों में पाया जाता है?
   (a) राजस्थान और गुजरात
   (b) उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश
   (c) झारखंड और बिहार
   (d) मिजोरम और मणिपुर
3. मौसम मिशन के अंतर्गत किस संस्थान ने महाबलेश्वर में एक्स-बैंड डॉप्लर मौसम रडार स्थापित किया है?
   (a) क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (RMC), मुंबई
   (b) भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे
   (c) भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD), पुणे
   (d) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

उत्तर : 1.a, 2.d, 3.b

आज का दिन

30 अप्रैल,1897

ब्रिटिश वैज्ञानिक जे. जे. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन, जिसे उन्होंने 'कणिका' कहा था की खोज की थी। इस खोज से भौतिकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आया।

- ■ 1789 : जॉर्ज वाशिंगटन ने पहले अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी।
- ■ 1933 : गीतकार और गिटारवादक विली नेल्सन का जन्म हुआ था।
- ■ 1939 : अमेरिका में पहला सार्वजनिक टेलीविजन प्रसारण हुआ था।
- ■ 1945 : जर्मन तानाशाह हिटलर ने आत्महत्या की थी।

व्रत त्योहार

आज : वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्दशी।
कल : वैशाख (बुद्ध)पूर्णिमा, वैशाख स्नान पूर्ण, ग्रीष्म ऋतु, सूर्य उत्तरायणे, उत्तर गोले।
राहुकाल : प्रातः 10.30 से 12.00 तक।

■ सूर्योदय : 05.44
■ सूर्यास्त : 18.52
(भारतीय मानक समयानुसार)

कल का पंचांग

विक्रमी संवत 2083, 11 वैशाख मास शक 1948, वैशाख मास 18 प्रविष्टे, 13 जिल्काद हिजरी 1447, वैशाख पूर्णिमा 22.52 तक उपरांत प्रथम ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष प्रतिपदा, स्वाती नक्षत्र 28.34 तक उपरांत विशाखा नक्षत्र, सिद्धि योग 21.12 तक उपरांत व्यतिपात योग, विष्टि (भद्रा) करण 10.02 तक उपरांत बव करण, चंद्रमा तुला राशि में दिन-रात।

राशिफल

amarujala.com/astrology
■ पं. विनोद त्यागी

मेष : स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कार्य विशेष में सफलता संदिग्ध रहेगी। नौकरी में स्थिति सामान्य रहेगी।

वृष : अनजानी आशंका बनी रहेगी। नौकरी में मान-सम्मान बना रहेगा। विरोधी परास्त होंगे।

मिथुन : पूर्वनियोजित कार्य में व्यस्त रहेंगे। नौकरी में दौड़-भाग अधिक रहेगी। अनैतिक कार्य से दूर रहें।

कर्क : सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा। अटका कार्य बनेगा। राजकाज में अनुकूलता रहेगी।

सिंह : अतिउत्साह पर नियंत्रण रखें। नौकरी में उन्नति के संकेत मिल सकते हैं। आर्थिक दबाव बना रहेगा।

कन्या : मानसिक उत्तेजना पर नियंत्रण रखें। बनता कार्य अटक सकता है। व्यवसाय में विस्तार होगा।

तुला : मानसिक उहा पोह बना रहेगा। विरोधी पक्ष से सावधानी बरतें। नौकरी में स्थिति सामान्य रहेगी।

वृश्चिक : राजनीतिक क्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा। अचानक अर्थ प्राप्ति हो सकती है। योजना सफल होगी।

धनु : आत्मबल बनाए रखें। नौकरी में नया कार्य भार आ सकता है। भौतिक सुख-साधनों पर व्यय होगा।

मकर : दिनमान सामान्य रहेगा। नौकरी में धैर्य बनाए रखें। संतान पक्ष से शुभ सूचना मिल सकती है।

कुंभ : मानसिक तनाव से बचें। आर्थिक स्थिति यथावत रहेगी। नौकरी में मन नहीं लगेगा।

मीन : मानसिक उत्तेजना एवं वाणी पर नियंत्रण रखें। नौकरी में उन्नति हो सकती है। व्यवसाय में लाभ होगा।

सुडोकू

	8	2			5	4		
7	3	4	2					
5			8			6		
				5	9			
1	2	6		7		9	3	5
			6	2				
		1			3			6
					4	2	8	9
		7	5			3	1	

सुडोकू 81 वर्गों का ग्रिड है, जो 9 वर्गों के ब्लॉक में बंटा हुआ होता है। कुछ वर्गों के अंक लिखे हैं और खाली वर्गों में 1 से लेकर 9 तक के अंक लिखने होते हैं। कोई नंबर 1 पंक्ति, कॉलम या 9 वर्ग वाले छोटे ब्लॉक में दोबारा नहीं आ सकता है।

उत्तर

6	8	2	1	3	5	4	9	7
7	3	4	2	9	6	8	5	1
5	1	9	8	4	7	6	2	3
4	7	8	3	5	9	1	6	2
1	2	6	4	7	8	9	3	5
9	5	3	6	2	1	7	4	8
2	4	1	9	8	3	5	7	6
3	6	5	7	1	4	2	8	9
8	9	7	5	6	2	3	1	4

दैनिक जागरण
परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है

छात्रों की आत्महत्याएं

यह समय की मांग थी कि उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की आत्महत्या को लेकर शिक्षा मंत्रालय सभी संस्थानों को सतर्क करते हुए उन्हें छात्रों की काउंसिलिंग करने और तय एसओपी अर्थात मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करने को कहता, लेकिन केवल इतना ही पर्याप्त नहीं। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में वह तंत्र पर्याप्त क्षमता, संवेदनशीलता और संसाधनों के साथ सक्रिय है या नहीं, जिस पर अवसाद ग्रस्त या किसी अन्य समस्या से घिरे छात्रों की काउंसिलिंग करने का उत्तरदायित्व होता है। उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों की आत्महत्याओं पर समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर चिंता जताने और उन्हें रोकने की आवश्यकता पर बल देने के बाद भी बात बनती दिख नहीं रही है। यह सामान्य बात नहीं कि आइआइटी खड़गपुर में पिछले डेढ़ वर्ष में नौ छात्रों ने आत्महत्या की। इसी तरह एनआइटी कुरुक्षेत्र में बीते दो महीनों में तीन छात्रों और एक छात्रा ने अपनी जान दे दी। इन दोनों शिक्षा संस्थानों में इतने कम समय में इतने अधिक विद्यार्थियों की आत्महत्या सामान्य बात नहीं। दुर्भाग्य से विभिन्न शिक्षा संस्थानों में छात्रों की आत्महत्या के मामले रह-रहकर सामने आते ही रहते हैं। ये मामले यही बताते हैं कि हमारे उच्च शिक्षा संस्थानों और विशेष रूप से उनके छात्रावासों में वैसा स्वस्थ और सकारात्मक वातावरण नहीं कि किसी कारण से परेशान कोई छात्र अपने प्राण त्यागने जैसा अतिवादी कदम न उठाने पाए।

छात्र-छात्राएं भिन्न-भिन्न कारणों से आत्महत्या करते हैं। कोई परीक्षा में लगातार असफलता से निराश होकर अपनी जान दे देता है, कोई नए माहौल में खुद को समायोजित न कर पाने के कारण, कोई हीनभावना से घिर जाने के चलते और कोई अपने साथ जातिगत, क्षेत्रगत भेदभाव के कारण। कुछ मामलों में कोई छात्र अपने साथी छात्रों द्वारा ही दुर्व्यवहार का शिकार होकर आत्महत्या कर लेता है। कई बार यह दुर्व्यवहार रैगिंग के रूप में होता है। इसके अलावा अन्य कारणों से भी छात्र आत्महत्या करते हैं। उन्हें ऐसा करने से तभी रोका जा सकता है, जब उनकी निराशा, उदासी, अकेलेपन अथवा उनके बदले व्यवहार को समय रहते भांपा जा सके और उनकी सही तरह काउंसिलिंग की जा सके। चूंकि अधिकांश उच्च शिक्षण संस्थानों में अलग-अलग क्षेत्रों और पृष्ठभूमि के छात्र आते हैं, इसलिए कई बार उनमें आपसी समन्वय और सद्भाव कायम नहीं हो पाता। ऐसा अनिवार्य रूप से हो, इसके लिए शिक्षा संस्थानों के प्रबंध तंत्र को पहले दिन से ही सक्रिय रहना चाहिए। उन्हें अपने संस्थान के छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की निरंतर जांच को लेकर भी सजगता का परिचय देना चाहिए।

सुनिश्चित हो आपूर्ति

गंगा, कोसी, गंडक, बागमती जैसी नदियों के वरदान वाले राज्य बिहार को गर्मी आते ही जल संकट से जूझना पड़ता है। सुनने में यह थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन है सच। बहरहाल, अच्छी बात यह है कि इस संकट के निदान के लिए बिहार सरकार ने कमर कस ली है। मुख्य सचिव ने बैठक कर निर्देश जारी किए हैं कि पेयजल आपूर्ति को लेकर लोगों को परेशानी नहीं हो, इसकी मुकम्मल व्यवस्था की जाए। कहीं से गड़बड़ी की शिकायत मिले, चाहे चापाकल में या फिर पाइपलाइन में, तो महज 24 घंटे में समस्या का निदान हो जाना चाहिए। जमीनी स्तर पर कवायद दिखती भी है, लेकिन कई समस्याएं ऐसी हैं जिनका निदान इस गर्मी में भी होता नहीं दिख रहा। शहरी जलापूर्ति योजना के तहत भागलपुर में वर्षों से पाइपलाइन बिछाने का काम हो रहा। अफसरों की उदासीनता के कारण लटकी यह योजना तय समय से डेढ़ साल पीछे है। इसके दोषी दंडित नहीं हुए, ऐसे में अंदेशा है कि कहीं इसमें और समय बर्बाद न हो। डेडलाइन देकर प्रतिदिन वरीय अधिकारी योजना की मानीटरिंग करें तो संभव है कि लोगों को शीघ्र इस समस्या का निदान मिल जाए। अभी तो लोग पानी के लिए अपने घरों की बोरिंग पर आश्रित हैं, लेकिन यह अच्छी व्यवस्था नहीं। इस प्रकार से पानी निकालने में खर्च भी अपेक्षाकृत बहुत अधिक होता है। जिसमें ऊर्जा भी लगती है। संचित और सीमित भूगर्भीय जल का दोहन भविष्य के लिए गंभीर खतरा हो सकता है। नल-जल योजना सही से काम करे और पेजयल की लंबित योजनाएं मानीटरिंग कर शीघ्र पूरी की जाएं, तभी जल संकट दूर होगा।

> पेयजल आपूर्ति की योजनाओं की उचित मानीटरिंग जरूरी है, तभी लोगों को राहत मिल सकेगी

केजरीवाल का बिखरता कुनबा

राज कुमार सिंह

जिस रफ्तार से आप ने दो राज्यों की सत्ता और राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल किया, उसी गति से उसमें आंतरिक असंतोष भी उभरता गया

अवधेश राजपूत

वैकल्पिक राजनीति के सपने दिखाते हुए चमत्कारिक रफ्तार से दिल्ली और पंजाब की सत्ता कांग्रेस से छीनने वाली आम आदमी पार्टी (आप) के दस राज्यसभा सदस्यों में से सात का भाजपा में शामिल होने का फैसला पार्टी के भटकाव का प्रमाण भी है। हालांकि तीन बागियों ने ही कार्यालय जाकर भाजपा का लड्डू खाया, पर राज्यसभा में आप के नेता संजय सिंह द्वारा उनकी सदस्यता समाप्ति के लिए पत्र लिखे जाने के बावजूद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सातों बागियों के भाजपा में विलय को मंजूरी दे दी। जाहिर है 'विभाजन बनाम दलबदल' की लड़ाई लंबी चलेगी, लेकिन उससे आप के आंतरिक संकट, असंतोष और बगावत पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। स्वाति मालीवाल अरसे से आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध मोर्चा खोले हुए थीं तो राघव चड्ढा ने भी राज्यसभा में उपनेता पद से हटाए जाने के बाद खुद को 'घायल' और इसीलिए 'घातक' बताते हुए 'सैलाब' लाने का एलान कर दिया था। इसलिए केजरीवाल के साथ ही उनकी राजनीति को गंभीरता से लेने वालों को भी इस प्रयोग की विफलता का विश्लेषण करना चाहिए। यह भटकाव अचानक नहीं आया।

सत्ता के गलियारों में प्रवेश के साथ ही आप में भटकाव और उसके चलते अलगाव शुरू हो गया था। आप आलाकमान ने पार्टी छोड़ गए सांसदों को पंजाब का 'गद्दार' करार दिया, पर यह नहीं बताया कि वे खुद कब और किसके 'वफादार' रहे? राघव, स्वाति और संदीप पाठक को आंदोलनकारी आप का सिपाही मान भी लें तो क्रिकेटर हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रमजीत साहनी और अशोक मित्तल को राज्यसभा सदस्यता किस निष्ठा के पुरस्कारस्वरूप दी गई? कभी मोहल्ला सभा की राय से पार्षद-विधायक प्रत्याशी चुनने की बात करने वाले केजरीवाल ने संसद के उच्च सदन की सदस्यता बांटने की कुछ तो कसौटी रखी होगी।

कारोबारी अशोक मित्तल वही हैं, जिन्हें केजरीवाल ने राघव को हटाकर राज्यसभा में पार्टी का उप नेता बनाया था, पर दोनों ने ही पांच अन्य के साथ 'झाड़ू' छोड़कर 'कमल' चुन लिया। इनके अलावा भी जो लोग राज्यसभा भेजे गए, उनकी निष्ठा पर लगातार उठते रहे सवालों से केजरीवाल मुंह चुराते रहे। केजरीवाल को सही आदमी की पहचान नहीं या फिर उनकी कसौटियां दल और विचारधारा के प्रति निष्ठा से इतर कुछ और हैं? खुद को 'ईमानदार' घोषित करते हुए केजरीवाल तमाम परंपरागत दलों और नेताओं के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपपत्र जारी करते रहे, पर आप में अंतहीन बगावत और अलगाव खुद उन्हें कठघरे में खड़ा करता है। विरोधियों की मानें तो जिस आप को सत्ता राजनीति के चरित्र में बदलाव का वाहक बनना चाहिए था, वह केजरीवाल की निरंकुश सत्ता का औजार बनकर रह गई। जिस रफ्तार से आप ने दो राज्यों की सत्ता और राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल किया, उसी गति से उसमें आंतरिक असंतोष उभरता गया। कम उम्र में सीए और फिर विधायक-सांसद बने राघव चड्ढा को जिस तरह राज्यसभा में उपनेता पद से हटाते हुए पत्र लिखा गया कि उन्हें पार्टी की ओर से बोलने का समय न दिया जाए, वह नेतृत्व से बढ़ती कटुता का प्रमाण है। जिन राघव पर पंजाब में 'सुपर सीएम' की तरह काम करने के आरोप लगे, वह अचानक इतना नापसंद कैसे हो गए? क्या निजी रिश्ते ही आप में राजनीतिक हैसियत तय करते हैं?

'आपरेशन लोटस' की भनक मिलने पर ही राघव को उपनेता पद से हटाने की बात कही जा रही है, पर जिन अशोक मित्तल को उनकी कुर्सी दी गई, वह भी भाजपा से जा मिले, शायद ईडी के छापों से डर से। कारोबारी हमेशा मुनाफे का ही सौदा करेगा। केजरीवाल और राघव के बीच दूरियां बढ़ने की खबरें अरसे से थीं। जब केजरीवाल कथित शराब घोटाले में जेल भेजे गए, तब राघव आंखों का इलाज कराने लंदन चले गए। जब दिल्ली की एक अदालत द्वारा शराब घोटाले में आरोपमुक्ति पर केजरीवाल ने खुद को फिर 'ईमानदार' घोषित किया, तब भी राघव ने खुशी जताने की जहमत नहीं उठाई। आप के मुखर नेता रहे संदीप पाठक द्वारा भाजपा में जाना चौंकाता है, पर केजरीवाल के राजनीतिक प्रबंधन पर सवालिया निशान भी लगाता है। यह नसीहत स्वाभाविक है कि आप छोड़ने वालों को राज्यसभा सदस्यता भी छोड़ देनी चाहिए, पर जब राजनीति का लक्ष्य ही सत्ता है तो उसे पाने के बाद कौन छोड़ देगा? दूसरों को आरोप लगते ही पदत्याग की नसीहत देने वाले केजरीवाल जेल जाने के बाद भी लंबे समय तक दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहे थे, जबकि उसी बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी के साथ ही इस्तीफा देकर अलग मिसाल पेश की थी। विधानसभा चुनाव होने पर दोनों राज्यों के मतदाताओं ने भी अलग-अलग जनादेश दिया।

आप में टूट से राज्यसभा में भाजपा के लिए बहुमत की राह आसान होगी, पर उसका लक्ष्य पंजाब और गुजरात है। गुजरात में भाजपा के दशकों से दबदबे के चलते तात्कालिक चुनौती नहीं, पर 13 के पार पहुंच गया आप का मत प्रतिशत खतरे का संकेत है। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ भाजपा का गठबंधन विजयी समीकरण था, लेकिन अलगाव के बाद दोनों हाशिए पर चले गए। आप प्रचंड बहुमत से सत्ता में है तो कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष क्रमशः कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़ भाजपा में आ चुके हैं। पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पौत्र रवनीत सिंह बिट्टू भाजपा से लोकसभा तो नहीं पहुंचे, पर राज्यसभा के रास्ते केंद्रीय मंत्री बना दिए गए। आप छोड़ भाजपाई बने राज्यसभा सदस्यों में से किसी का भी जनाधार नहीं, लेकिन उनके जरिये आप में बड़े विभाजन से विधानसभा चुनाव से पहले भगवंत मान सरकार खतरे में पड़ी तो भाजपा का स्थिरता का कार्ड चल सकता है। पंजाब की सत्ता भी हाथ से फिसलना आप के भविष्य पर सवालिया निशान होगा।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)
response@jagran.com

वैश्विक समाधान में समर्थ यूपीआइ

इस फरवरी में जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला किया तो पश्चिम एशिया में हड़कंप मच गया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजरायल, बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात पर सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दागे तथा स्ट्रेट आफ होर्मुज बंद कर दिया। यह वह समुद्री रास्ता है, जिससे दुनिया का 20 प्रतिशत तेल और अरबों डालर का व्यापार होता है। बैंकिंग के रास्ते धीमे पड़ गए, पैसे भेजना मुश्किल हो गया। 40 दिनों की भीषण लड़ाई के बाद दो हफ्ते का युद्धविराम हुआ, लेकिन उसके विस्तार के बाद भी स्थिति नाजुक बनी हुई है। इस जंग ने दुनिया की आर्थिक व्यवस्था को तहस-नहस कर दिया। होर्मुज बंद होने से तेल के दाम आसमान छूने लग गए। शिपिंग कंपनियां रास्ता बदलने पर मजबूर हो गईं और सबसे बड़ी तकलीफ यह रही कि भारत के लाखों श्रमिक जो यूएई, कुवैत, बहरीन और सऊदी अरब में काम करते हैं, उनके परिवारों तक पैसे भेजना मुश्किल हो गया। पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था संकट में आ गई।

यह पहली बार नहीं जब दुनिया ने देखा कि वित्तीय व्यवस्था को हथियार बनाया जा सकता है। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस को स्विफ्ट से बाहर कर दिया था। इस व्यवस्था के जरिये दुनिया के बैंक आपस में पैसे भेजते हैं। सीधे शब्दों में यह बैंकों का वाट्सएप है। रूस के स्विफ्ट से बाहर होने के बाद रूसी लोग दुनिया से कट गए। अब ईरान पर भी कड़े प्रतिबंध हैं।

भारत ने यूपीआइ यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को 2016 में तब शुरू किया था, जब दुनिया में इस तरह के संकटों की कल्पना भी मुश्किल थी। नेशनल पेमेंट्स कार्पोरेशन आफ इंडिया यानी एनपीसीआइ ने यह व्यवस्था इसलिए बनाई थी, ताकि हर भारतीय को सस्ता, तेज और आसान डिजिटल भुगतान मिल सके। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यही यूपीआइ एक दिन दुनिया के लिए स्विफ्ट का सबसे बड़ा निष्पक्ष विकल्प बन सकता है। रूस-यूक्रेन युद्ध और अब अमेरिका-इजरायल और ईरान की जंग ने यह साबित कर दिया कि भारत ने जो व्यवस्था अपने नागरिकों के लिए बनाई थी, वह आज पूरी दुनिया की जरूरत है। स्विफ्ट ने वादा किया था कि वह निष्पक्ष रहेगा, लेकिन राजनीति आई तो उसने पक्ष लिया। यूपीआइ किसी के हाथ का हथियार नहीं और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। यूपीआइ जिसे आप फोन पे, गूगल पे या पेटीएम के जरिये रोज इस्तेमाल करते हैं, दुनिया की सबसे तेज और सबसे सस्ती भुगतान व्यवस्था है। अब यह देश की सीमाएं पार कर रही है। सिंगापुर, यूएई, फ्रांस और मारीशस जैसे कई देशों से यूपीआइ का जुड़ाव हो चुका है।

रोहित यादव

> जब दुनिया में जंग हो तब रुपये का प्रवाह रुकना नहीं चाहिए और यूपीआइ से इसमें अपेक्षित सफलता मिलेगी

यूपीआइ पर बढ़ता दुनिया का भरोसा। फाइल

भारत दुनिया में सबसे अधिक विदेशी पैसा मंगाने वाला देश है। हर साल करीब 11 लाख करोड़ रुपये भारतीय विदेश से अपने घर धनराशि भेजते हैं। लंदन में बैठी नर्स, ह्यूस्टन का इंजीनियर, दुबई का दुकानदार सब अपने परिवार को पैसे भेजते हैं। पुराने तरीकों से पैसे भेजने में 6-7 प्रतिशत तक राशि कट जाती है। यूपीआइ के जरिये यह खर्च लगभग खत्म हो सकता है।

जब दुनिया में जंग हो तब पैसा रुकना नहीं चाहिए। यूपीआइ यही सुनिश्चित करने का काम कर रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या रूस या चीन ने भी ऐसा कुछ नहीं बनाया? बनाया तो, लेकिन दुनिया ने उन्हें नहीं अपनाया, क्योंकि भरोसा नहीं था। ईरान के खिलाफ युद्ध में यही देखा गया कि जो देश अमेरिका के निशाने पर हैं, उनकी भुगतान व्यवस्था दुनिया स्वीकार नहीं करती। भारत पर भरोसे के चलते कई देश यूपीआइ से जुड़ने को तैयार हैं। इस युद्ध ने यह भी साफ किया कि दुनिया डालर पर निर्भरता कम करना चाहती है। भारत की यूपीआइ सेटलमेंट व्यवस्था इसका एक व्यावहारिक जवाब है।

कुछ लोग सोचते हैं कि अगर भारत अपनी यूपीआइ तकनीक दूसरे देशों को दे रहा है तो वे इसे कापी कर लेंगे। यह सोच सही नहीं। तकनीक कापी हो सकती है, लेकिन नेटवर्क नहीं। जैसे वाट्सएप की तकनीक कोई भी बना सकता है लेकिन उसके करोड़ों उपयोगकर्ता कोई नहीं छीन सकता। यूपीआइ का नेटवर्क, उसके करोड़ों उपयोगकर्ता और उसकी साख-यही भारत की असली पूंजी है। आज भारत प्रोजेक्ट नेक्सस जैसी वैश्विक पहलों में सक्रिय भूमिका निभा रहा है।

अभी यूपीआइ वैश्विक स्तर पर पूरी तरह सरल नहीं बन पाया है। विदेश में रहने वाले भारतीयों को अभी भी भारतीय सिम कार्ड की जरूरत पड़ती है। सभी देशों में सभी दुकानों पर यूपीआइ नहीं चलता, लेकिन रिजर्व बैंक और एनपीसीआइ इस पर काम कर रहे हैं। जल्द ही ये रुकावटें भी दूर होंगी। आज दुनिया जिस तरह अनिश्चितता से भरी है, उसमें यूपीआइ की जरूरत और भी ज्यादा है। युद्ध का मैदान अब सिर्फ जमीन पर नहीं, वह बैंकों में, पेमेंट सिस्टम में और डिजिटल नेटवर्क में भी है। अमेरिका-इजरायल और ईरान की जंग ने फिर साबित किया कि जब दुनिया बंट जाती है तो पैसों की निष्पक्ष व्यवस्था सबसे बड़ी जरूरत बन जाती है। भारत का यूपीआइ वही निष्पक्ष व्यवस्था है।

(लेखक नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट स्टडीज, मुंबई के स्कूल आफ बिजनेस मैनेजमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

सकारात्मकता की सार्थकता

सकारात्मक सोच का अर्थ है रचनात्मक मानसिकता के साथ चुनौतियों का सामना करना, अपने समक्ष समाधान खोजना और किसी भी स्थिति से सर्वश्रेष्ठ परिणामों को सुनिश्चित करना। सकारात्मकता से हमें नई दृष्टि और परिधि प्राप्त होती है। इससे हमारा आत्मविस्तार होता है तथा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य लाभ मिलता है। सकारात्मकता से मन में पवित्र भावों का जागरण होने लगता है, दोष ढूंढ़ने की प्रवृत्ति नष्ट होती है। हमारी दृष्टि में दूसरे का सुख स्थान पाने लगता है। अपने कर्मों के प्रति पूज्य भाव का उदय होता है। नकारात्मकता से हम छिद्रान्वेषी हो जाते हैं और तब सारा संसार बुराइयों में लिप्त दिखाई देने लगता है तथा स्वयं के दोषमुक्त होने की प्रवृत्ति समाप्त होती जाती है। सकारात्मकता से विषम परिस्थितियों में धैर्य बना रहता है।

वास्तव में सफलता की कुंजी सकारात्मकता ही है। सकारात्मकता से ओतप्रोत व्यक्ति के शब्दकोश में 'असंभव' शब्द नहीं होता है। वह परिस्थितियों से जूझते हुए अपने लक्ष्य को पा ही लेता है। सकारात्मकता आत्मविश्वास की आधारशिला है। सकारात्मक सोच से दुखों को दूर किया जा सकता है। सुमति ही सकारात्मकता है और कुमति नकारात्मकता। जिसने सुमति का आश्रय लिया, अपना कल्याण सिद्ध कर लिया और जो कुमति के साथ रहा, उसने अपना सर्वस्व नाश कर लिया।

सकारात्मकता ही हमें दूसरों के लिए जीने की प्रेरणा देती है तथा सुखद समानुभूति कराती है,। जबकि नकारात्मकता हमें संकीर्ण बनाकर छोटा कर देती है। नकारात्कमता के चलते ही हम स्वार्थ के वशीभूत होकर रह जाते हैं। ध्यान रहे कि धैर्यशील व्यक्ति असफलताओं से धैर्य नहीं खोते और अपने सकारात्मक विचारों के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। सचमुच सकारात्मकता सार्थक जीवन का मूलमंत्र है, जो हमें हमारे उद्देश्य तक पहुंचाती है।

गौरीशंकर वैश्य

क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ एकीकृत एआइ

प्रदीप

> औषधि निर्माण और ऊर्जा उत्पादन जैसे क्षेत्रों में क्वांटम कंप्यूटिंग और एआइ का संगम नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता

विज्ञान और तकनीकी के इतिहास में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब दो स्वतंत्र ज्ञान धाराएं मिलकर एक नई क्रांति को जन्म देती हैं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) और क्वांटम कंप्यूटिंग का संयोजन ठीक ऐसा ही एक महत्वपूर्ण मोड़ प्रस्तुत कर रहा है। हाल ही में यूनिवर्सिटी कालेज लंदन के शोधकर्ताओं ने 'साइंस एडवांसेज' जर्नल में प्रकाशित अपने एक अध्ययन में यह दिखाया है कि क्वांटम कंप्यूटिंग और एआइ का एकीकरण जटिल भौतिक प्रणालियों (विशेष रूप से अराजक या कैओटिक प्रणालियों) की भविष्यवाणियों को अधिक कुशल बना सकता है।

पहली नजर में यह एक तकनीकी उपलब्धि मालूम होती है, लेकिन गहराई से देखें तो यह विज्ञान की कार्यपद्धति में एक अहम बौद्धिक बदलाव का भी संकेत है। पारंपरिक रूप से आधुनिक विज्ञान दो प्रमुख स्तंभोंः सिद्धांत और प्रयोग पर आधारित रहा है। कंप्यूटिंग ने तीसरे स्तंभ के रूप में सिमुलेशन को जोड़ा और एआइ ने इस सिमुलेशन को गति और विस्तार दिया। मगर एआइ के साथ एक मौलिक समस्या भी उठ खड़ी हुईः उसकी 'ब्लैक बाक्स-नुमा' प्रकृति।

दरअसल क्वांटम कंप्यूटर बिट्स (0 और 1) के बजाय क्यूबिट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो 'सुपरपोजिशन' के जरिये एक साथ कई अवस्थाओं में मौजूद हो सकते हैं। साथ ही, एंटैंगलमेंट की वजह से ये क्यूबिट्स एक-दूसरे से गहराई से जुड़े रहते हैं, जिससे अत्यंत जटिल सूचना को संक्षिप्त रूप में अभिव्यक्त करना मुमकिन हो जाता है। हालिया शोध में विज्ञानियों ने क्वांटम कंप्यूटर का इस्तेमाल पूरे सिमुलेशन को चलाने के लिए नहीं, बल्कि एआइ प्रशिक्षण के एक महत्वपूर्ण चरण में किया है। सबसे पहले, डाटा को क्वांटम प्रणाली से गुजारा जाता है, जो उसमें छिपे स्थायी सांख्यिकीय पैटर्न को पहचानती है।

यह तरीका कई मायनों में क्रांतिकारी साबित हुआ। हालिया शोध में क्वांटम-एआइ हाइब्रिड माडल ने पारंपरिक एआइ माडलों की अपेक्षा 20 प्रतिशत ज्यादा सटीकता का प्रदर्शन किया। यही नहीं, यह अराजक प्रणालियों के मामलों में भी लंबे समय तक स्थिर भविष्यवाणियां करने में सक्षम रहा। एक और उल्लेखनीय पहलू यह है कि इस नई प्रणाली में सैकड़ों गुना कम मेमोरी की जरूरत पड़ी, जिससे भविष्य में बड़े पैमाने के सिमुलेशन अधिक सुलभ और किफायती हो सकते हैं। इस विकास का दायरा सिर्फ सैद्धांतिक भौतिकी तक सीमित नहीं है। जलवायु पूर्वानुमान, रक्त प्रवाह की माडलिंग, औषधि निर्माण, ऊर्जा उत्पादन और यहां तक कि पवन ऊर्जा संयंत्रों के डिजाइन जैसे क्षेत्रों में भी क्वांटम कंप्यूटिंग और एआइ का संगम नई संभावनाओं के दरवाजे खोल सकता है।

(लेखक विज्ञान संचारक हैं)

बंगाल के नतीजों पर टिकी निगाहें

'ममता के सामने गढ़ बचाने की चुनौती' शीर्षक से लिखे आलेख में राहुल वर्मा ने बंगाल विधानसभा चुनाव का समग्रता में विश्लेषण किया है। बंगाल विधानसभा चुनाव देश की राजनीति का केंद्र बना हुआ है। दूसरे चरण के मतदान के बाद मुकाबला और रोचक हो गया है। राज्य में लंबे समय से राजनीतिक हिंसा और तीखी चुनावी प्रतिस्पर्धा का माहौल रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने अपना मजबूत जनाधार बचाने की चुनौती है, वहीं भाजपा सत्ता परिवर्तन के लक्ष्य के साथ जुटी रही। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। यदि ममता बनर्जी की चौथी बार वापसी होती है, तो राष्ट्रीय पटल पर भाजपा के विरुद्ध उनकी छवि और मजबूत होगी। यदि भाजपा सत्ता परिवर्तन में सफल होती है, तो यह टीएमसी के अस्तित्व के लिए खतरे की घंटी होगी। राज्य में भारी मतदान प्रतिशत यह संकेत देता है कि जनता लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी निभाना चाहती है। केंद्रीय बलों की तैनाती से मतदाताओं में सुरक्षा भाव बढ़ा। अब देखना यह है कि क्या ममता अपना गढ़ बचा पाती है, या भाजपा नया इतिहास रचेगी?

हिमांशु शेखर-केसपा, गयाजी

दलित एक्ट में संशोधन

अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, जिसे बोलचाल में दलित या एससी-एसटी एक्ट कहते हैं, उसके कतिपय प्रविधानों में संशोधन आज की अनिवार्यता है, क्योंकि वे विभेदकारी और नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध हैं। प्रथम तो यह कि बिना

मेलबाक्स

जांच किए पहले गिरफ्तारी कर लेना कतई अनुचित है, क्योंकि कोर्ट से निर्दोष साबित होने पर आरोपी के अपमान और त्रास की भरपाई नहीं हो पाती। दूसरा यह कि यदि दलित से गैर दलित का कोई अन्य विवाद भी हो, तो भी यह एक्ट लागू कर दिया जाए। यह क्या बात हुई? दलित यदि कोई नाजायज बात गैर दलित से मनवाने पर विवाद करे और न मानने पर मुकदमा लिखवा दे, तो यह एक्ट लागू कर दिया जाता है। प्रविधान यही है। यह कतई अन्यायपूर्ण है और केवल राजनीतिक दलों का वोट बैंक ही साधता है। ये प्रविधान समाज को विघटित करने वाले तथा विद्वेषकारी होकर संशोधित किए जाने योग्य हैं।

रघोत्तम शुक्ल, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, लखनऊ

अविश्वसनीय और अहंकारी ट्रंप

बुधवार को प्रकाशित लेख "अस्थिर और अविश्वसनीय ट्रंप" ने डोनाल्ड ट्रंप की कार्यशैली, विशेषकर उनके अहंकारपूर्ण और आत्मकेंद्रित रवैये को अत्यंत स्पष्टता और साहस के साथ सामने रखा है। यह लेख केवल राजनीतिक विश्लेषण ही नहीं, बल्कि उस खतरनाक मानसिकता का पर्दाफाश है जिसमें शक्ति के साथ संयम नहीं, बल्कि अहंकार जुड़ जाता है। ट्रंप के निर्णयों और बयानों में एक निरंतरता दिखती है- वह है उनका अति-आत्मविश्वास, जो कई बार घमंड की सीमा को पार कर जाता है। वैश्विक मुद्दों को समझने और सुलझाने के बजाय उन्हें व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का प्रश्न बना देना उनके नेतृत्व की सबसे बड़ी कमजोरी रही है। अंतरराष्ट्रीय कूटनीति जहां धैर्य, संवाद और संतुलन की मांग करती है, वहीं ट्रंप का रवैया अक्सर 'मैं ही अंतिम सत्य हूं' जैसी सोच से प्रेरित प्रतीत होता है। यही अहंकार उन्हें सहयोगियों की सलाह को नजरअंदाज करने और विरोधियों को उकसाने की ओर ले जाता है। लेख में जिस प्रकार उनकी नीतिगत अस्थिरता का उल्लेख किया गया है, वह दरअसल इसी अहंकार का परिणाम है। जब कोई नेता स्वयं को नियमों और परंपराओं से ऊपर समझने लगे, तो निर्णय न तो दूरदर्शी होते हैं और न ही विश्वसनीय। अन्य वैश्विक मुद्दों पर उनका बदलता रुख इस बात का प्रमाण है कि उनकी प्राथमिकता स्थायी समाधान नहीं, बल्कि तात्कालिक प्रभाव और व्यक्तिगत छवि रही है। ट्रंप की आक्रामक बयानबाजी केवल राजनीतिक रणनीति नहीं, बल्कि शक्ति-प्रदर्शन की मानसिकता को दर्शाती है।

बिमलेश कुमार सिंह चौहान, लखनऊ

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय: 011-43166300, नोएडा कार्यालय: 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

टाटा मोटर्स ने 144 पेटेंट आवेदन दाखिल किए नई

दिल्ली: वाणिज्यिक वाहन बनाने वाली कंपनी टाटा मोटर्स लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2025-26 में 144 पेटेंट आवेदन दाखिल किए। यह एक वर्ष में अब तक की सर्वाधिक संख्या है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी ने पेटेंट आवेदनों के अलावा 21 डिजाइन और 35 कापीराइट आवेदन भी दाखिल किए, जिससे उसकी बौद्धिक संपदा को और मजबूती मिली। इसके अलावा, कंपनी को 15 पेटेंट स्वीकृतियां भी मिलीं, जिससे कुल स्वीकृत पेटेंट की संख्या 650 से अधिक हो गई। (प्रेट्र)

फिलिप्स अपने राजस्व का लगभग पांच से छह प्रतिशत रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्च करती है जबकि वैश्विक कंज्यूमर इंडस्ट्री में औसतन दो से तीन प्रतिशत खर्च होता है।
– दीपा खन्ना, चीफ बिजनेस लीडर, रायल फिलिप्स

संसेक्स	निफ्टी	सोना प्रति दस ग्राम	चांदी प्रति किलो ग्राम	डालर	क्रूड प्रति बैरल
77,496.36 ▲ 609.45	24,177.65 ▲ 181.95	₹ 1,52,800 ▼ ₹ 1,500	₹ 2,44,500 ▲ ₹ 500	₹ 94.88 ▲ ₹ 0.20	$ 114.4

एक नजर में

प्राकृतिक आपदा में कर्जदारों को बैंक खुद दे सकेंगे राहत

मुंबई : आरबीआइ ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत उपायों पर संशोधित दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा है कि बैंक अब उधारकर्ताओं के अनुरोध का इंतजार किए बिना ही उन्हें राहत दे सकेंगे। हालांकि ग्राहक चाहें तो प्राकृतिक आपदा घोषित होने के 135 दिनों के भीतर इससे बाहर निकल सकते हैं। नए नियम एक जुलाई, 2026 से लागू हो जाएंगे। नए दिशा-निर्देश वाणिज्यिक बैंकों, लघु वित्त बैंकों, सहकारी बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों पर लागू होंगे। (प्रेट्र)

पहले पखवाड़े में बैंक ऋण वृद्धि घटकर 15% पर

मुंबई: बैंक ऋण वृद्धि की गति 15 अप्रैल को समाप्त पखवाड़े में धीमी होकर 15 प्रतिशत से नीचे आ गई। 15 अप्रैल को समाप्त पखवाड़े में बैंक ऋण वृद्धि की सालाना दर घटकर 14.88 प्रतिशत रही, जबकि इससे पिछले पखवाड़े में यह 15.96 प्रतिशत थी। इस अवधि में कुल बैंक ऋण में 2.06 प्रतिशत यानी 4.51 लाख करोड़ रुपये की कमी दर्ज की गई। 15 अप्रैल को समाप्त पखवाड़े में बैंक ऋण 214 लाख करोड़ रुपये रहा, जबकि 31 मार्च को समाप्त पखवाड़े में यह 218 लाख करोड़ रुपये था। पिछले वर्ष इसी अवधि में बैंक ऋण 186 लाख करोड़ रुपये था। (प्रेट्र)

मार्च तिमाही में 4.37 करोड़ ने की हवाई यात्रा

नई दिल्ली: भारतीय विमानन कंपनियों ने 2026 के पहले तीन महीनों (जनवरी-मार्च) में घरेलू मार्गों पर 4.37 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को अपने गंतव्य पर पहुंचाया। इस साल मार्च में 1.44 करोड़ लोगों ने हवाई यात्रा की। फरवरी में यह आंकड़ा 1.41 करोड़ था। हालांकि, मार्च, 2025 में 1.45 करोड़ यात्रियों ने हवाई यात्रा की थी। इंडिगो की बाजार हिस्सेदारी फरवरी के 63.1 प्रतिशत से बढ़कर मार्च में 63.3 प्रतिशत हो गई, जबकि एयर इंडिया ग्रुप की हिस्सेदारी 27 प्रतिशत से घटकर 26.2 प्रतिशत हो गई। (प्रेट्र)

अब देश में सिर्फ एथनाल से चल सकेंगे वाहन

मसौदा जारी, तेल आयात बिल घटाने में मिलेगी मदद, 30 दिनों में आम लोगों को देनी होगी राय

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी हाल के महीनों में कई बार यह संकेत दे चुके हैं कि सरकार की मंशा देश में बिकने वाले पेट्रोल में ज्यादा एथनाल मिलाने की है। अब उनके मंत्रालय ने इस बारे एक मसौदा जारी किया है। इसके मुताबिक देश में 85 प्रतिशत तक एथनाल मिश्रण या 100 प्रतिशत एथनाल से भी वाहन चलाने की मंजूरी दी जा सकती है। अभी देश में 20 प्रतिशत मिश्रित ईंधन (ई20) की बिक्री को इजाजत है, जिसे ई85 या ई100 ईंधन करने के उद्देश्य से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 28 अप्रैल 2026 को केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में आवश्यक संशोधन का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है।

सरकार की तरफ से मौजूदा नीति में बड़े बदलाव का यह संकेत तब आया है जब पश्चिम एशिया संघर्ष की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में भारी अस्थिरता है। कच्चे तेल की कीमतों के बढ़ने से पूरी अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ने की बात कही जा रही है। ई10 से ई20 पर आने के बाद से ही भारत विदेशी मुद्रा में लगभग 14 अरब डालर की बचत कर चुका है।

ऐसे में भारत जितना ज्यादा एथनाल मिश्रित ईंधनों की बिक्री करेगा, भारत का तेल आयात बिल उतना ही कम होगा। हालांकि, बड़ा सवाल यह है कि देश का वाहन उद्योग अभी पूरी तरह से अपने वाहनों को ई-20 के लायक भी नहीं बना पाया है, वहां ई85 मिश्रण वाले पेट्रोल की बिक्री के लिए वाहनों को किस तरह से तैयार किया जाएगा। इस बारे में दैनिक जागरण ने देश के तीन प्रमुख आटोमोबाइल कंपनियों से बात की लेकिन आधिकारिक तौर पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कंपनियों का कहना है कि वह सरकार की तरफ से इस बारे में पूरे नियम आने के बाद ही कुछ कहने की स्थिति में होंगे, क्योंकि यह देखना होगा कि ई85 (यानी 85 प्रतिशत एथनाल व 15 प्रतिशत पेट्रोल) के लिए कितना समय दिया जाता है। मसौदे पर 30 दिनों तक आम लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं।

ई20 की जगह ई85 या ई100 ईंधन को बढ़ावा देने की तैयारी, विदेशी मुद्रा की होगी बचत

सौ प्रतिशत बायोडीजल को भी इस्तेमाल करने का प्रस्ताव

इस मसौदे में पेट्रोल में 85 प्रतिशत मिश्रण को अलग ईंधन ग्रेड के रूप में मान्यता देने की बात है। साथ ही पूरी तरह से एथनाल (ई100) पर वाहन चलाने की अनुमति भी दी गई है। बी100 के नाम से सौ प्रतिशत बायोडीजल को भी पहली बार भारतीय वाहनों में इस्तेमाल करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही उत्सर्जन मानकों को बदलने और वाहनों को मंजूरी देने संबंधी मौजूदा नियमों से जुड़े मानकों को बदलने का भी प्रस्ताव है ताकि ज्यादा एथनाल वाले ईंधन के लिए वाहनों का प्रमाणन आसान हो।

फिलहाल 20 अरब लीटर है देश में एथनाल का उत्पादन

वर्ष 2025-26 में तेल कंपनियों ने ई20 के लिए 1100 करोड़ लीटर एथनाल खरीदा है जबकि देश में एथनाल उत्पादन लगभग 20 अरब लीटर के आसपास है। वर्ष 2027 तक इसे बढ़ाकर 2700 करोड़ लीटर करने की तैयारी है। देश में उत्पादन क्षमता मांग से ज्यादा हैं। हालांकि, ई85 व ई100 के लिए एथनाल उत्पादन को कई गुना बढ़ाना पड़ेगा।

वाहनों के माइलेज को लेकर स्थिति करनी होगी साफ

एथनाल मिश्रित ईंधन से वाहनों पर पड़ने वाले असर और माइलेज को लेकर भी सरकार को स्थिति साफ करनी होगी। नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि ई20 से वाहनों का माइलेज दो प्रतिशत कम हो सकता है। आटो कंपनियों को भी भारी-भरकम निवेश करने के लिए तैयार करना होगा।

तेल-गैस आपूर्ति सामान्य होने में लगेगा वक्त, बढ़ेगी महंगाई

वित्त मंत्रालय की मासिक रिपोर्ट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : पश्चिम एशिया संकट के कारण तेल व गैस का उत्पादन और आपूर्ति दोनों ही प्रभावित हो चुकी है और इसे सामान्य होने में लंबा वक्त लगेगा। ऐसे में खरीफ का उत्पादन बेहतर नहीं होता है तो देश में महंगाई बढ़ सकती है। अल नीनो असर के कारण इस साल मानसून सामान्य से कम रहने की आशंका जाहिर की गई है। पिछले दो महीनों से जारी पश्चिम एशिया संकट के कारण सप्लाई चेन पहले ही प्रभावित हो चुकी है। देश के चार बंदरगाहों पर अप्रैल के तीसरे सप्ताह में पिछले साल की तुलना में 40 प्रतिशत कम जहाज आए। जाहिर है, सप्लाई चेन प्रभावित होने लगी है, जिसका असर दिखेगा। ये आशंकाएं बुधवार को जारी वित्त मंत्रालय की मासिक रिपोर्ट में जाहिर की गई है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कच्चे तेल के उत्पादन में कमी और खरीद कीमत बढ़ने से कई देश पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत बढ़ा चुके हैं और जिन देशों ने बढ़ोतरी का भार अपने उपभोक्ताओं पर नहीं डाला है, वे भी इसकी कीमत बढ़ा सकते हैं। भारत सरकार की तरफ से पिछले सप्ताह स्पष्ट किया गया था कि पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे। हालांकि, पेट्रोल व डीजल की खुदरा कीमत तेल कंपनियां बढ़ाती-घटाती हैं। वित्त मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में फिलहाल की चुनौतियों को देखते हुए ईंधन के विकल्प और इसके भंडारण संबंधी नीतियों में बदलाव की भी सिफारिश की है।

- आयातित यूरिया से लेकर चिप तक की कीमत में पिछले साल के मुकाबले बेतहाशा बढ़ोतरी
- कई देशों ने पेट्रोल की खुदरा कीमत बढ़ाई, फिलहाल भारत सरकार ने नहीं लिया है फैसला

पिछले साल की तुलना में 560 गुना बढ़े चिप के दाम

रिपोर्ट के मुताबिक सप्लाई चेन के प्रभावित होने से आयातित यूरिया की कीमत 950 डालर प्रति टन हो गई है जो पिछले साल अप्रैल में 390 डालर प्रति टन थी। आयातित अमोनिया की कीमत 775 डालर प्रति टन के स्तर पर पहुंच गई है जो पिछले साल अप्रैल में 365 डालर प्रति टन थी। चिप (डायनेमिक रैम) की कीमत में पिछले साल की तुलना में 560 गुना की बढ़ोतरी हो चुकी है। कच्चे तेल की औसत कीमत वर्ष 2025 में 67.74 डालर प्रति बैरल थी जो वर्ष 2026 में 82-100 डालर प्रति बैरल के बीच रहेगी। इससे महंगाई और विकास की चुनौतियां बढ़ेंगी।

2026 में वैश्विक विकास दर 3.4% रहने का अनुमान

विश्व आर्थिक परिदृश्य के मुताबिक युद्ध से पहले वर्ष 2026 में वैश्विक विकास की दर 3.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था, जिसे मार्च में 3.1 प्रतिशत कर दिया गया। अब यह विकास दर 2.5 प्रतिशत तक रहने का अनुमान है। वहीं वैश्विक विकास दर 5.4-6.0 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। भारत इससे अछूता नहीं रह सकता है। हालांकि वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा है कि देश की घरेलू अर्थव्यवस्था के मानक मजबूत दिख रहे हैं। इस कारण देश की विकास दर मजबूत बनी रहेगी।

जनवरी-मार्च में सोने की मांग 10% बढ़ी

मुंबई, प्रेट्र: जनवरी-मार्च तिमाही के दौरान सोने की मांग सालाना आधार पर 10 प्रतिशत बढ़कर 151 टन रही। इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह सोने की कीमतों में तेज उछाल के बीच निवेश मांग में आई मजबूत वृद्धि है। अब सोने की मांग का रुझान बदलता हुआ दिख रहा है, जहां आभूषण के बजाये निवेश के लिए खरीद तेजी से बढ़ रही है। 2025 की पहली तिमाही में देश की कुल सोने की मांग 137 टन थी।

विश्व स्वर्ण परिषद (डब्ल्यूजीसी) ने बुधवार को जारी अपनी रिपोर्ट में कहा कि तिमाही के दौरान सोने की छड़ों, सिक्कों और ईटीएफ के जरिये निवेश मांग 54 प्रतिशत बढ़कर 82 टन हो गई। तिमाही के दौरान आभूषण मांग पर दबाव रहा और यह सालाना आधार पर 19 प्रतिशत घटकर 66 टन रह गई। ऊंची कीमतों का असर खपत पर पड़ा है।

डब्ल्यूजीसी ने पूरे वर्ष के लिए सोने की मांग 650-750 टन के बीच रहने का अनुमान जताया है, जबकि पिछले साल यह 712 टन थी। हाल के महीनों में सोने की बढ़ती कीमतों ने उपभोक्ताओं के बजट को प्रभावित किया है।

- सोने की कीमतों में तेज उछाल के बीच निवेश मांग में आई मजबूत वृद्धि से मांग बढ़कर 151 टन हुई
- बदलता हुआ दिख रहा सोने की मांग का रुझान, आभूषण के बजाय निवेश के लिए बढ़ रही खरीदारी

> 2026 की पहली तिमाही में भारत का सोना बाजार मात्रा के रुझान और मूल्य वृद्धि के बीच अंतर को दर्शाता है, जो रिकार्ड ऊंची कीमतों और बदलती उपभोक्ता प्राथमिकताओं से प्रभावित है। –**सचिन जैन**, क्षेत्रीय मुख्य कार्यपालक अधिकारी (भारत), डब्ल्यूजीसी

वैश्विक स्तर पर सोने की मांग में मामूली तौर पर बढ़ोतरी

जनवरी-मार्च तिमाही में वैश्विक स्तर पर सोने की मांग साल-दर-साल मामूली तौर पर बढ़कर 1,231 टन हो गई। इसकी वजह भू-राजनीतिक तनाव और ज्यादा कीमतों के बीच छड़ और सिक्कों के निवेश में हुई 42 प्रतिशत की वृद्धि है। 2025 की समान अवधि में सोने की मांग 1,205 टन थी।

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

एफएमसीजी-वाहन शेयरों में तेजी से सेंसेक्स 609 अंक उछला

मुंबई, प्रेट्र: एशियाई बाजारों में मजबूती और दैनिक उपयोग का सामान बनाने वाली कंपनियों, वाहन एवं दूरसंचार शेयरों में लिवाली से बुधवार को घरेलू बाजार उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में चढ़कर बंद हुए। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 609.45 अंक उछलकर 77,496.36 अंक पर बंद हुआ। वहीं, एनएसई का 50 शेयरों वाला मानक सूचकांक निफ्टी 181.95 अंक बढ़कर 24,177.65 अंक पर पहुंच गया।

सेंसेक्स के समूह में शामिल कंपनियों में से आइटीसी लिमिटेड, टेक महिंद्रा, मारुति सुजुकी, रिलायंस, भारती एयरटेल और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर चढ़कर बंद हुए। विश्लेषकों के अनुसार, बेहतर तिमाही नतीजों और घरेलू मांग की मजबूती ने घरेलू बाजार को भू-राजनीतिक तनाव से ध्यान हटाकर समर्थन देने का काम किया।

77,496.36 अंक पर बंद हुआ बीएसई का मानक सूचकांक

182 अंक चढ़कर 24,177 पर पहुंचा एनएसई का निफ्टी

रुपया 94.88 के रिकार्ड निचले स्तर पर बंद

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और विदेशी पूंजी की लगातार निकासी से रुपया बुधवार को डालर के मुकाबले 20 पैसे टूटकर 94.88 के अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ। इससे पहले, रुपये का सर्वकालिक निचला बंद स्तर 27 मार्च को 94.85 प्रति डालर दर्ज किया गया था। रुपया 30 मार्च को डालर के मुकाबले 95.22 के अपने अब तक के सबसे कम इंट्राडे स्तर पर पहुंची थी।

राष्ट्रीय फलक

सात राज्यों में 22 हजार घर खरीदारों के 'सपनों के घर' की जगी उम्मीद

- संकटग्रस्त यूनिटेक के घर खरीदारों को घर उपलब्ध कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का मानवीय संकल्प
- विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान हेतु केंद्र द्वारा नियुक्त बोर्ड, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से मांगे सुझाव

नई दिल्ली, प्रेट्र : वर्षों से अपने सपनों के घर की बाट जोह रहे हजारों परिवारों के लिए न्याय के गलियारों से एक भावुक और सकारात्मक खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट किया कि उसका एकमात्र और सर्वोपरि उद्देश्य यूनिटेक लिमिटेड के सात राज्यों में स्थित विभिन्न आवास परियोजनाओं के लिए उन 22 हजार घर खरीदारों को उनके घर दिलाना है, जो लंबे समय से अधर में लटके हुए हैं। जस्टिस जे.बी. पार्डीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने इस पेचीदा विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए केंद्र द्वारा नियुक्त बोर्ड, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से सुझाव मांगे हैं।

यह मामला केवल ईंट और गारे की इमारतों का नहीं, बल्कि उन हजारों मध्यमवर्गीय परिवारों की गाढ़ी कमाई और उम्मीदों का है, जिन्होंने वर्षों पहले यूनिटेक की परियोजनाओं में निवेश किया था। पीठ ने बड़ी गंभीरता से पूछा कि आखिर ग्राहकों द्वारा जमा किया गया पैसा गया कहां? इस पर केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सालिसिटर जनरल ने चौंकाने वाली बात बताई कि पूर्व प्रमोटरों ने इस धन को विदेशों (टैक्स हेवन देशों) में ठिकाने लगा दिया। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अब कोई और बहाना नहीं चलेगा, समाधान ढूंढना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों – जिनमें सात प्रमुख बैंक और तीन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां शामिल हैं – को एक सप्ताह में लिखित सुझाव देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि राज्य अधिकारियों द्वारा आदेशों की अनदेखी या निर्माण कार्यों में बाधा डालने पर सख्त रुख अपनाया जाएगा। इससे पहले भी कोर्ट ने रेरा पंजीकरण से छूट देकर अटके हुए ऋणों के वितरण का रास्ता साफ किया था, ताकि अटकी हुई परियोजनाओं को गति मिल सके। वर्तमान में कंपनी पर कुल 14,129.85 करोड़ रुपये की देनदारी है। फारेंसिक आडिट में यह सामने आया था कि प्रमोटरों ने लगभग पांच हजार करोड़ रुपये का दुरुपयोग किया।

प्रतीकात्मक

दुष्कर्म के बाद 11 वर्षीय बच्ची फंदे से लटकी, दरिंदे ने नोचा

जागरण संवाददाता, बरेली : 11 वर्षीय बच्ची से ऐसी बर्बरता, जिससे सुनने वाले भी सिहर जाएं। दरिंदे ने बालिका से दुष्कर्म किया। दांतों से कई जगह काटा, नाखूनों से नोचा, जननांगों को चोट पहुंचाई। हैवानियत की शिकार बेबस बिटिया फंदा लगाकर जान देने को मजबूर हो गई। शायद उसे आभास था कि दरिंदे के विरुद्ध स्वजन साथ नहीं देंगे। बुधवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ऐसा ही हुआ। पुलिस ने तहरीर मांगी तो स्वजन आनाकानी करने लगे। बाद में अज्ञात पर प्राथमिकी कराई, उसमें भी दुष्कर्म का उल्लेख नहीं किया।

बच्ची के पिता दिल्ली में फैक्ट्री में नौकरी करते हैं। मंगलवार को बच्ची का शव घर में फंदे से लटका मिला। बुधवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पुलिस अचंभित रह गई। उसमें उल्लेख किया कि बच्ची से दुष्कर्म हुआ था। उसके जननांगों पर घाव थे। कंधे और पीठ पर नाखून से नोचने के निशान थे।

सरकार ने जारी की हब एंड स्पोक माडल पर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए एसओपी

- यात्रियों के लिए घरेलू से अंतरराष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय से घरेलू यात्रा बनेगी आसान
- एअर इंडिया एक जून को वाराणसी से शुरू करेगी इस माडल पर आधारित ट्रायल

नई दिल्ली, प्रेट्र : नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यात्रियों के लिए घरेलू हवाई अड्डों से अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी को आसान बनाने के लिए हब और स्पोक एविएशन माडल को लागू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। सूत्रों के अनुसार, एअर इंडिया एक जून से वाराणसी एयरपोर्ट से इस माडल पर आधारित ट्रायल शुरू कर सकती है। यात्री वाराणसी से दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे और फिर वहां से लंदन के लिए दूसरी उड़ान लेंगे।

हब एंड स्पोक माडल उन यात्रियों को आसान कनेक्टिविटी देगा जो स्पोक यानी छोटे व क्षेत्रीय एयरपोर्ट से किसी हब यानी बड़े एयरपोर्ट के जरिये अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों को जा रहे हैं। इस माडल के तहत यात्रियों के लिए घरेलू से अंतरराष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय से घरेलू यात्रा को अधिक आसान बनाया जाएगा। इसमें इमिग्रेशन प्रक्रियाएं और सामान का ट्रांसफर शामिल हैं। 27 अप्रैल को जारी इस एसओपी ने कहा गया है, "यात्रियों का इमिग्रेशन व कस्टम क्लीयरेंस पहली उड़ान के शुरुआती एयरपोर्ट और आखिरी उड़ान के गंतव्य वाले एयरपोर्ट पर किया जाएगा, जबकि हब एयरपोर्ट पर सामान का ट्रांसफर एयरसाइड में होगा।" एसओपी के अनुसार, हब एंड स्पोक उड़ानों के अंतरराष्ट्रीय चरण में यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए डिजीयात्रा में रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होगा। हब एंड स्पोक उड़ानों के घरेलू से अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए वेब चेक-इन और ई-बोर्डिंग पास की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। हब एंड स्पोक उड़ानों का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों को दो बोर्डिंग पास मिलेंगे, जिन पर 'आइ' और 'डी' के निशान होंगे, ताकि अंतरराष्ट्रीय और घरेलू यात्रियों की पहचान व उन्हें अलग करना आसान हो सके। एयरलाइनों को हब एंड स्पोक एयरपोर्टों पर खास नोडल अधिकारी नियुक्त करने होंगे और इसकी जानकारी इमिग्रेशन अधिकारियों को देनी होगी। नोडल अधिकारी की मुख्य जिम्मेदारी यात्रियों को मिलने से रोकना और उनकी पहचान की पुष्टि करना होगी।

प्रतीकात्मक

टेक्सटाइल सेक्टर से सरकार संपर्क में, कई आइटम पर आयात शुल्क में राहत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- सरकार सेक्टर से जुड़े सभी हितधारकों के संपर्क में, निगरानी प्रकोष्ठ का गठन
- स्टेक होल्डर्स के साथ साप्ताहिक आधार पर नियमित बैठकें

पश्चिम एशिया संकट को ध्यान में रखते हुए सरकार टेक्सटाइल सेक्टर से लगातार संपर्क में हैं ताकि इस सेक्टर का उत्पादन प्रभावित नहीं हो। कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार टेक्सटाइल सेक्टर में मिलते हैं। टेक्सटाइल मंत्रालय के मुताबिक सरकार सेक्टर से जुड़े सभी हितधारकों के संपर्क में हैं और एक निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। प्रकोष्ठ उद्योग को सुविधा प्रदान करने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए जा सकने वाले उपायों पर विचार कर रहा है।

मंत्रालय स्टेक होल्डर्स के साथ साप्ताहिक आधार पर नियमित बैठकें कर रहा है। टेक्सटाइल सेक्टर के निर्माताओं को गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय पेट्रोलियम कंपनियों के संपर्क में है। टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़े कई कच्चे माल के आयात पर लगने वाले शुल्क को स्थगित कर दिया गया है। इनमें मोनोएथिलीन ग्लाइकाल (एमईजी), प्योर टेरेफ्थैलिक एसिड (पीटीए), पाली चिप्स, मेथनाल, टोल्यून, स्टाइरीन, विनाइल क्लोराइड मोनोमर, , पालीस्टाइरीन शामिल हैं।

प्रतीकात्मक

एलन मस्क ने ओपनएआइ और आल्टमैन पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप

- बहुचर्चित मुकदमे में गवाही के लिए पेश हुए मस्क, ओपनएआइ को बताया अपना ब्रेनचाइल्ड

ओकलैंड, रायटर: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) कंपनी ओपनएआइ के खिलाफ बहुचर्चित मुकदमे में गवाही देने दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति एलन मस्क मंगलवार को पेश हुए। मस्क ने ओपनएआइ, इसके सह-संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सैम आल्टमैन और इसके प्रेसिडेंट ग्रेग ब्राकमैन पर मुकदमा किया है। इस मामले में मई मध्य तक फैसला आ सकता है।

मस्क का कहना है कि आल्टमैन और ब्राकमैन ने ओपनएआइ के मूल मिशन (मानवता के लाभ के लिए गैर-लाभकारी एआइ विकसित करना) को त्यागकर और गैर-लाभकारी संस्था को लाभ कमाने वाली कंपनी में बदलकर उन्हें और जनता को धोखा दिया है। उन्होंने कहा, अगर हम चैरिटी को लूटना जायज ठहरा देते हैं, तो दान देने की बुनियाद ही नष्ट हो जाएगी।

मस्क ने ओपनएआइ को अपना "ब्रेनचाइल्ड बताया। ब्रेन चाइल्ड का अर्थ है किसी व्यक्ति के रचनात्मक सोच, मेहनत का परिणाम। मस्क ने कहा, मैंने ही यह विचार दिया, नाम तय किया। उन्हें वह सब कुछ सिखाया जो मैं जानता हूं। शुरुआती फंडिंग भी मैंने ही मुहैया कराई। यह विशेष रूप से चैरिटी के लिए था। मैं इसे लाभ कमाने वाली कंपनी के रूप में शुरू कर सकता था, लेकिन मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। हालांकि मस्क के गवाही देने से पहले, ओपनएआइ और आल्टमैन के वकील विलियम सैविट ने जूरी सदस्यों से कहा कि मस्क "सत्ता की चाबी" चाहते थे और असफल होने के बाद ही उन्होंने मुकदमा दायर किया। 2023 में उन्होंने अपनी खुद की एआइ कंपनी, एक्सएआइ शुरू की। मस्क ओपनएआइ और उसके सबसे बड़े निवेशकों में से एक माइक्रोसाफ्ट से 150 अरब डालर का हर्जाना मांग रहे हैं। वे यह भी चाहते हैं कि ओपनएआइ को फिर गैर-लाभकारी संस्था बना दिया जाए। आल्टमैन को इसके बोर्ड से निकाल दिया जाए। वहीं माइक्रोसाफ्ट के वकील ने कहा कि कंपनी ने कुछ भी गलत नहीं किया है।

एलन मस्क। फाइल

ओपनएआइ ने कहा- "सत्ता की चाबी" चाहते थे मस्क, सफलता नहीं मिली तो किया मुकदमा

पूर्व डीआइजी भुल्लर के ठिकानों से मिले 1.4 करोड़ ईडी ने किए जब्त

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़

- 27 अप्रैल को ईडी ने भुल्लर के सहयोगियों के 11 ठिकानों पर दी थी दबिश
- सीबीआइ ने भी पंजाब के बड़े अधिकारियों के खिलाफ दर्ज की प्राथमिकी

ईडी ने पंजाब पुलिस के पूर्व डीआइजी हरचरण सिंह भुल्लर के खिलाफ मनी लांड्रिंग की जांच में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने भुल्लर के चंडीगढ़ व पंजाब के 11 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जहां से 1.4 करोड़ रुपये की रकम बरामद हुई है। ईडी ने इस राशि को जब्त कर लिया है। ईडी छापेमारी में कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद हुए थे।

ईडी ने गत सोमवार को भुल्लर के खिलाफ प्रिवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत यह जांच की थी। ईडी ने भुल्लर के सेक्टर-40 स्थित घर पर भी दबिश दी थी, जहां से पिछले साल सीबीआइ को साढ़े सात करोड़ रुपये कैश बरामद हुआ था। इसके अलावा भुल्लर के जालंधर, लुधियाना और पटियाला स्थित कई ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। बता दें कि पिछले साल सीबीआइ ने भुल्लर को एक स्क्रैप कारोबारी आकाश बत्ता की शिकायत पर गिरफ्तार किया था। शिकायत पर सीबीआइ ने पहले बिचौलिए कृष्णु और फिर उसकी निशानदेही पर भुल्लर को गिरफ्तार किया। उधर, सीबीआइ के रडार पर पंजाब के आइपीएस व आइएएस अधिकारी भी आए हैं। सीबीआइ ने इन अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है और जल्द ही एफआइआर दर्ज कर उनके नाम सार्वजनिक कर दिए जाएंगे।

Last Day To Join Private Channel.
Closing entry for new members Now

♦ **Indian Newspaper**

1) Times of India
2) The Hindu
3) Business line
4) The Indian Express
5) Economic Times
And more Newspapers

InternationalNewspapers channel [Europian, American, Gulf & Asia]

♦ **Magazine Channel**
National & International
[Genaral & Exam related]

♦ **English Editorials**
[National + InternationalEditorials]

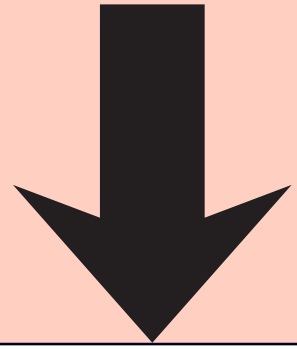

Click here to join

♦ Lifetime validity at just 19 Rupees

I give you my guarantee you, its worth every penny